कर्नाटक की सियासी सूरत

फिर कांग्रेस की फजीहत

कर्नाटक की सियासी सूरत अब साफ नजर आने लगी है। यहां सत्ता की लड़ाई में उलझी कांग्रेस को बिहार की दुर्दशा के बाद कर्नाटक में अपने ही लोगों से कई मोर्चों पर बगावत से दो चार होना पड़ रहा है। कर्नाटक में चल रही खींचतान से कांग्रेस में अंदरखाने चल रही अनुशासनहीनता अब सड़क पर आ चुकी है और इसके चलते संकटकाल से गुजर रही इस प्राचीनतम पार्टी की रही-सही साख भी दांव पर है। कर्नाटक की कहानी कुछ ऐसी है कि यहां पार्टी के दो गुटों में खुलकर सत्ता संघर्ष चल रहा है। यहां सत्ता का खेल अब फर्स्ट और सेकंड हाफ को लेकर रोमांचक दौर में है। शिवकुमार गुट राज्य में सरकार बनाने के समय तय फार्मूले पर अमल की रट लगा रहा है। गुट के बागी तेवर कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी साबित हो सकती है। क्योंकि अगर शिवकुमार गुट की शर्तें नहीं मानी गईं तो तय मानिए यहां पार्टी को दो धड़ों में बंटने से कोई रोक नहीं सकता। राजनीतिक गलियारों में इसको लेकर अब खुलेआम चर्चा भी शुरू हो गई है। शिवकुमार गुट का कहना है कि सरकार गठन के दौरान जो फार्मूला तय हुआ था उसके मुताबिक अब सत्ता की चाभी उनके पास होनी चाहिए। वैसे भी कांग्रेस का बिखराव और टूट का अपना ही इतिहास है। ऐसे में कर्नाटक के हालात पार्टी में फिर किसी बड़े भूचाल के संकेत दे रहे हैं। कांग्रेस में टूट और बगावतों का एक लंबा चौड़ा इतिहास रहा है। कांग्रेस का इतिहास ऐसी ढेरों घटनाओं से भरा हुआ है, जब कांग्रेस की सत्ता को लेकर हुई टूट से किरकिरी हुई है। मोतीलाल नेहरू और सुभाष से लेकर गुलाम नबी आजाद तक, कांग्रेस में विद्रोह और टूटने का इतिहास रहा है। याद रहे मोदी के केंद्र में आने के बाद से कांग्रेस के दुर्दिन शुरू हो गए थे। दो चार मौकों पर कुछ हद तक सियासी जंग में रंग जमाने वाली कांग्रेस को पिछले कई सालों से घोर हताशा और निराशा के दौर से गुजरना पड़ रहा है। आज आलम यह है कि कभी देशव्यापी सियासी साम्राज्य वाली कांग्रेस की हैसियत और मिल्कियत सिमट कर सन्नाटे की जद में आ चुकी है।

इधर, कांग्रेस एक बार फिर कर्नाटक में मुश्किलों से जूझ रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उनके डिप्टी डीके शिवकुमार के बीच लीडरशिप का संकट और खुली दुश्मनी बढ़ रही है। पार्टी हाईकमान जाति के समीकरणों, क्लास अपील और मुकाबले वाले राजनीतिक आधारों में टकराव के बीच वफादारी को बैलेंस करने और फूट को रोकने के लिए संघर्ष कर रहा है। यह कहानी 2023 की विधानसभा जीत से शुरू हुई है, जब पार्टी सिद्धारमैया के नेतृत्व में सत्ता में आई थी, और साथ ही शिवकुमार की अहमियत को ध्यान में रखते हुए पार्टी ने एक सेकंड लाइन भी खींच दी थी। कर्नाटक में सरकार गठन के समय फार्मूला यह तय हुआ था कि सिद्धारमैया सरकार के पांच साल के कार्यकाल के आधे समय के लिए मुख्यमंत्री के तौर पर काम करेंगे, और उसके बाद शिवकुमार बाकी ढाई साल के कार्यकाल के लिए सीएम होंगे। अब, जब सिद्धारमैया नवंबर 2025 में आधा कार्यकाल पार कर चुके हैं, तो शिवकुमार का खेमा फार्मूले पर अमल को लेकर अड़ा हुआ है। इस बीच, दूसरी तरफ़, सत्ता मोह में फांसा सिद्धारमैया खेमा कथित तौर पर पूरे पांच साल का समय पूरा करने पर ज़ोर दे रहा है।

चिंता लोकतंत्र की या वोट बैंक की

एसआईआर का विरोध

ललित गर्ग

भारत का लोकतंत्र आज जिस निर्णायक मोड़ पर खड़ा है, वहां उसकी विश्वसनीयता और मजबूती का सवाल पहले से कहीं अधिक गंभीर हो गया है। चुनावों की पारदर्शिता, मतदाता सूची की शुचिता और राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से मतदाता पहचान की सत्यता को बनाए रखना केवल प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि लोकतंत्र की आत्मा को सुरक्षित रखने का मूल तत्व है। विशेष गहन पुनरीक्षण अर्थात एसआईआर इसी उद्देश्य से प्रारंभ की गई वह अनिवार्य प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से मतदाता सूची में मौजूद संदिग्ध, दोहरे या अवैध प्रविष्टियों की पहचान और सत्यापन किया जा सके। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस कार्य को लोकतंत्र की मजबूती के लिए आवश्यक कदम माना जाना चाहिए, उसे कुछ विपक्षी दल अपने राजनीतिक हितों के चश्मे से देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में जिस प्रकार के उतावले, भावनात्मक और अक्सर तथ्यहीन तर्क प्रस्तुत किए गए, उससे यही प्रतीत होता है कि यह विरोध किसी तर्क या सिद्धांत का नहीं, बल्कि वोट-बैंक की चिंता का परिणाम है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहकर बेतूका राष्ट्र-विरोधही अड़ंगा लगाने वालों को आईना ही दिखाया कि बिहार में तो एक भी व्यक्ति यह शिकायत करने नहीं आया कि उसका नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया है। यह भी उल्लेखनीय है कि बिहार में एसआईआर के समय कुछ खास लोगों के वोट काटे जाने का आरोप उछालने वाले भी ऐसे कथित पीड़ित लोगों के उदाहरण का साक्ष्य नहीं दे सके थे। हालांकि बिहार में एसआईआर पर विपक्षी दलों को मुंह की खानी पड़ी, लेकिन वे बाज नहीं आ रहे हैं और अब 12 राज्यों में जारी एसआईआर की प्रक्रिया को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष खड़े हैं।

यह तब है, जब एसआईआर वाले राज्यों में करीब 65 प्रतिशत फार्म भरे जा चुके हैं। इसका मतलब है कि लोग इस प्रक्रिया में बढ़-चढ़ कर भाग ले रहे हैं। एसआईआर होना इसलिए आवश्यक है, क्योंकि मतदाता सूचियों में भारी त्रुटियां एवं विसंगतियां है, बड़ी संख्या में ऐसे लोगों के नाम दर्ज हैं, जिनकी मृत्यु हो गई है या फिर जो अन्यत्र चले गए हैं। इसके अलावा ऐसे भी लोग हैं, जिनके पास दोहरे

मतदाता पहचान पत्र हैं। चुनाव आयोग एसआईआर के जरिये इन्हीं विसंगतियों को दूर कर रहा है, लेकिन विपक्षी दलों को पता नहीं क्यों यह रास नहीं आ रहा है। वे मतदाता सूचियों में गड़बड़ी की शिकायत भी कर रहे हैं और एसआईआर भी नहीं होने देना चाहते है। लोकतंत्र की जड़ों में सबसे बड़ा विष तब घुलता है जब मतदाता सूची अवैध हस्तक्षेपों, बाहरी घुसपैठियों और राजनीतिक संरक्षण के सहारे खड़ी प्रविष्टियों से दूषित होने लगती है। भारत लंबे समय से विदेशी घुसपैठ की समस्या से जूझ रहा है। राज्यों के बीच असंतुलित प्रवासन, सीमावर्ती क्षेत्रों में बेतरतीब आबादी का फैलाव, राजनीतिक शरण और संरक्षण के नाम पर अवैध बसेरों का निर्माण-ये सब ऐसी वास्तविकताएं हैं जिन्हें अनदेखा करना राष्ट्रहित से खिलवाड़ है।

एसआईआर की प्रक्रिया इसीलिए आरंभ की गई कि मतदाता सूची को अद्यतन, शुद्ध, विश्वसनीय, पारदर्शी और तथ्यों पर आधारित बनाया जा सके। यह प्रक्रिया किसी समुदाय, क्षेत्र या वर्ग के खिलाफ नहीं, बल्कि व्यक्तिगत पहचान के सत्यापन पर आधारित है। यह समान रूप से हर उस मतदाता की जांच करती है जो कानूनन इस प्रक्रिया का हिस्सा है। इसके बावजूद विपक्ष द्वारा इसे अधिकारों पर हमला, राजनीतिक भेदभाव या अविश्वास की राजनीति से जोड़ना केवल दुष्प्रचार एवं भोलेभाले लोगों को गुमराह करना है। यह सवाल इसलिए उठता है कि जब प्रक्रिया सबके लिए समान है, सभी क्षेत्रों पर लागू है और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन में संचालित हो रही है, तो किस आधार पर इसे लोकतंत्र विरोधी कहा जा सकता है? वास्तव में विपक्ष इस प्रश्न का ठोस, तथ्यपूर्ण उत्तर देने में असफल रहा है। यह आशंका निराधार नहीं कि बंगाल जैसे राज्यों में बड़ी संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठिए मतदाता बन बैठे हैं। उनके बांग्लादेश लौटने से इसकी पुष्टि भी होती है। यह ठीक है कि पहचान पत्र के रूप में आधार भी मान्य है, लेकिन उसे भी फर्जी तरीके से बनवाया गया हो सकता है। ऐसे में चुनाव आयोग को दस्तावेजों के सत्यापन का अधिकार मिलना ही चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत विपक्षी तर्कों का विश्लेषण करें, तो उनमें वास्तविक तथ्यों एवं आंकड़ों का अभाव है। भावनात्मक अपीलें, आशंकाओं का जानबूझकर सृजन, प्रशासनिक प्रक्रिया को अविश्वसनीय बताने का प्रयास, और तथ्यों से अधिक आरोपों का शोर-ये सब इस बात की ओर संकेत करते हैं कि उद्देश्य लोकतंत्र की रक्षा नहीं बल्कि अपनी राजनीतिक जमीन को बचाना है। यदि मतदाता सूची वास्तव में त्रुटिरहित है, यदि घुसपैठियों का प्रश्न बिना आधार का है, यदि किसी वर्ग की वैधता पर कोई प्रश्नचिन्ह नहीं, तो फिर सत्यापन से भय क्यों? सत्यापन तो वही व्यक्ति या समूह टालेगा, जो स्वयं को संदेह के घेरे में पाता हो। जो स्वच्छ, वैध और तथ्यपूर्ण हैं उन्हें कभी डर नहीं होता कि जांच उनके लिए समस्या बन जाएगी। इसलिए यह विरोध लोकतंत्र की चिंता नहीं बल्कि लोकतंत्र का उपयोग करके अपने हित साधने की कोशिश प्रतीत होता है। भारत की चुनाव प्रणाली में वर्षों से यह शिकायत उठती रही है कि मतदाता सूची में दोहरी प्रविष्टियां, मृत व्यक्तियों के नाम, काल्पनिक मतदाता और बाहरी लोगों की अवैध प्रविष्टियां बढ़ती जा रही हैं। इनमें से अधिकांश समस्याएं प्रशासनिक लापरवाही का परिणाम हैं, लेकिन एक बड़ा हिस्सा ऐसे राजनीतिक हितों का भी है जो ऐसी प्रविष्टियों को बनाए रखने में खुद को लाभान्वित देखते हैं।

यह तथ्य किसी से छिपा नहीं कि भारत के अनेक राज्यों में स्थानीय राजनीतिक तंत्र विदेशी घुसपैठियों के लिए न केवल छत्रछाया प्रदान करता रहा है, बल्कि उन्हें वोट-आधारित पहचान और सुविधाओं तक पहुंच भी दिलाता रहा है। इन परिस्थितियों में एसआईआर जैसी प्रक्रिया न केवल उचित है, बल्कि अत्यंत आवश्यक है। यह प्रक्रिया जितनी देर से लागू होगी, लोकतंत्र पर उतना ही खतरा बढ़ेगा। एसआईआर के विरोध का एक और पक्ष भी है, और वह है विपक्ष का यह डर कि यदि मतदाता सूची शुद्ध कर दी गई, तो उनका चुनावी गणित प्रभावित होगा। यह राजनीति का वह पक्ष है जिसमें आदर्शवाद के लिए बहुत कम जगह है। राजनीतिक दल अक्सर यह मानकर चलते हैं कि जहां संख्या उनके पक्ष में है, वहां सुधार का कोई हस्तक्षेप उनकी स्थिति को कमजोर कर सकता है। यह प्रवृत्ति लोकतंत्र की आत्मा के विरुद्ध है, क्योंकि लोकतंत्र केवल सत्ता प्राप्त करने का माध्यम नहीं बल्कि नागरिक विश्वास और संवैधानिक मूल्यों का संरक्षक है।

एसआईआर का उद्देश्य किसी को मताधिकार से वंचित करना नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि मताधिकार का उपयोग वही करे जो इसके योग्य है, जो देश का वैध नागरिक है, और जिसका नाम सही तरीके से मतदाता सूची में दर्ज है। भारत का भविष्य उन सुधारों पर निर्भर करता है जो चुनावों को अधिक पारदर्शी और विश्वसनीय बनाएं। जब तक मतदाता सूची शुद्ध नहीं होगी, तब तक चुनाव परिणामों पर संदेह रहेगा और लोकतंत्र की साख कमजोर होती जाएगी। एसआईआर इस दिशा में उठाया गया साहसिक कदम है, जिसे किसी भी प्रकार के राजनीतिक दबाव या भ्रम फैलाने वाले अभियानों से प्रभावित नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में यह प्रक्रिया और अधिक निष्पक्ष और संरक्षित होती है, इसलिए विरोध के ये प्रयास और भी आधारहीन प्रतीत होते हैं।

लोकतंत्र की मरम्मत और मजबूती का यह अवसर खोना राष्ट्रहित के विरुद्ध होगा। जो दल इस प्रक्रिया को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, वे भले ही इसे जनता के हित का मुद्दा बताने का प्रयास करें, परंतु वस्तुतः वे अपने संकीर्ण हितों की रक्षा कर रहे हैं। भारत को ऐसी राजनीति की नहीं, बल्कि ऐसी व्यवस्था की आवश्यकता है जो सत्य को प्राथमिकता दे, सत्ता से अधिक संविधान को महत्व दे, और मतदाता सूची को राजनीतिक हथियार नहीं बल्कि लोकतंत्र की पवित्र सूची माने। एसआईआर की गति और दायरा इसलिए न केवल बनाए रखना चाहिए, बल्कि उसे और भी तेज, निर्णायक और प्रभावी बनाना चाहिए, ताकि भारत का लोकतंत्र अवैध प्रभावों से मुक्त होकर एक मजबूत, पारदर्शी और विश्वसनीय भविष्य की ओर अग्रसर हो सके।

भारत की ताज़ा जीडीपी उछालः 'मृत अर्थव्यवस्था' क्लब को मिला शांत लेकिन करारा जवाब

वैभव डांगे

संस्थापक एवं निर्देशक,
बिल्ड इंडिया फ़ाउंडेशन
(लोकनीति विशेषज्ञ)

हाल के बजटों में सार्वजनिक पूँजीगत व्यय में 30% से अधिक वार्षिक वृद्धि की गई है, और इसके स्पष्ट परिणाम अब ज़मीन पर दिखाई दे रहे हैं

भारत के नवीनतम तिमाही जीडीपी आंकड़े–सरकारी अनुमानों के अनुसार 7% से अधिक–ने एक बार फिर वैश्विक निराशावादियों को विनम्र लेकिन ठोस संदेश दिया हैः भारत की अर्थव्यवस्था की मृत्यु की अफवाहें काफी बढ़ा-चढ़ाकर पेश की गई थीं। जब विकसित अर्थव्यवस्थाएँ मंदी से जूझ रही हैं और उभरते बाज़ार भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं में फँसे हुए हैं, भारत ने न केवल अपनी विकास गति बनाए रखी है बल्कि उसमें थोड़ा 'टर्बोचार्ज' भी जोड़ दिया है।

इस गति के केंद्र में है सरकार का अविरल इंफ्रास्ट्रक्चर फोकस। हाल के बजटों में सार्वजनिक पूँजीगत व्यय में 30% से अधिक वार्षिक वृद्धि की गई है, और इसके स्पष्ट परिणाम अब ज़मीन पर दिखाई दे रहे हैं। राज्यों को जोड़ते नए हाईवे, आधुनिक हवाईअड्डे, रेलवे का रिकॉर्ड आधुनिकीकरण, बंदरगाह विस्तार, और समर्पित माल कॉरिडोर–इन सबने निर्माण, लॉजिस्टिक्स और सहायक क्षेत्रों में नई जान फूँक दी है। वैश्विक सप्लाई चेन आजकल कुछ ऐसे बर्ताव कर रही हैं जैसे मूडी किशोर–अनिश्चित, भावुक और ज़रा-सी बात में टूट जाने वाली। ऐसे माहौल में भारत का घरेलू कैपेक्स चक्र अर्थव्यवस्था के समझदार वयस्क की तरह स्थिरता देता दिख रहा है।

मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने भी इस तिमाही में शानदार प्रदर्शन किया। इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटो और फ़ार्मा जैसे क्षेत्रों के सहारे विनिर्माण सीवीए में मजबूत वृद्धि रही। 2 लाख करोड़ से अधिक की ढछक योजनाओं ने कंपनियों को उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रेरित किया है, और वैश्विक सप्लाई-चेन विविधीकरण भारत के पक्ष में हवा बना रहा है। फैक्टरियों में अब केवल मंत्री-निरीक्षण के दौरान ही चहल-पहल नहीं होती–वास्तव में काम हो रहा है। क्षमता उपयोग 74% से ऊपर पहुँच गया है और कमोडिटी कीमतों में नरमी ने

उद्योगों को राहत दी है।

और फिर आती है जीएसटी सुधारों की भूमिका। कभी जीएसटी को भारत की अर्थव्यवस्था पर ''घातक'' बताने वाले आलोचक अब थोड़ा असहज महसूस कर रहे हैं, क्योंकि हाल में की गई जीएसटी दर-कटौतियों–खासकर आवश्यक और व्यापक उपभोग वाली वस्तुओं पर–ने महँगाई के दबाव के बीच उपभोग को समर्थन दिया है। आज मासिक संग्रह 1.6झ1.7 लाख करोड़ के औसत पर मज़बूती से खड़ा है। चुनिंदा वस्तुओं पर कम दरों ने अनुपालन बढ़ाया, कर-आधार को चौड़ा किया और उपभोक्ता भावना सुधारी। कुल मिलाकरः कम टैक्स स्लैब, ज़्यादा टैक्स संग्रह–एक ऐसा समीकरण जिसे कुछ आलोचक अब भी क्वांटम फिज़िक्सि जितना जटिल मानते हैं।

इस तिमाही के मजबूत जीडीपी आंकड़े वार्षिक वृद्धि दर को भी ऊपर ले जा सकते हैं। उद्योग और सेवा क्षेत्र दोनों गति में हैं और सरकारी कैपेक्स लगातार बढ़ रहा है, जिससे पूरे वर्ष की वृद्धि 6.8% से 7.2% के दायरे में रहने की उम्मीद है। वैश्विक मानकों में यह प्रदर्शन सिर्फ अच्छा नहीं–लगभग 'एथलेटिक' है। अमेरिका की नई टैरिफ नीतियों के बीच यह मज़बूत आर्थिक स्थिति भारत के लिए रणनीतिक रूप से भी फायदेमंद है। मजबूत घरेलू अर्थव्यवस्था भारत को व्यापार वार्ताओं में आत्मविश्वास देती है। मैन्युफैक्चरिंग की मजबूती भारत को वैश्विक सप्लाई चेन का विश्वसनीय विकल्प बनाती है–जो अमेरिका भी चाहता है। और मजबूत टैक्स संग्रह यह सुनिश्चित करता है कि भारत कोई निर्बल पक्ष बनकर टैरिफ में रियायत की भीख माँगता नज़र न आए।

जिन आलोचकों ने भारत की अर्थव्यवस्था की ''शोकसभा'' समय से पहले ही आयोजित कर ली थी, उनके लिए सबसे बड़ा सवाल अब यह है कि ''मरी हुई अर्थव्यवस्था'' आखिर दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में कैसे बनी हुई है? शायद अर्थव्यवस्था ने उनके रिपोर्ट्स पढ़े ही नहीं। शायद वह 'निराशावाद' नाम की भाषा बोलती ही नहीं। कुल मिलाकर, इस तिमाही का जीडीपी सिर्फ वृद्धि नहीं दिखाता–यह आर्थिक परिपक्वता भी दिखाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश ने रीढ़ मजबूत की, विनिर्माण वृद्धि ने शरीर में नई ताकत भरी, जीएसटी सुधारों ने खून का संचार सुधारा और भू-राजनीतिक संतुलन ने पूरी व्यवस्था को फिट रखा।

मासूम चेहरों के पीछे छिपा आतंकवाद, क्रूरता और विध्वंस

डॉ. अंशुल उपाध्याय

आतंकवाद जाति और मज़हब के नाम पर गहरा धब्बा हैं। जो लोग भी इस कृत्य में शामिल होते है उनकी जीवन प्रत्याशा अपने आप ही कम जाती हैं। एक ओर जहां आतंकी नेटवर्क को चलाने के लिए बालकों के दिमाग में ज़हर और नफ़रत भरकर उनको कम उम्र में ही इस काम में धकेल दिया जाता है। वही दूसरी और युवाओं को रूपये और उनके परिवार का पोषण का जूठा वादा करके आतंकी बनने के लिए घसीट लिया जाता है।

अव्वल दर्जे की मनोवैज्ञानिक ट्रेनिंग का नतीजा होते हैं आतंकी : बदलते परिवेश में मनोवैज्ञानिक तरीके से युवक और युवतियों का धीरे-धीरे ब्रेनवाश करके 15 से 16 वर्ष की आयु तक उन्हें एक ट्रेंड और क्रूर आतंकी बना दिया जाता है। फिर ये मासूम एक ऐसे व्यक्ति बन जाते है जिसका खुद का दिमाग चलना ही बंद हो जाता है। और जो भी उन्हें आदेश या टारगेट दिए जाते हैं वे अपना दिमाग बिना चलाए आंख मूंद कर उन टारगेटों को पूरा करने के लिए निकल जाते हैं। फिर चाहे उन्हें सुसाइड बंबर बनकर अपने ही शरीर के चीथड़े ही क्यों ना उडाने पड़े। आतंकवादियों को जरा भी इस बात का इल्म नहीं होता कि उन्होंने उनके इस काम से कितने मासूमो को मारा है। इतनी क्रूरता आखिर किस लिए सिर्फ? सरकार को दिखाने के लिए या जनता को डराने के लिए? या फिर अपने नाकाम मानसून को पूरा करने के लिए? इस पर मैं बस इतना कहूंगी कि ये घटनाएं सिर्फ एक क्रूर मनुष्य के दिमाग़ से जन्म लेती है और विचलित, ब्रेन लॉक मनुष्य के द्वारा अंजाम तक पहुंचाई जाती हैं। जिनका मकसद सिर्फ समाज में आतंकवाद डर को फैलाना होता है।

कश्मीर की आड़ में अपने खूनी मंसूबों को अंजाम देते हैं आतंकी :आतंकवादी ऐसे लक्ष्य विहीन लोग होते है जो, कश्मीर की आड़ में कश्मीर को ही खोखला कर रहे है। कश्मीर में रहने वाला शायद ही कोई ऐसा परिवार होगा जिसने आतंक के इस डरावने चेहरे का सामान न किया हो। पाकिस्तान मैं बैठे कुछ लोग अगर कश्मीर की आजादी की बात कर रहे है तो इसमें कोई भी दो मत नहीं है कि जितना वह आतंक और नरसंहार फैला रहे है उसके बाद उनसे शांति और करुणा की बात करना बेफिजूल ही है। ये न केवल अपने खूनी मंसूबों को ही अंजाम दे रहे हैं। बल्कि हथियारों का निर्माण और उनकी तस्करी करने वालों को भी सीधा फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। हथियारों की तस्करी करने वाले ये लोग तो अमीर देशो में बैठे हुए हैं। और आतंकवादी बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता हैं मिडिल क्लास और निम्न तबगे के लोगों का। जबकि इन आतंकियों के जो हुक्मरान होते हैं वह खुद अपने बच्चों और परिवार को तो लग्जरी लाइफ देते हैं और आम जन को बली चढ़ाने के लिए आतंकवाद की आग में झोंक देते हैं।

दिल्ली में विस्फोट के पीछे का काला सच : वर्तमान घटना क्रम की बात करे तो, दिल्ली लाल किले के पास हुए जोरदार कार धमाके में डॉ. उमर नबी ने करीब 30-40 किलोग्राम विस्फोटक का इस्तेमाल किया था। पुलिस इस बात की आशंका जता रही हैं। कि इस धमाके में अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल हुआ है। सूत्रों के मुताबिक आतंकी ने विस्फोट को और खतरनाक बनाने के लिए अमोनियम नाइट्रेट के अलावा दूसरे पदार्थों का भी इस्तेमाल भी किया होगा। जिसकी जांच अभी चल रही है। इन्हीं केमिकल पदार्थों के द्वारा ही धमाका काफी जोरदार हुआ था और इसकी गूंज काफी दूर तक सुनाई दी थी। मार्च 2020 में गिरफ्तार अलीपुर महिला सुधार गृह में बंद परवीन जो मौलाना मसूद अज़हर की बहन, है और लश्कर-ए -तैयबा की एक हैंडलर भी है से पूछ ताछ में पता चला है कि वह खुद जैश की महिला शाखा की प्रमुख सईदा अज़हर के निर्देशों पर काम करती थी। परवीन कथित तौर पर आतंकवादियों के लिए ऑनलाइन भर्ती का काम संभालती थी और उसकी गतिविधियों पर नज़र रखती थी है। आज आतंकी सिर्फ पहाड़ों में छिपे बंदूकधारी नहीं रह गए है, बल्कि यहां तो यूनिवर्सिटी में पढने वाले डॉक्टर, इंजीनियर और टेक-सेवी नौजवानो को भी आतंकी बनाया जा रहा हैं।

आप की बात

जहां-तहां वाहन न लगाए

जहां-तहां वाहन लगाने से जाम की समस्या उत्पन्न हो जाती है जिसे यातायात प्रभावित होती है जिससे तत्काल सेवा एम्बुलेंस, स्कूल बस, कच्ची खाद्य सामग्री कुछ ज्यादा ही प्रभावित होती है जिससे बड़े पैमाने पर नुकसान होता है क्योंकि यह सभी चीजरु जीवन रेखारु है होता यह है की मोटरसाइकिल, बड़े वाहन जहां कहां सड़क के किनारे खड़े करके कोई सामान खरीदने फिर अपना सामान खरीदने लगते हैं और गाड़ी को बेपरवाह वहीं छोड़ देते है जिससे जाम की समस्या उत्पन्न हो जाती है वही बस और ट्रक लाइन होटल के पास सड़क पर ही खड़ा कर देते हैं जैसे जाम की समस्या उत्पन्न हो जाती है एवं दुर्घटना हो जाती है क्योंकि विपरीत दिशा से आ रही गाड़ी या कोई व्यक्ति को सामने की वस्तु दिखाई नहीं देती है अब तो ठंड का मौसम भी है जिसे कोहरा का प्रकोप बढ़ने की उम्मीद है जिससे सड़क दुर्घटना भी बढ़ जाती है वहीं शहरी की जाम समस्या में बड़े-बड़े दुकान,मॉल जिसमें अधिकांश के पास अपना पार्किंग सुविधा नहीं है जिसके कारण लग्जरी गाड़ी एवं दोपहिया गाड़ी सड़क के किनारे ही लगते हैं ऐसे में प्रशासन को चाहिए कि जिनके पास पार्किंग की सुविधा नहीं है उन पर कार्रवाई करे आमजन को भी अपनी सुरक्षा की ख्याल रखते यातायात के नियम का पालन करके हेलमेट पहनकर गाड़ी चलानी चाहिए। **एस कुमार चंदवारा, लालगंज, वैशाली**

न्यायिक संस्थाओं का कार्य राजनीतिक प्रशासनिक प्रभाव से मुक्त है'

सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश सूर्याकान्त ने कहा कि देश की न्यायिक संस्थाएं राजनीतिक और प्रशासनिक प्रभाव से मुक्त होकर अपना कार्य करती हैं. उन्होंने कानून के विद्यार्थियों को भी सम्बोधित करते हुए कहा कि वर्तमान डिजिटली युग में डीपफेक, गलत सूचना और डिजिटल गिरफ्तारियों के इस दौर में ईमानदारी केवल आदर्श ही नहीं बल्कि अस्तित्व का एक सहारा है और यही वास्तविक सफलता का एक मात्र शॉर्टकट भी है. सही बात है वर्तमान समय में डिजिटली कारस्तानियां बढ़ती जा रही हैं. सोशल मीडिया ने इसे और अधिक बढ़ा दिया है. तब ये सब आज के समय में कानूनी, सामाजिक और राजनीतिक रूप में चुनौतियां बनती जा रही हैं. जिनका सामना समाज, सरकार, विधिवेत्ता और विद्वानजन मिलकर ही ईमानदारीपूर्वक सरलता से कर सकते हैं. ताकि समाज में फ़ैल रही अनावश्यक भ्रांतिया दूर की जा सके और उनसे होने वाले अनावश्यक नुकसान व परेशानियों से लोगों को बचाया जा सके।

शकुंतला महेश नेनावा
57, गिरधर नगर (तिलक नगर के पास), इंदौर (म..प्र.).

मोदी जी का डीजीपी से आग्रह

छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में डीजी आई जी कांफ्रेंस में प्रधानमंत्री मोदीजी की संवेदनशीलता और पीड़ा उभर कर आयी जब उन्होंने कहा कि जिस तरह अपराधी सरेआम घूम रहे है और जिस तरह महिलाओं के साथ दुष्कर्म, अपराध और वे दहेज प्रताड़नाओं की शिकार हो रही है उनकी सुरक्षा के लिए पुलिसिंग को मजबूत बनाना होगा इसके लिए तकनीकी में सुधार करना होगा जिससे स्मार्ट तकनीकी माध्यम से अपराधियों की धर पकड़ हो सके और महिलाओं की सुरक्षा हो सके।

मोदीजी की इस राय के साथ साथ पुलिसिंग में सुधार के साथ साथ देश की न्याय प्रक्रिया में भी सुधार हो जाए तो सोने में सुहागा हो जाए क्योंकि देखने में यही आ रहा है कि कोर्ट से निर्णय होने में देरी होती है तो गवाह पलट जाते है और एविडेंस के साथ छेड़खानी हो जाती है जिससे अपराधी बिना सजा के बरी हो जाता है,जो कि देश की न्यायिक प्रणाली के लिए एक प्रश्न चिन्ह छोड़ जाती है ।

भगवानदास छारिया
सोमानी नगर इंदौर

प्राथमिकताएं पटरी से उतरीं

होम क्रेडिट इंडिया जैसी एनबीएफसी की ताज़ा रिपोर्ट चौंकाती है–घर, पढ़ाई जैसे बड़े सपनों के लिए ऋण लेने वाले तेज़ी से घटते जा रहे हैं, जबकि स्मार्टफ़ोन के लिए ऋण लेने वालों की भीड़ लगातार बढ़ रही है। पिछले एक वर्ष में ही फ़ोन ऋण 9% उछला, जबकि गृह ऋण 3% सिमट गया। मानो हमारी प्राथमिकताएँ उलट गई हों। आज का युवा घर की चाबी की ठोस सुरक्षा से अधिक नयी फ़ोल्डेबल स्क्रीन की चमक को भविष्य मान रहा है। ईएमआई पर 80 हजार का फ़ोन लेना ''समझदारी'' लगता है, पर 25-30 लाख का घर ''बोझ''।

यह सिर्फ आँकड़ा नहीं, हमारी सोच का दर्पण है। हम वह समाज बन गए हैं जो दिखावे की चमक को ही सुख मान बैठा है। घर अब निवेश नहीं, बोझ लगता है; और फ़ोन प्रतिष्ठा तथा त्वरित सुख का साधन बन गया। बैंक भी प्रसन्न–छोटे ऋण जल्दी लौटते हैं, जोखिम नगण्य। सच यही है कि हम भविष्य को गिरवी रखकर वर्तमान की चमक किराए पर ले रहे हैं। जिस दिन यह स्क्रीन मद्धिम पड़ेगी, घर का सपना फिर उतना ही दूर दिखेगा–बिना किसी चाबी के।

प्रो. आरके जैन ''अरिजीत'', बड़वानी (मप्र)

पाठकगण अपने विचार responsemail.hindipioneer@gmail.com पर भेज सकते हैं।

स्मार्टफोन असली है या नकली, ऐसे पहचानें

वेब साइट को ब्लॉक करने के तरीके

कम्प्यूटर पर आप कई साइट्स को ब्लॉक कर सकते है। साइट्स को ब्लॉक करने के कई तरीके होते है। आप ऑपरेटिंग सिस्टम और नेटवर्क राउटर पर साइट्स को ब्लॉक कर सकते है। अगर आपको अपने पर्सनल कम्प्यूटर पर कुछ ऐसी साइट्स है जिनको ब्लॉक करना चाहते है तो इसके लिए कुछ आसान से टिप्स बताये गए है। आप इन टिप्स का इस्तेमाल कर सकते है।

सबसे पहले आप अपने कम्प्यूटर में एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट से सिस्टम में लॉग इन करे। इसके बाद रन पर जाकर क्लिक करे। रन ऑप्शन आपको सर्च में जाकर मिलेगा। रन पर क्लिक करने के बाद आप सीःविंडोजसिस्टम32ड्राइवरईटीसी पर जाये। आपको होस्ट नाम की एक फाइल दिखेगी उस पर जाकर डबल क्लिक करे। जब आप होस्ट फाइल ओपन करेंगे तो आपको इस फाइल में कुछ -127.0.0.0.1 लोकलहोस्ट और -::1 लोकलहोस्ट लिखा हुआ मिलेगा।

यूजर्स को फाइल को एडिट करने के लिए सारे राइट्स देना पड़ता है। प्रापर्टिज बटन पर क्लिक करने के बाद आप सिक्यूरिटी टैब-यूजर अकाउंट-एडिट में जाकर एडिट कर सकते है। साइट्स को ब्लॉक करने के लिए आप फूल कंट्रोल पर क्लिक करे। साइट्स को ब्लॉक करने के लिए आप एड्रेस बार में उन साइट्स का नाम डाले। आपको जिस भी साईट को ब्लॉक करना है उसके साथ 127.0.0.1 भी टाइप करे। ऐसा करने पर आपके कम्प्यूटर में वह साईट ब्लॉक हो जाएगी।

जैसे आपको गूगल की साइट को ब्लॉक करना है तो आप फाइल के आखरी में 127.0.0.1 डब्लूडब्लूडब्लू डॉट गूगल डॉम कॉम को टाइप करे। आप एक बार में एक से ज्यादा साइट को ब्लॉक नही कर सकते है। सबसे आखरी में सेव बटन पर क्लिक कर दे। कम्प्यूटर को बंद करके फिर से स्टार्ट करे आपने जिन भी साइट को ब्लॉक किया है वे सभी साइट ब्लॉक हो जाती है।

अगर आपको किसी बड़े ब्रांड का मोबाइल फोन उसकी असली कीमत से काफी कम में मिल रहा है, तो उसे खरीदने से पहले उसकी कड़ी जांच जरूर कर लें, क्योंकि ऐसे प्रॉडक्ट नकली भी हो सकते हैं। पिछले दिनों ऐसी कई खबरें आईं जिनमें बड़े ब्रांड के पकड़े गए फोन असल में नकली थे। काफी कम कीमत में बड़े ब्रांड के फोन मिलने पर बहुत से लोग धोखा जा जाते हैं। ऐसे में यह जरूरी हो जाता है कि आपको असली और नकली स्मार्टफोन में अंतर पता करने का तरीका मालूम हो। अब हम आपको बताने जा रहे हैं असली और नकली फोन को पहचानने की 10 आसान ट्रिक्स...

स्मार्टफोन की लुक्सः स्मार्टफोन असली है या नकली उसके लिए सबसे पहले फोन की बॉडी की फिनिशिंग और कंपनी के लोगो को ध्यान से देखें। अगर लोगो में या फिनिशिंग में कुछ भी गड़बड़ लगती है तो फोन फेक हो सकता है क्योंकि अक्सर नकली फोन में कंपनी का लोगो ऊपर से लगा दिया जाता है। स्मार्टफोन खरीदते वक्त फोन की पैकिंग गौर से देखें।

कलर और डिजाइनः जब भी कोई मॉडल खरीदने जाते हैं तो उसके बारे में इंटरनेट से जानकारी जरूर लें। जैसे कि कितने रंगों में फोन लॉन्च किया गया है। स्मार्टफोन की जानकारी सिर्फ कंपनी की ऑफिशियल से ही देखें।

फोन का वजनः फोन का वजन ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक करें। क्योंकि नकली फोन में हल्के पार्ट्स लगा दिए जाते हैं। फोन से जुड़ी जानकारी कंपनी की वेबसाइट पर जरूर पढ़ लें।

स्पीड और फीचर्सः ऑरिजिनल फोन की नकली फोन की तुलना में स्पीड कम होती है। नकली फोन में सॉफ्टवेयर की मदद से उसकी हार्डवेयर डीटेल बदल दी जाती है। अगर आपका फोन स्लो चल रहा है तो यह नकली हो सकता है।

कीमतः फोन की असल कीमत के बारे में कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट से पता करें। अगर आपको स्मार्टफोन काफी कम कीमत में मिल रहा है तो उसे तुरंत छोड़ दें। एक बात का और जरूर ध्यान रखें कि आपके पसंदीदा मॉडल की कितनी सेल है और इसके ऑनलाइन प्राइसेज क्या है। कम कीमत के लालच में कभी न आएं।

गारंटी या वारंटीः स्मार्टफोन खरीदते वक्त उसकी गारंटी या वारंटी के बारे में जरूर पता कर लें। इससे जुड़े तमाम पेपर्स को ध्यान से चेक करें। जिस भी रिटेल शोरूम या शॉप से स्मार्टफोन खरीद रहें हैं वहां से सील जरूर लगवाएं। कंपनियां वारंटी के साथ साथ प्रोडक्ट में डिफेक्ट निकलने पर रिप्लेसमेंट का भी ऑप्शन देती हैं, जबकि नकली फोन में ये सुविधा नहीं मिलती।

आईएमईआई नंबरः हर मोबाइल का आईएमईआई नंबर होता है। अपने फोन के इस नंबर को पता लगाने के लिए डायल करके जान सकते है। इसे देखने के लिए अपने फोन के हैंडसेट की बैट्र निकालकर फोन के पैनल पर लगे स्टीकर से इस नंबर का पता कर सकते है। अगर फोन डुअल सिम है तो उसके दो आईएमईआई नंबर होंगे।

वेंडर रेटिंगः ऑनलाइन फोन खरीदते वक्त वेंडर रेटिंग पर जरूर ध्यान दें। अच्छे वेंडर के प्रोडक्ट नकली होने की संभावना कम होती है। इसलिए हमेशा अच्छी रेटिंग वाली ई-कॉमर्स बेवसाइट्स से ही स्मार्टफोन खरीदें।

ऐप्स हेल्पः गूगल प्ले स्टोर पर कई ऐसे एंड्रॉइड ऐप्स हैं जो स्मार्टफोन के हार्डवेयर से जुड़ी तमाम जानकारी आपको देते हैं जैसे कि ऐप्स प्रोसेसर, रैम, ग्राफिक्स के साथ स्मार्टफोन का मॉडल, ब्रांड, स्क्रीन के साथ अन्य हार्डवेयर फीचर्स भी बता देती हैं। इन ऐप्स में सीपीयू-जेड, माई लांचर (एमआईयूआई), सीपीयू एक्स जैसे ऐप्स शामिल भी है।

हार्डवेयर स्विचः जो स्मार्टफोन फेक होते हैं उनके हार्डवेयर बटन अलग होते हैं। इनमें ज्यादा अंतर नहीं होता, लेकिन असली स्मार्टफोन के साथ इसे इस्तेमाल करके महसूस किया जा सकता है। अगर आपको स्मार्टफोन नकली लग रहा है, तो आप इसकी जानकारी कंपनी के ऑफिशियल स्टोर या डीलर को दे सकते हैं।

30 लाख नौकरियां खतरे में, अगले 10 सालों में एआई छीन सकता है काम

एआई के साइड इफेक्ट्स सामने आने शुरू हो गए हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूके के वर्कफोर्स में धीरे-धीरे घुस रहा है, और एक नई स्टडी बताती है कि अगले 10 सालों में लाखों वर्कर्स पर इसका असर पड़ सकता है। नेशनल फाउंडेशन फॉर एजुकेशनल रिसर्च की एक नई रिपोर्ट के मुताबिक, एआई और ऑटोमेशन की मिली-जुली ताकतों की वजह से 2035 तक 3 मिलियन (30 लाख) तक कम-स्किल्ड नौकरियां खत्म हो सकती हैं। हालांकि रिपोर्ट में माना गया है कि इसी समय में पूरी इकॉनमी में लगभग 2.3 मिलियन (23 लाख) नई नौकरियां जुड़ सकती हैं, लेकिन ये फायदे बराबर नहीं बंटेंगे।

किन जॉब्स पर खतरा, किसकी बढ़ेगी डिमांडः सबसे बड़ी चिंता ट्रेड्स, मशीन ऑपरेशन्स और एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स में काम करने वाले लोगों के लिए है, जिन्हें मशीनों या सॉफ्टवेयर से रिप्लेस होने का सबसे ज्यादा खतरा होता है।

दूसरी तरफ, इंजीनियर, साइंटिस्ट और टीचर जैसे बहुत स्किल्ड प्रोफेशनल की डिमांड बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि टेक्नोलॉजी प्रोडक्टिविटी बढ़ाती है और कम से कम शॉर्ट से मीडियम टर्म में वर्कलोड बढ़ाती है। ऑटोमेशन के लिए सबसे ज्यादा कमजोर कामों में एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, फैक्ट्री और मशीन ऑपरेटर, वेयरहाउस वर्कर, कैशियर और प्लंबिंग, रूफिंग और इलेक्ट्रिकल काम जैसे कुछ काम शामिल हैं।

सुरक्षित ऑनलाइन शॉपिंग के लिए फॉलो करें ये टिप्स

इन दिनों लगभग हर ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर ब्लैक फ्राइडे सेल चल रही है। इस दौरान सामान काफी सस्ता हो जाता है और लोग खूब शॉपिंग करते हैं। इसे देखते हुए स्कैमर्स भी एक्टिव हो जाते हैं और वो फर्जी वेबसाइट या दूसरे तरीकों से लोगों को चूना लगाने की कोशिश में रहते हैं। हाल ही में 2,000 से ज्यादा असली लगने वाली फर्जी वेबसाइट्स का पता लगा है, जहां लोगों से सेल का लालच देकर पैसा लूटा जा रहा था। ऐसे में ऑनलाइन शॉपिंग करते समय सतर्क रहने की जरूरत है। आज हम आपको ऑनलाइन शॉपिंग के दौरान सुरक्षित रहने की टिप्स बताने जा रहे हैं।

केवल भरोसेमंद वेबसाइट से करें शॉपिंगः ऑनलाइन शॉपिंग के लिए हमेशा भरोसेमंद वेबसाइट पर ही जाएं। मैसेज में आए लिंक या सोशल मीडिया पर दिखे लुभावने ऑफर के लालच में किसी नई या संदिग्ध लगने वाली वेबसाइट पर शॉपिंग करने से बचें।

यूआरएल में लॉक आइकन को देखेंः अगर आपको किसी वेबसाइट पर डाउट है तो हमेशा उसके यूआरएल को ध्यान से देखें। असली वेबसाइट के यूआरएल में कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होगी और इसमें लॉक आइकन भी नजर आएगा। लॉक आइकन का मतलब है कि साइट पर सिक्योर सॉकेट लेयर एनक्रिप्शन लगा है, जिससे आपका डेटा अनएनक्रिप्टेड साइट से ज्यादा सुरक्षित है।

डेबिट कार्ड से न करें शॉपिंगः ऑनलाइन शॉपिंग के लिए मोबाइल पेमेंट ऐप या क्रेडिट कार्ड का ही यूज करें। कभी भी डेबिट कार्ड से शॉपिंग न करें। अगर डेबिट कार्ड कॉम्प्रोमाइज हो जाता है तो साइबर क्रिमिनल्स को आपके बैंक अकाउंट की सारी डिटेल मिल जाएगी, जिससे आपको भारी नुकसान उठाना पड़ जाएगा।

पब्लिक वाई-फाई पर शॉपिंग न करेंः अगर आप कैफे, रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट पर हैं और पब्लिक वाई-फाई का यूज कर रहे हैं तो ऑनलाइन शॉपिंग करने से बचें। इसकी वजह यह है कि पब्लिक वाई-फाई में सेफ्टी कम होती है और इसके जरिए होने वाली ट्रांजैक्शंस को हैक किया जा सकता है।

क्या व्हाट्सऐप मैसेज डिलीट हो गए हैं, ऐसे वापस पाएं

कई बार व्हाट्सऐप मैसेज डिलीट होने पर हमें काफी अजीब-सा लगता है कि करीबी दोस्तों के साथ किया चैट हमेशा के लिए खत्म हो गया। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, तो एक खुशखबरी है। आप व्हाट्सऐप पर डिलीट हो चुके मैसेज को वापस पा सकते हैं। व्हाट्सऐप का इस्तेमाल कर रहे ज्यादातर यूजर्स शायद यह बात नहीं जानते होंगे कि हर सुबह 4 बजे व्हाट्सऐप आपके मोबाइल फोन के सारे मैसेज को रिस्टोर करता है। ऐसे में अगर आपसे कोई मैसेज धोखे से डिलीट हो गया है, तो आप इसको आसानी से वापस पा सकते हैं।

ये है प्रोसेस....

1. व्हाट्सऐप को अपने मोबाइल में से अनइंसटॉल कर दें।

2. इसके बाद स्टोर से व्हाट्सऐप को दोबारा अपने मोबाइल में इंसटॉल करें।

3. इंस्टॉलेशन के प्रोसेस के समय यह एप्लीकेशन आपसे पुराने मैसेज रिस्टोर करने को पूछेगा।

4. अगर आप यस पर क्लिक करते हैं तो पिछले रिस्टोर तक आपके सारे मैसेज वापस आ जाएंगे।

आप अपने व्हाट्सऐप को कंप्यूटर या मोबाइल में इस्तेमाल कर सकते हैं...

इसके लिए आपको गूगल क्रोम में व्हाट्सऐप वेब टाइप करना होगा। इसके बाद आप अपने मोबाइल में आ रहे अनुदेश को फॉलो करके व्हाट्सऐप को कम्प्यूटर या लैपटॉप से जोड़ सकते हैं। इसके बाद सभी मैसेज नोटिफिकेशन आपको आपके कम्प्यूटर या लैपटॉप पर मिलने लगेंगे। ध्यान रहे आपको फोन उस वक्त इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहिए। यह सुविधा अभी आईफोन यूजर्स के लिए नहीं है।

एन्ड्रॉयड और विडोज फोन के यूजर्स अपनी व्हाट्सऐप चैट, फोटो और वीडियो को पासवर्ड से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। प्ले स्टोर से व्हाट्सऐप लॉकर एप इंस्टॉल करके आप पिन डालकर अपने व्हाट्सऐप अकाउंट को लॉक कर सकते हैं। आईफोन यूजर्स इस सुविधा को जेलब्रेकिंग के माध्यम से इस्तेमाल कर सकते हैं।

फेसबुक प्रोफाइल से अनचाहे लोगों को कैसे रखें दूर

क्या आपको पता है कि फेसबुक पर हमारी गतिविधियों के बारे में कोई भी बेहद आसानी से जान सकता है? हमारी निजी जानकारियां इंटरनेट पर जासूसी करने वालों से सुरक्षित नहीं है। खासतौर से फेसबुक पर (थ्बमइववा) हम जो जानकारियां सबमिट करते हैं, उन्हें चोरी-छिपे बेहद आसानी से देखा जा सकता है। यदि आपको फेसबुक की कुछ ट्रिक्स मालूम हों, तो आप इस खतरे को टाल भी सकते हैं।

फेसबुक प्रोफाइल बनाते वक्त हम सबमिट करते हैं अपनी बहुत-सी जानकारियांः-

आमतौर पर लोग फेसबुक जैसी सोशल नेटवर्किंग साइट का इस्तेमाल फोटो शेयरिंग, लाइक, कॉमेंट, वीडियो अपलोड करने के लिए करते है। आप अन्य लोगों द्वारा शेयर की गई फोटो, वीडियो पर लाईक या कमेंट भी करते हैं। इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करने से पहले आप प्रोफाइल बनाते हैं और इस प्रक्रिया के दौरान ही आप अपनी तमाम जानकारियां भी उपलब्ध कराते हैं। हालांकि हमें यह मालूम नहीं होता कि हमारी इन्हीं जानकारियों को कोई अनजान व्यक्ति चुरा भी सकता है।

कैसे होती है फेसबुक प्रोफाइल की जासूसी

आपकी दी गई जानकारी के मुताबिक कंपनियां आपको ऐड भेजती हैं और अगर आपने मोबाइल नंबर शेयर किया हुआ है तो आपको फोन भी करती हैं। इसी तरह कई कंपनियां आपकी जानकारी हासिल कर आपको अपने प्रोडक्ट के लिए ऐड भेजती है। यदि आप जागरूक हों, तो ऐसी ऐड ट्रैकिंग से बाहर निकलना बेहद आसान है। आगे हम आपको ऐसे 8 स्टेप्स बताएंगे, जिनके जरिए आप अपनी फेसबुक प्रोफाइल की जासूसी करने वाले लोगों और कंपनियों को ब्लॉक कर सकते हैं....

1. अपने फेसबुक प्रोफाइल पेज के बाईं ओर ऊपर की तरफ डाउन ऐरो पर क्लिक कर सेटिंग्स पर क्लिक करें।

2. सेटिंग्स में दाईं ओर लिस्ट में एडस पर क्लिक करें

3. इसके बाद इसमें देखें कि आप किस-किस के साथ अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहें हैं।

4. यहां पर नो वन पर क्लिक करके सेव चेंजेज पर क्लिक कर दें।

5. अब अपने होम पेज पर वापस आएं और दाईं ओर ऊपर की तरफ लॉक मेनू पर जाएं।

6. यहां पर बाईं ओर एप्स पर क्लिक करें।

7. यहां दिख रहे एप्स आपको फॉलो कर रहे हैं।

8. एक-एक पर जाकर आप उसे एडिट या डीलीट कर सकते हैं।

पेनड्राइव से डिलीट डाटा ऐसे पाएं वापस

डाटा स्टोरेज के लिए हम बहुत सी ड्राइव्स का प्रयोग करते हैं, इनमें से एक है पेन ड्राइव यह साइज और वजन में हल्की होती है, इसलिए आप आसानी से कैरी कर सकते हैं। आपके डाटा को सेव रखने के लिए यह एक अन्य बेहतर स्टोरेज है, लेकिन क्या हो अगर गलती से आपका डाटा पेनड्राइव से डिलीट हो जाएं? फिक्र करने की जरूरत नहीं! अगर ऐसा हो जाता है तो भी आप अपने डिलीटेड डाटा को आसानी से रिकवर कर सकते हैं। बस इसके लिए ये तरीके फॉलो करने होंगे।

- सबसे पहले आप गूगल प्ले स्टोर से फ्री में उपलब्ध पैनडोरा रिकवरी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करें।
- अब पैनडोरा रिकवरी सॉफ्टवेयर को ओपन करें।
- ओपन सॉफ्टवेयर पर नीचे की ओर नेक्स्ट विकल्प दिखेगा, इस पर क्लिक करें, जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो अगला विकल्प टर्म एंड कंडीशन उपलब्ध हो जाएगा, फिर इस ऑप्शन के नीचे भी आपको नेक्स्ट का विकल्प मिलेगा, उस पर क्लिक करें।
- इसके बाद अपने कंप्यूटर या लैपटॉप के जिस फोल्डर में पैनडोरा एप को इंस्टॉल करना चाहते हैं, उस फोल्डर को सेलेक्ट करें।
- जैसे ही जब सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाए तो उसे ओपन करें, इस दौरान ध्यान रखें कि आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में बैकअप लेने वाली या रिकवर करने वाली पेन ड्राइव जरूर लगी हो। इसके बाद सिस्टम में दिख रहे पैनडोरा रिकवरीसॉफ्टवेयर के आइकन पर क्लिक करें। अब जैसे ही आपको पेनड्राइव का ऑप्शन दिखाई दें, तो उस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपको पेनड्राइव से डिलीट हुई फाइल्स दिखने लगेंगी।
- उपलब्ध डिलीट फाइल्स पर राइट क्लिक करें। अब ऑप्शन्स में से रिकवरी विकल्प का चयन करें। इन फाइल्स को जिस फोल्डर या जगह में सेव करना चाहते हैं, उनका चयन करें।
- बस अब आप चंद सेकंड में देखेंगे कि डिलीट डाटा सेव हो गया है।

सीएमवाईके प्रिंटेक के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक डॉ. देवेन्द्र सिंह द्वारा पंजीकृत कार्यालय 201-205, 208-210 द्वितीय मंजिल, प्रताप भवन, 5 बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002, दूरभाष : 01169342500, 46035729 से प्रकाशित तथा द इंडियन एक्सप्रेस प्रा.लि. ए-8, सेक्टर 7, जिला गौतमबुद्धनगर- उत्तर प्रदेश, नोएडा 201, 301, फोन नंबर 0120-2470700 से मुद्रित। प्रधान संपादक डॉ. देवेन्द्र सिंह।
पाठकों को सुझाव दिया जाता है कि इस अखबार के किसी भी विज्ञापन पर प्रतिक्रिया करने से पहले पूरी तरह उसके बारे में दिए गए दावों, शर्तों और तथ्यों की जांच कर लें। पायनियर ग्रुप के मुद्रक, प्रकाशक, सम्पादक या उसका कोई भी कर्मचारी विज्ञापनदाता द्वारा उनके किसी उत्पाद तथा सेवा हेतु किए गए किसी दावे की सच्चाई का आश्वासन या उत्तरदायित्व नहीं लेता है। ऐसे विज्ञापनों के बाद किसी आर्थिक क्षति के लिए वे जिम्मेदार भी नहीं हैं।

एजुकेशन & कॅरिअर

सपनों को सच करने की चाह हो, तो पढ़ाई में कभी थकावट नहीं होती।

अमर उजाला Job Alert

Real-time job alerts
amarujala.com/jobs

बीएसएससी ने जारी किया विज्ञापन

सहायक अनुदेशक, निम्नवर्गीय लिपिक व अन्य पद रिक्त

23175 पद

आवेदन की अंतिम तिथि : 15 दिसंबर, 2025
योग्यताएं : बारहवीं व समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण
यहां आवेदन करें : bssc.bihar.gov.in

बीडीएल में रोजगार के अवसर ■ 156 पद

अप्रेंटिसशिप के लिए करें आवेदन
आवेदन की अंतिम तिथि 08 दिसंबर, 2025
आयु-सीमा
न्यूनतम 14 वर्ष व अधिकतम 30 वर्ष निर्धारित
यहां आवेदन करें
bdl-india.in

सेल में रोजगार की संभावनाएं ■ 124 पद

मैनेजमेंट ट्रेनी के पदों पर रिक्तियां
आवेदन की अंतिम तिथि 05 दिसंबर, 2025
वेतनमान
रुपये 50,000 से लेकर रुपये 1,60,000 प्रतिमाह
यहां आवेदन करें
sail.co.in

यूकेएमएसएसबी में रिक्तियां ■ 587 पद

नर्सिंग अधिकारी के पदों पर रोजगार के अवसर
आवेदन की अंतिम तिथि : 17 दिसंबर, 2025
वेतनमान : रुपये 44,900 से लेकर रुपये 1,42,400 तक निर्धारित
यहां आवेदन करें : ukmssb.org

बिहार विधान परिषद में संभावनाएं ■ 64 पद

डाटा एंट्री ऑपरेटर, स्टेनोग्राफर व अन्य पदों पर करें अप्लाई
आवेदन की अंतिम तिथि 19 दिसंबर, 2025
योग्यताएं
बारहवीं, स्नातक व अन्य निर्धारित पात्रताएं
यहां आवेदन करें
vidhanparishad.bihar.gov.in

एसटीपीआई में निकली भर्ती ■ 24 पद

असिस्टेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर व अन्य पद खाली
आवेदन की अंतिम तिथि 12 जनवरी, 2026
योग्यताएं
बीटेक, एमटेक व अन्य निर्धारित पात्रताएं
यहां आवेदन करें
stpi.in

योग्य उम्मीदवार करें आवेदन ...

- कालिंदी कॉलेज, दिल्ली : सीनियर पर्सनल असिस्टेंट का पद खाली।
  आवेदन की अंतिम तिथि : 14 दिसंबर, 2025
- kalindicollege.in
- बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड : प्रोग्राम मैनेजर का पद रिक्त।
  आवेदन की अंतिम तिथि : 31 दिसंबर, 2025
- forestonline.bihar.gov.in

अपनी प्रतिक्रियाओं और सुझावों के लिए हमें udaan@amarujala.com पर ई-मेल करें।

हमेशा चौकन्ना रहने के खतरे

अत्यधिक सतर्क रहना तनाव को और गहरा कर देता है। बेहतर है कि काम के बीच छोटे-छोटे विराम लेते रहें

तन्वी गौतम
हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू

Harvard Business Review

जब काम का दबाव लगातार बना रहता है, तो दिमाग कभी-कभी हमेशा चौकन्ना रहने की अवस्था में पहुंच जाता है। यही अति-सतर्कता (हाइपरविजिलेंस) कहलाती है, जिसमें ध्यान सीमित हो जाता है और छोटी-छोटी बातें भी अनावश्यक रूप से खतरनाक महसूस होने लगती हैं। इसका असर काम पर ही नहीं, मन की शांति पर भी पड़ता है। ऐसे में लगातार होने वाले तनाव को संभालना बहुत जरूरी है। छोटी कसरतें, समय पर ब्रेक, सीमाएं तय करना और काम को टुकड़ों में बांटना उस मानसिक गार्ड को थोड़ा आराम देते हैं। धीरे-धीरे संतुलन बनने लगता है और आप कामयाबी को बिना अपने मन पर बोझ डाले हासिल कर पाते हैं।

■ अति सतर्कता को समझें

अति-सतर्कता या हाइपरविजिलेंस के कारण लोग खुद को थका हुआ और चिंतित महसूस करने लगते हैं। यह स्थिति व्यक्तिगत असुरक्षा, पिछले अनुभवों या उच्च दबाव वाले कार्य वातावरण के कारण उत्पन्न हो सकती है। इसके अलावा, मानसिक या मनोवैज्ञानिक स्थितियों के साथ-साथ सामाजिक और पारिवारिक कारकों से भी जुड़ी हो सकती है। इसका प्रभाव व्यक्ति की निर्णय लेने की क्षमता और प्रदर्शन पर भी गंभीर रूप से पड़ता है।

■ उत्साह को बनाए रखें

अपने जुनून को बरकरार रखते हुए समस्याओं को हल करने के लिए आपको कठिन परिस्थितियों में खुद को संभालने के तरीकों को जानना होगा। स्वयं को उन कार्यों में व्यस्त रखें, जिनसे आपको तार्किक और योजनात्मक बनने के साथ-साथ भावनात्मक रूप से जुड़ने में मदद मिले। कार्यस्थल पर अपने उत्साह को बनाए रखने के लिए अपने सहकर्मियों या प्रबंधक से उत्साहपूर्ण सवाल पूछें। ऐसे सवाल आपके जीवन में टकराव के बजाय जिज्ञासा पैदा करने में मदद कर सकते हैं।

■ रचनात्मक उपाय अपनाएं

यदि काम में सहजता महसूस नहीं हो रही है, तो जरूरी है कि आप स्थिति सुधारने के लिए नए तरीकों की तलाश करें। अपने विचारों पर ध्यान दें, क्योंकि वही भावनाएं बनाते हैं। नकारात्मक सोच से निकलने के लिए रचनात्मक उपाय अपनाएं और सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करें। यही आपको आगे बढ़ने की ताकत देगा।

■ खुशहाल वातावरण है जरूरी

अति सतर्कता से बचने के लिए अपने आस-पास के वातावरण को उद्देश्यपूर्ण तरीके से डिजाइन करना जरूरी है। आपका व्यवहार आपकी चिंता को कम कर सकता है। अपने दिमाग को तरोताजा और कठिन परिस्थितियों में खुद को शांत रखने के लिए आप धीरे-धीरे लंबी सांस लें। इसके अलावा, दैनिक दिनचर्या में व्यायाम, ताजी घास पर नंगे पैर चलना या गाने गुनगुनाने जैसी सरल प्रक्रियाओं को शामिल करें।

खुद को परखें

1. ब्नेई मेनाशे समुदाय मुख्यतः किन राज्यों में पाया जाता है?
   (a) मिजोरम और मणिपुर
   (b) गुजरात और राजस्थान
   (c) नगालैंड और त्रिपुरा
   (d) बिहार और झारखंड
2. हाल ही में, उत्तराखंड के किस राष्ट्रीय उद्यान में हॉफिंच पक्षी देखा गया है?
   (a) नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान
   (b) राजाजी राष्ट्रीय उद्यान
   (c) जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान
   (d) फूलों की घाटी
3. उद्यमी-इन-रेजिडेंस कार्यक्रम किस सरकारी विभाग द्वारा कार्यान्वित किया जाता है?
   (a) उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग
   (b) जैव प्रौद्योगिकी विभाग
   (c) वाणिज्य विभाग
   (d) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग

उत्तर-1.a, 2.c, 3.d

एमआईटी की पहल

नाइट साइंस जर्नलिज्म फेलोशिप प्रोग्राम 2026-27

मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (एमआईटी) ने नाइट साइंस जर्नलिज्म फेलोशिप प्रोग्राम 2026-27 के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। यह फेलोशिप विश्वभर के उत्कृष्ट विज्ञान पत्रकारों को विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पत्रकारिता की कला का गहन अन्वेषण करने में सहायता प्रदान करने वाला एक प्रतिष्ठित अवसर है।

आवेदन के लिए आवश्यक है कि आवेदक चाहे स्टाफ पत्रकार हों या स्वतंत्र विज्ञान, स्वास्थ्य, प्रौद्योगिकी या पर्यावरण संबंधी रिपोर्टिंग में कम से कम तीन वर्षों का निरंतर अनुभव रखते हों। चयनित उम्मीदवारों को 85,000 अमेरिकी डॉलर तक का स्टाइपेंड, यात्रा एवं आवास भत्ता व अन्य लाभ प्राप्त होंगे। उम्मीदवार आधिकारिक लिंक tinyurl.com/ytjy98bp पर जाकर 09 जनवरी, 2026 तक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

आवेदन आमंत्रित

लाइका स्ट्रीट फोटो कॉन्टेस्ट में हों शामिल

लाइका स्ट्रीट फोटो कॉन्टेस्ट के लिए स्ट्रीट फोटोग्राफी के उत्साही फोटोग्राफरों से आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। यह कॉन्टेस्ट उन फोटोग्राफरों को मंच प्रदान करता है, जो दुनिया के सामने अपना अनूठा दृष्टिकोण प्रस्तुत करना चाहते हैं।

■ मानदंड

प्रत्येक प्रतिभागी अधिकतम पांच फोटो जमा कर सकता है। जमा किए जाने वाले प्रत्येक फोटो का आकार एक एमबी से अधिक नहीं होना चाहिए। साथ ही, फोटो की अधिकतम लंबाई 2000 पिक्सेल निर्धारित की गई है। इसके अलावा, फाइल के नाम में न तो रिक्त स्थान होना चाहिए और न ही कोई विशेष चिन्ह।

■ पुरस्कार

कॉन्टेस्ट के विजेताओं के सर्वश्रेष्ठ फोटो को लाइका स्टोर वारसॉ और लाइका गैलरी वियना की प्रदर्शनी में प्रदर्शित किया जाएगा। इसके अलावा, विजेताओं को ग्रैंड प्रिक्स पुरस्कार के रूप में लाइका क्यू3 43 कैमरा प्रदान किया जाएगा।

■ यहां आवेदन करें

इच्छुक प्रतिभागी आधिकारिक लिंक leicastreetphoto.pl पर जाकर 09 जनवरी, 2026 तक ऑनलाइन माध्यम से हिस्सा ले सकते हैं।

एग्जाम अलर्ट — हफ्ते की परीक्षाएं

आईबीपीएस आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट प्रारंभिक परीक्षा

- **परीक्षा की तिथि :** 06 व 07 दिसंबर, 2025
- इस परीक्षा में तर्कशक्ति और संख्यात्मक क्षमता से 40-40 अंकों के 40-40 प्रश्न पूछे जाएंगे। तर्कशक्ति के प्रश्नों को हल करने के लिए 25 मिनट और संख्यात्मक क्षमता के प्रश्नों को हल करने के लिए 20 मिनट का समय निर्धारित है।
- **यहां से प्रवेश-पत्र डाउनलोड करें** ibps.in

यूपीपीएससी एलटी ग्रेड सहायक शिक्षक परीक्षा

- **परीक्षा की तिथि :** 06 व 07 दिसंबर, 2025
- इस परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के सामान्य अध्ययन से 30 प्रश्न व प्रत्येक वैकल्पिक विषय से 120 प्रश्न प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न दो अंकों के होंगे। परीक्षा की अवधि दो घंटे निर्धारित है।
- **यहां से प्रवेश-पत्र डाउनलोड करें** tinyurl.com/28ubpy28

सामान्य ज्ञान

ग्रे सील

- **क्या है**
  यह फोसिडी परिवार की एक बड़ी सील है।
- **चर्चा में क्यों**
  हाल ही में, शोधकर्ताओं ने पाया कि सील के दूध में 332 तरह की खास शर्कराएं पाई जाती हैं।
- **दिन में अधिक सक्रिय**
  नर ग्रे सील लगभग 10 फीट तक होते हैं, जबकि मादाएं छोटी होती हैं। बच्चे सफेद फर के साथ जन्म लेते हैं, जो उन्हें गर्म रखता है। ये दिन में सक्रिय रहते हैं और रात में आराम करते हैं।
- **इनका आवास**
  इसे अटलांटिक सील और हॉर्सहेड सील भी कहा जाता है। ज्यादातर समय तटीय पानी और बर्फीली जगहों पर दिखाई देती है।
- **मांसाहारी जीव**
  यह कभी-कभी 'बॉटलिंग' करती है, यानी पानी में सीधी खड़ी रहती हैं और सिर्फ सिर बाहर दिखता है। ये मांस खाती हैं, खासकर मछली। इनकी उम्र आमतौर पर 25 से 35 साल होती है।

रोशनी यहां है

इस बार : नीरज तिवारी
क्यों : नौकरी में अस्वीकृति से लेकर फलते-फूलते व्यवसाय तक का सफर

नीरज तिवारी को अपने शुरुआती दिनों में कई बार नौकरी के लिए रिजेक्शन झेलना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार मानने के बजाय अपनी अलग राह बनाई। उन्होंने एचसीसीआईएल कंपनी की स्थापना की, जो प्रौद्योगिकी और प्रबंधन सेवाओं के क्षेत्र में काम करती है। इस कंपनी का टर्नओवर करोड़ों में है...

कई बार झेला रिजेक्शन, सिर्फ 50 हजार की पूंजी से शुरू किया काम, अब दे रहे हैं लोगों को रोजगार

जीवन में हर व्यक्ति कभी न कभी ऐसे मोड़ पर खड़ा होता है, जब चुनौतियां और असफलताएं उसे आगे बढ़ने से रोकने लगती हैं। नीरज तिवारी भी ऐसे ही समय में थे, जब लगातार नौकरी में रिजेक्शन उनके सामने बाधाओं की तरह उभर रहे थे। हर असफल प्रयास उनके अंदर की उम्मीद को धीरे-धीरे कम करता जा रहा था। फिर भी, उन्होंने हार नहीं मानी। 2012 में, केवल 50 हजार रुपये की सीमित पूंजी और ढेरों शंकाओं के साथ, नीरज ने हाईटेक ह्यूमन कैपिटल (इंडिया) लिमिटेड (एचएचसीआईएल) कंपनी की नींव रखी। यह कोई बड़ी शुरुआत नहीं थी, बस एक छोटा कदम था। धीरे-धीरे इस छोटे से प्रयास ने आकार लेना शुरू किया।

एचएचसीआईएल ने सुरक्षा गार्ड और सुविधा प्रबंधन सेवाओं के क्षेत्र में भरोसे का नाम कमाया। समय के साथ कंपनी का विस्तार हुआ और चार हजार से अधिक कर्मचारी इस सपने का हिस्सा बने। कंपनी अब 12 राज्यों में अपनी सेवाएं दे रही है और लगातार विकसित हो रही है। आज, नीरज तिवारी की दूरदर्शिता के चलते एचएचसीआईएल ने लगभग एक हजार करोड़ रुपये का वार्षिक राजस्व हासिल कर लिया है।

अपना रास्ता खुद बनाया

नीरज तिवारी ने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद जब नौकरी की तलाश शुरू की, तो उन्हें लगातार असफलताओं और निराशाओं का सामना करना पड़ा। हर जगह से उन्हें वही परिचित जवाब मिलता 'हम आपको कॉल करेंगे।' इस बार-बार मिलने वाली हताशा ने उन्हें गहराई से सोचने पर मजबूर किया। उन्होंने महसूस किया कि यदि वे सिर्फ अवसरों का इंतजार करते रहे, तो सफलता का रास्ता कठिन और अनिश्चित रहेगा। इसी सोच ने उन्हें यह निर्णय लेने के लिए प्रेरित किया कि अब वे अपने अवसर स्वयं बनाएंगे, दूसरों के भरोसे नहीं रहेंगे। इसी नवीन दृष्टिकोण के साथ उन्होंने एचएचसीआईएल की नींव रखी। नीरज का उद्देश्य केवल अपने कॅरिअर को आगे बढ़ाना नहीं था, बल्कि वह यह भी चाहते थे कि उनके प्रयासों से दूसरों के लिए नए रोजगार और विकास के अवसर भी खुलें। यही सोच और उद्देश्य आगे चलकर कंपनी की पहचान बन गया।

सिर्फ दस कर्मचारियों से की शुरुआत

एचएचसीआईएल की शुरुआत एक छोटे से उद्यम के रूप में हुई थी, लेकिन समय के साथ यह एक मजबूत और तेजी से बढ़ती कंपनी बन गई। यह यात्रा बिल्कुल आसान नहीं थी। शुरुआत में कंपनी के पास केवल दस कर्मचारी और 50 हजार रुपये की सीमित पूंजी थी। सुरक्षा और सुविधा प्रबंधन के क्षेत्र में पहले से कई बड़ी कंपनियां मौजूद थीं, इसलिए नए ग्राहकों का भरोसा जीतना नीरज तिवारी के लिए एक बड़ी चुनौती थी। मगर लगातार मेहनत, बेहतर सेवाएं और गुणवत्तापूर्ण काम ने धीरे-धीरे उनको अपनी अलग पहचान दिला दी।

छह साल के भीतर पहुंचे शिखर पर

एचएचसीआईएल में नीरज ने शुरुआत से ही क्वालिटी पर जोर दिया। उन्होंने कम लागत में बेहतर सेवाएं प्रदान करनी शुरू कीं और धीरे-धीरे मार्केट में अपनी मजबूत पहचान बना ली। समय के साथ उन्होंने कंपनी का दायरा भी लगातार बढ़ाया। आज कंपनी कई तरह की सेवाएं देती है, जिनमें सिक्योरिटी सॉल्यूशन, कैश सॉल्यूशन, फैसिलिटी मैनेजमेंट, कॉरपोरेट रिस्क मैनेजमेंट और बैकग्राउंड वेरिफिकेशन जैसी प्रमुख सेवाएं शामिल हैं। वर्तमान में एचएचसीआईएल की मौजूदगी 12 राज्यों में है और कंपनी में लगभग चार हजार से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं। कंपनी अब आईपीओ लाने की तैयारी कर रही है। एक रिपोर्ट के अनुसार, एचएचसीआईएल का लक्ष्य वित्त वर्ष 2027-28 तक शेयर बाजार में सूचीबद्ध होना है। कंपनी की उत्कृष्टता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि लॉन्च के केवल छह साल बाद ही एचएचसीआईएल को गुजरात की सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा एजेंसी का दर्जा मिल गया था। इसी तरह, 2017 में नीरज तिवारी को 'यंग अचीवर्स ऑफ द ईयर' सम्मान से नवाजा गया।

युवाओं को सीख

- जब शुरुआत छोटी हो, तो मेहनत ही वह रास्ता है, जिसे दुनिया पहचानती है।
- बड़ी कंपनियां संसाधनों से बनती हैं, पर पहचान विश्वास और गुणवत्ता से ही मिलती है।
- चुनौतियां रास्ता रोकती नहीं, बल्कि यह परखती हैं कि आपका इरादा कितना सच्चा है।
- सीमित पूंजी आपके कदम रोक सकती है, लेकिन दृष्टि और साहस आपकी दिशा तय करते हैं।
- सफलता वहीं जन्म लेती है, जहां डर खत्म होता है और पहले कदम की हिम्मत शुरू होती है।

आज का दिन

1 दिसंबर, 1988

प्रथम विश्व एड्स दिवस मनाया गया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस दिवस की शुरुआत राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय संगठनों और स्थानीय सरकारों एवं व्यक्तियों के बीच सूचना के आदान-प्रदान के लिए की थी।

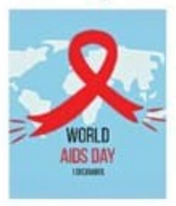

- **1761 :** मैरी तुसाद का जन्म फ्रांस में हुआ था।
- **1825 :** रूसी सम्राट अलेक्जेंडर प्रथम का दक्षिणी रूस में निधन हुआ था।
- **1963 :** नागालैंड भारत का 16वां राज्य बना था।
- **2000 :** विसेंट फॉक्स को मेक्सिको के राष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई थी।

व्रत त्योहार

आज : मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष एकादशी।
कल : अखंडा द्वादशी, हेमंत ऋतु, सूर्य दक्षिणायने, दक्षिण गोले। **राहुकाल :** दिन में 15.00 से 16.30 तक

कल का पंचांग

विक्रमी संवत 2082, 11 मार्गशीर्ष मास शक 1947, मार्गशीर्ष मास 17 प्रविष्टे, 10 जमादिउस्सानी हिजरी 1447, मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष द्वादशी 15.57 तक उपरांत त्रयोदशी, अश्विनी नक्षत्र 20.51 तक उपरांत भरणी नक्षत्र, वरियान योग 21.07 तक उपरांत परिध योग, बालव करण 15.57 तक उपरांत कौलव करण, चंद्रमा मेष राशि में दिन-रात।

- सूर्योदय : 07.01
- सूर्यास्त : 17.20

(भारतीय मानक समयानुसार)

amarujala.com/astrology

राशिफल

■ पं. विनोद त्यागी

मेष : स्वास्थ्य का ध्यान रखें। स्वजनों से विवाद संभव है। नौकरी में मन नहीं लगेगा। व्यय पर नियंत्रण रखें।

वृष : जनहित कार्यों में रुचि रहेगी। नई योजना में पूंजी निवेश संभव है। व्यावसायिक धन लाभ से उत्साह बढ़ेगा।

मिथुन : नौकरी में नया पदभार संभव है। बॉन्ड, बीमा से अर्थ प्राप्ति हो सकती है। व्यवसाय में धन लाभ होगा।

कर्क : प्रभावी के सहयोग से अटका कार्य बनेगा। नौकरी में स्थिति अनुकूल रहेगी। व्यवसाय में सुधार आएगा।

सिंह : स्वजनों से निराशा होगी। नौकरी में परेशानी आ सकती है। व्यवसाय में लाभ होगा। वाहन से परेशानी होगी।

कन्या : स्वबुद्धि विवेक से अटका कार्य बनेगा। विवाह प्रस्ताव आ सकता है। नौकरी में पद प्रतिष्ठा बढ़ सकती है।

तुला : राजनीतिक क्षेत्र में सम्मान बढ़ेगा। नौकरी में वर्चस्व बना रहेगा। व्यवसाय में उत्तम लाभ होगा।

वृश्चिक : मानसिक द्वंद्व बना रहेगा। नौकरी में सहकर्मियों से वाद-विवाद संभव है। संतान पक्ष से कुछ चिंता रहेगी।

धनु : पूर्व नियोजित कार्य में व्यस्त रहेंगे। नौकरी में श्रम की अधिकता रहेगी। कार्य विशेष में निराशा होगी।

मकर : प्रभावी व्यक्ति से परिचय होगा। नौकरी में जवाबदेही बढ़ सकती है। व्यवसाय में लाभ होगा।

कुंभ : सकारात्मक सोच बनाए रखें। प्रयासों में सफलता मिलेगी। नौकरी में मान-सम्मान बना रहेगा।

मीन : भाग्य सहायक रहेगा। संतान पक्ष से शुभ समाचार मिल सकता है। नौकरी में नूतन पद भार संभव है।

जन्मदिन

उदित नारायण, गायक

इस वर्ष परिश्रम करने एवं धैर्य रखने से योजनाएं साकार होंगी। विश्वासपात्र से धोखा हो सकता है। आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। मकान या प्लॉट का क्रय हो सकता है। अविवाहितों के विवाह प्रस्ताव आएंगे। संतान सुख में वृद्धि होगी। रोजगारपरक परीक्षाओं में सफलता मिलेगी। आरोग्य सुख उत्तम रहेगा।

सुडोकू

7		3	9					
	1			3				
			8			2		9
	2	1		5				
	7		2		3		5	
				4		8	7	
3		4			5			
				2			8	
					1	4		5

सुडोकू 81 वर्गों का ग्रिड है, जो 9 वर्गों के ब्लॉक में बंटा हुआ होता है। कुछ वर्गों के अंक लिखे हैं और खाली वर्गों में 1 से लेकर 9 तक के अंक लिखने होते हैं। कोई नंबर 1 पंक्ति, कॉलम या 9 वर्ग वाले छोटे ब्लॉक में दोबारा नहीं आ सकता है।

उत्तर

7	8	3	9	6	2	5	1	4
2	1	9	5	3	4	7	6	8
5	4	6	8	1	7	2	3	9
6	2	1	7	5	8	9	4	3
4	7	8	2	9	3	6	5	1
9	3	5	1	4	6	8	7	2
3	9	4	6	8	5	1	2	7
1	5	7	4	2	9	3	8	6
8	6	2	3	7	1	4	9	5

डेली हेल्थ कैप्सूल

औषधीय गुणों से भरपूर है सहजन की चाय

सहजन की फली की तरह ही इसकी पत्तियों में भी कई औषधीय गुण होते हैं, जो सेहत के लिए लाभकारी होते हैं।

आयुर्वेद में सहजन के पत्तों का उपयोग कई बीमारियों के इलाज में किया जाता है। इन पत्तों में विटामिन ए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी, प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन और मैग्नीशियम होता है। प्रतिदिन इन पत्तियों की चाय का सेवन करने से इम्युनिटी बेहतर होती है। इससे बीमारियों का जोखिम कम होता है। इसकी चाय में भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सिडेंट होते हैं, जो शरीर में सूजन के कारण होने वाली समस्याओं को दूर करने में मदद करते हैं। इसका नियमित सेवन करने से दिल की बीमारियों का जोखिम कम होता है। सहजन की पत्तियों में एंटी डायबिटीक गुण होते हैं, जो ब्लड शुगर को कम करने में मददगार होते हैं। डायबिटीज रोगी चिकित्सक की सलाह लेकर इस चाय का सेवन कर सकते हैं। सहजन की पत्तियों में मौजूद गुण विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में सहायता करते हैं। इससे किडनी फंक्शन को बेहतर बनाने में मदद मिलती है। कई अध्ययनों के अनुसार, सहजन की पत्तियों और छाल के अर्क में विभिन्न प्रकार की कैंसर कोशिकाओं को बढ़ने से रोकने और उन्हें खत्म करने की क्षमता होती है।

क्या कहते हैं विशेषज्ञ

सहजन की चाय का अत्यधिक सेवन करने से ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर बहुत कम हो सकता है। हाइपरयूरिकेमिया, गठिया, यूरिक एसिड और ऑटोइम्यून के रोगी विशेष सावधानी बरतें।

-डॉ. नवदीप जोशी
प्राकृतिक चिकित्सक

ताकि सनद रहे

फिक्स्ड इनकम का तोहफा

RBI का फ्लोटिंग रेट बॉन्ड

पारंपरिक बैंक जमा योजनाओं और छोटी बचत योजनाओं की तुलना में बेहतर व सुरक्षित विकल्प की तलाश कर रहे निवेशकों के बीच भारतीय रिजर्व बैंक के फ्लोटिंग रेट बॉन्ड तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं।

शेयर बाजार में लंबी चलने वाली अस्थिरता और सोने-चांदी की कीमतों में तेज उठापटक के बाद निवेशकों के बीच फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट लोकप्रिय हो रहे हैं।

रूढ़िवादी निवेशकों के बीच बैंक और छोटी बचत योजनाओं से अलग, लेकिन सुरक्षित और सुनिश्चित रिटर्न के लिए आरबीआई फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स की मांग काफी बढ़ गई है। भारत सरकार की गारंटी और भारतीय रिजर्व बैंक की निगरानी वाले ये बॉन्ड सुरक्षा, स्थिर आय और बाजार के साथ बदलते रिटर्न की तलाश करने वाले निवेशकों के लिए एक पसंदीदा विकल्प बन गए हैं।

फ्लोटिंग रेट बॉन्ड क्या हैं?

फ्लोटिंग रेट बॉन्ड में ब्याज दर को समय-समय पर एक बेंचमार्क दर के आधार पर संशोधित किया जाता है। बैंक एफडी या अन्य बचत योजना (जहां ब्याज दर पूरी अवधि के लिए अपरिवर्तित रहती है) के विपरीत फ्लोटिंग रेट बॉन्ड की ब्याज दर अपनी अवधि के दौरान बाजार की ब्याज दरों के अनुरूप बदलती रहती है।

- फ्लोटिंग रेट बॉन्ड की ब्याज दर राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (NSC) की मौजूदा दर से 0.35% अधिक होती है। जब एनएससी की दरें बढ़ती हैं, तो आरबीआई फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड की दरें भी बढ़ जाती हैं, और जब एनएससी की दरें गिरती हैं, तो इसकी दर में भी कमी आती है।

क्या है ब्याज दर?

NSC की ब्याज दर 7.7 फीसदी है, इसलिए फ्लोटिंग रेट बॉन्ड की मौजूदा ब्याज दर 8.05% है, जो इसे डेट विकल्पों के बीच एक बेहतरीन विकल्प बनाती है। इस बॉन्ड पर हर छह माह में ब्याज का भुगतान किया जाता है। आरबीआई ब्याज दर में किसी भी बदलाव की सूचना देता है।

बैंक जमा और बॉन्ड यील्ड से बेहतर

आरबीआई फ्लोटिंग रेट बॉन्ड की मौजूदा कूपन दर एसबीआई की 05-10 साल वाली फिक्स्ड डिपॉजिट दर (6.05%) से अधिक है। इतना ही नहीं, यह 10 वर्षीय बेंचमार्क सरकारी प्रतिभूति (G-Sec) की यील्ड (6.52%) से भी करीब 1.5 फीसदी ज्यादा है।

लॉक-इन अवधि

आरबीआई फ्लोटिंग रेट सेविंग्स बॉन्ड्स की लॉक-इन अवधि निवेशक की आयु के आधार पर भिन्न-भिन्न होती है। यह 18 से 60 वर्ष से कम के निवेशकों के लिए 07 साल, 60 से 70 वर्ष के लिए 06 साल, 70 से 80 वर्ष के लिए 05 साल और 80 वर्ष से अधिक के लिए 04 साल है।

न्यूनतम निवेश

आरबीआई फ्लोटिंग रेट बॉन्ड में न्यूनतम निवेश की राशि 1,000 रुपये है। इसमें निवेश की कोई अधिकतम सीमा नहीं है। बॉन्ड पर मिलने वाली ब्याज आय कर योग्य होती है। ब्याज आय को आपकी कुल वार्षिक आय में जोड़ा जाएगा और टैक्स स्लैब के मुताबिक कर लगाया जाएगा। इन बॉन्ड्स को आरबीआई रिटेल डायरेक्ट वेबसाइट से खरीदा जा सकता है।

तारीख पता है?

कंपनियों के तिमाही नतीजे/घोषणा

- 02 दिसंबर : Siemens Ltd.
- 03 दिसंबर : Tata Capital, LG Electronics, HDB Financial, Ather Energy, Tata Motors, NSDL, JSW Cement, Vikram Solar, Aditya Birla Lifestyle.
- 03 दिसंबर : S&P मैन्यूफैक्चरिंग एंड सर्विस पीएमआई
- 05 दिसंबर : आरबीआई एमपीसी बैठक के नतीजों की घोषणा

■ डिस्क्लेमर : अपना पैसा में छपे विचार, राय और निवेश संबंधी सुझाव अलग-अलग विशेषज्ञों, ब्रोकर फर्मों या रिसर्च संस्थानों के हैं। इनसे अखबार या उसके प्रबंधन की सहमति जरूरी नहीं है। कृपया किसी भी तरह का निवेश फैसला लेने से पहले अपने पंजीकृत वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें। इस जानकारी के आधार पर होने वाले किसी भी नुकसान की जिम्मेदारी अखबार या उसके प्रबंधन की नहीं होगी।

म्यूचुअल फंड मतलब मनी फ्रेंड। यह निवेश हर परिस्थिति में मदद करता है। मेडिकल इमरजेंसी हो, लास्ट मिनट ट्रैवल प्लान हो या फिर कैश-फ्लो की समस्या, म्यूचुअल फंड हर मुश्किल सवाल का हल है। अचानक सामने आई वित्तीय जरूरत के लिए म्यूचुअल फंड फटाफट कर्ज दिलाने में आपकी मदद करते हैं, वह भी निवेश और बचत को बिना कोई नुकसान पहुंचाए...

म्यूचुअल फंड : कर्ज फटाफट...बिना झंझट

क्रिसिल के मुताबिक, म्यूचुअल फंड के बदले लोन का पोर्टफोलियो करीब 38,000 करोड़ रुपये है, जबकि पूरा उद्योग 80 लाख करोड़ रुपये का निवेश संभालता है।

सारांश ने पत्नी को सरप्राइज देने के लिए टूर पैकेज बुक किया। चार दिन के पैकेज पर एक लाख रुपये खर्च होंगे। टिकट और होटल बुकिंग तो क्रेडिट कार्ड से हो गया, लेकिन अब अन्य खर्चों के लिए कैश चाहिए।

म्यूचुअल फंड है न। तुरंत म्यूचुअल फंड अकाउंट खोला और रिडीम के लिए रिक्वेस्ट डाल दी। मैसेज आया। नकदी के लिए म्यूचुअल फंड यूनिट बेचने की जरूरत नहीं। यूनिट को गिरवी रखकर लोन लिया जा सकता है। सारांश का काम हो गया, म्यूचुअल फंड निवेश भी बच गया और बिना किसी कागजी प्रक्रिया के फटाफट पैसा भी मिल गया।

म्यूचुअल फंड्स में निवेश करने वालों में से 48 फीसदी की उम्र 18 से 30 वर्ष के बीच है। ऐसे निवेशकों के पास क्रेडिट स्कोर नहीं होता, जिससे पर्सनल लोन मिलना मुश्किल होता है। इसकी ब्याज दर भी ऊंची होती है। इंस्टैंट मिलने वाले डिजिटल लोन में हैरेसमेंट और कर्ज जाल में फंसने का डर होता है। म्यूचुअल फंड यूनिट रिडीम करने पर लंबी अवधि के निवेश लक्ष्य प्रभावित हो सकते हैं। इसलिए युवा निवेशकों के बीच फटाफट लोन के लिए लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स (LAMF) लोकप्रिय साधन बन रहा है।

■ क्यों बढ़ रहा LAMF का आकर्षण?

तुरंत अप्रूवल: डिजिटल KYC, ई-मैंडेट और यूनिट प्लेजिंग से मिनटों में लोन स्वीकृत।

कम ब्याज दर: सुरक्षित ऋण है, इसलिए पर्सनल लोन की तुलना में ब्याज दर काफी कम।

उपयोग किए गए ऋण पर ब्याज: एक तरह से ओवरड्राफ्ट सुविधा। उतनी ही राशि पर ब्याज, जितनी क्रेडिट लिमिट में से उपयोग होती है।

निवेश अप्रभावित: यूनिट्स बेची नहीं जाती हैं। केवल गिरवी रखी जाती हैं। इस दौरान गिरवी रखी यूनिट्स बाजार के प्रदर्शन के अनुसार बढ़ती रहती हैं।

■ कहां हो रहा है उपयोग?

- आपातकालीन चिकित्सा खर्च
- शॉर्ट-टर्म बिजनेस वर्किंग कैपिटल
- घर की मरम्मत
- स्कूल या कॉलेज फीस
- नए निवेश के लिए मार्जिन
- यात्रा और लाइफस्टाइल खर्च
- अस्थायी कैश-फ्लो संकट
- ऊंचे ब्याज वाले क्रेडिट कार्ड के रोलओवर से बचना

■ कैसे तय होती है ऋण सीमा

लोन-टू-वैल्यू (LTV) अनुपात यह निर्धारित करता है कि गिरवी रखे गए म्यूचुअल फंड यूनिट्स के वर्तमान बाजार मूल्य (NAV) के मुकाबले आप अधिकतम कितनी ऋण राशि प्राप्त कर सकते हैं। यह डेट और इक्विटी फंड्स के लिए अलग-अलग होता है।

- NAV प्रतिदिन बदलता है, इसलिए स्वीकृत ऋण सीमा भी दैनिक आधार पर फंड के वर्तमान मूल्य के अनुसार समायोजित होती रहती है।
- यदि NAV बढ़ता है, तो स्वीकृत कर्ज भी बढ़ता है, और NAV गिरता है, तो स्वीकृत कर्ज भी कम होता है।

■ मार्जिन कॉल का जोखिम

मार्जिन कॉल एक ऑटोमैटिक सुरक्षा ट्रिगर है। यह तब लागू होता है, जब आपके गिरवी रखे गए यूनिट्स का बाजार मूल्य काफी गिर जाता है, जिससे मौजूदा उपयोग की गई ऋण राशि एलटीवी सीमा से अधिक हो जाती है।

■ मार्जिन कॉल के बाद क्या करना होगा?

निवेशक के पास दो तरीके हैं:

- नकद जमा करना
- अधिक यूनिट्स गिरवी रखना।

मार्जिन कॉल कब और कैसे ट्रिगर होता है?

मार्जिन कॉल तब होता है, जब उपयोग की गई कर्ज राशि घटी हुई नई अधिकतम मंजूर ऋण सीमा (NAV में गिरावट के कारण) के करीब पहुंच जाती है। उदाहरण-इक्विटी फंड

स्थिति	गिरवी यूनिट्स का मूल्य	अधिकतम मंजूर ऋण (50%LTV)	उपयोग किया गया ऋण	मार्जिन स्थिति
प्रारंभिक	2,00,000	1,00,000	70,000	सुरक्षित (30,000 बफर)
बाजार गिरावट	1,20,000	60,000	70,000	मार्जिन कॉल

बाजार में गिरावट के दौरान, आपका उपयोग किया गया ऋण 70,000 रुपये अब नई अधिकतम ऋण सीमा 60,000 रुपये से अधिक हो गया है। आपके पास 10,000 रुपये की कमी है।

म्यूचुअल फंड पर लोन किफायती समाधान

रोहित पटेरिया
को-फाउंडर और सीईओ, लार्क फिनसर्व

इस सुविधा से मध्यम वर्ग के साथ-साथ पहली बार उधार लेने वालों के लिए फटाफट कर्ज लेना आसान हो गया है। यह निवेशकों को आपात स्थितियों का सामना करने, अल्पकालिक आवश्यकताओं को पूरा करने और अवसरों को भुनाने में सक्षम बनाता है। ये सब उनके दीर्घकालिक निवेश लक्ष्य से समझौता किए बिना होता है

मार्जिन कॉल की अनदेखी पड़ेगी भारी

अगर आप निर्धारित समय के भीतर मार्जिन कॉल को पूरा करने में विफल रहते हैं, तो ऋणदाता के पास बकाया ऋण राशि की वसूली के लिए गिरवी रखे गए म्यूचुअल फंड यूनिट्स की आवश्यक संख्या को बेचने और शेष ऋण को मंजूर एलटीवी अनुपात के भीतर लाने का कानूनी अधिकार होता है।

जोखिम से बचने के लिए उठाएं ये कदम

- अपनी LAMF सीमा का उपयोग 100% तक न करें। एनएवी में गिरावट व संभावित मार्जिन कॉल से बचाव के लिए हमेशा अप्रयुक्त सीमा बनाए रखें।
- **नकद तैयार रखें:** किसी भी मार्जिन कॉल को पूरा करने के लिए हमेशा एक छोटा कैश रिजर्व तैयार रखें।

समझ-बूझ

ग्रेच्युटी के लिए अब लंबा इंतजार नहीं

कंपनी की ओर से अपने कर्मचारियों को लंबे समय तक काम करने के बदले दिए जाने वाले उपहार, ग्रेच्युटी के लिए अब आपको पांच साल तक इंतजार नहीं करना होगा। सरकार ने नए श्रम कानून में ग्रेच्युटी से जुड़े नियमों में कुछ बदलाव किए हैं, जिन्हें जानना आपके लिए जरूरी है।

- आमतौर पर किसी कंपनी में लगातार पांच साल की नौकरी पूरी होने पर ही ग्रेच्युटी का लाभ मिलता था, लेकिन अब फिक्स्ड टर्म कर्मचारियों को सर्विस के एक साल पूरा होने पर ही इसका लाभ मिलेगा।
- कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को ग्रेच्युटी सहित सोशल सिक्योरिटी कवरेज उपलब्ध कराने का दायित्व प्रमुख नियोक्ता का होगा। इन्हें भी एक साल की सेवा के बाद ग्रेच्युटी का लाभ मिलेगा।
- एक्सपोर्ट सेक्टर के फिक्स्ड-टर्म कर्मियों को भी ग्रेच्युटी के दायरे में लाया जाएगा।

कैसे होती है ग्रेच्युटी की गणना

ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 की धारा 4(2) के तहत, ग्रेच्युटी की गणना का फॉर्मूला है: अंतिम बेसिक सैलरी (डीए सहित)x15/26xपूरे किए गए सेवा के वर्ष।

खबरों के आर-पार

अब 1600 रोकेगा स्पैम और फ्रॉड कॉल

बैंक, बीमा कंपनी, म्यूचुअल फंड या सेबी के नाम पर आने वाले फर्जी कॉल पर जल्द रोक लगने वाली है। ट्राई ने BFSI सेक्टर से कहा है कि वह ग्राहकों से बात करने के लिए केवल 1600 सीरीज से शुरू होने वाले फोन नंबरों का ही इस्तेमाल करें। इससे बैंक, बीमा या सेबी के नाम पर होने वाली ठगी को रोका जा सकेगा।

क्या होगा फायदा:

- बैंक और बीमा कंपनियों के कॉल 1600 सीरीज के नंबर से आएंगे।
- ग्राहक असली और फर्जी कॉल को आसानी से पहचान सकेंगे।
- स्पैम कॉल से फ्रॉड में आएगी कमी।
- मार्च 2026 से लागू होगी नई व्यवस्था।

पूछताछ

सर्विस के 5 साल पूरे होने से पहले मैं EPF अकाउंट से पैसा निकालता हूं, तो क्या मुझे टैक्स देना होगा?

अगर कोई सदस्य सेवा के 05 साल पूरे होने से पहले EPF खाते से पैसा निकालता है, तब EPFO नियोक्ता और कर्मचारी, दोनों के योगदान और उस पर मिले ब्याज पर 10 फीसदी की दर (यदि पैन दिया है) से टीडीएस काटेगा। अगर पैन उपलब्ध नहीं है, तब टीडीएस की दर 34.608 फीसदी होगी।

इन मामलों में टीडीएस नहीं काटा जाएगा:

■ एक पीएफ खाते से दूसरे पीएफ खाते में ट्रांसफर ■ सदस्य के खराब स्वास्थ्य के कारण सेवा की समाप्ति ■ नियोक्ता द्वारा कारोबार बंद करना ■ परियोजना का काम पूरा होना ■ सदस्य के नियंत्रण से बाहर अन्य कारण ■ 05 साल की अवधि के बाद निकासी ■ सेवा की अवधि 05 साल से कम, लेकिन पीएफ राशि 50,000 रुपये से कम ■ पैन के साथ फॉर्म 15G/15H देने पर 05 साल की अवधि से पहले 50,000 रुपये या इससे ज्यादा निकासी।

फंड की फिटनेस

फंड की मुख्य बातें

- फंड हाउस : एक्सिस म्यूचुअल फंड
- कुल AMU: 3.40 लाख करोड़
- फंड मैनेजर : देवांग शाह, आदित्य पगारिया
- यूनिट अलॉटमेंट: 11 दिसंबर, 2025
- एग्जिट लोड : 12 माह से पहले रिडेम्पशन पर 1 फीसदी

अस्थिर बाजार फिर भी बनेगा मुनाफा

नए और सतर्क निवेशकों के बीच बढ़ा मल्टी एसेट फंड का क्रेज

Axis Multi Asset Active FoF NFO

बाजार में अस्थिरता के दौरान निवेशक सहज और बहुआयामी समाधान खोजते हैं और यही कारण है कि इस समय मल्टी एसेट फंड्स का आकर्षण तेजी से बढ़ रहा है। ये फंड इक्विटी, डेट या कमोडिटी (गोल्ड, सिल्वर) में से किसी एक को चुनने की जटिलता के बिना, तुरंत डायवर्सिफिकेशन की क्षमता प्रदान करते हैं।

एक्सिस म्यूचुअल फंड ने निवेशकों की इस बढ़ती मांग को देखते हुए एक नया फंड लॉन्च किया है। इसका नाम है- एक्सिस मल्टी एसेट एक्टिव फंड ऑफ फंड्स। इसका लक्ष्य इक्विटी, फिक्स्ड इनकम, कमोडिटी को एक गतिशील रूप से प्रबंधित पोर्टफोलियो के भीतर संयोजित करना है।

यह NFO 21 नवंबर से 05 दिसंबर तक खुला है। इसमें न्यूनतम 100 रुपये से निवेश किया जा सकता है। मल्टी एसेट फंड अस्थिरता को कम करके और कई परिसंपत्ति वर्गों में जोखिम को फैलाकर नए निवेशकों को आराम की भावना प्रदान करते हैं।

■ फंड का प्रदर्शन

मल्टी एसेट फंड्स में लगातार निवेशकों का रुझान बढ़ रहा है। हर महीने इनमें 5-6 हजार करोड़ रुपये का निवेश आ रहा है। निवेशक अब यह समझ गए हैं कि किसी एक स्टॉक या थीम में पैसा नहीं बनता है। एसेट अलोकेशन ही लंबी अवधि में पूंजी बनाने की कुंजी है।

फंड मैनेजमेंट टीम बाजार की चाल पर नजर रखती है और एसेट्स का मिश्रण बदलती रहती है, ताकि आपका निवेश न सिर्फ सुरक्षित रहे, बल्कि हर स्थिति में संभावनाओं का पूरा फायदा उठा सकें।

■ क्या कहते हैं एक्सपर्ट

Complete Circle के सीनियर पार्टनर विकास पुरी कहते हैं कि जिन निवेशकों के पोर्टफोलियो में मल्टी एसेट अलोकेशन फंड नहीं हैं, और वे ऐसे फंड चाहते हैं, तो एक्सिस म्यूचुअल फंड का यह एनएफओ उनके लिए अच्छा विकल्प हो सकता है।

जाइए, लीजिए बैंक से अपना भूला हुआ पैसा

दस्तावेज या जागरूकता के अभाव में परिवार बैंकों में बेकार पड़ी राशि तक नहीं पहुंच पा रहे

पीके गुप्ता
रिटायर्ड मैनेजर
आईडीबीआई बैंक

क्या आपको पता है, बैंकों में 67,000 करोड़ रुपये (जून, 2025 तक) लावारिस (अनक्लेम्ड) पड़े हैं? यह आपकी और हमारी ही वह भूली हुई संपत्ति है, जिसे कई सारे लोग बैंक खातों में रखकर भूल गए, या उनके नॉमिनी इन खातों से अनजान हैं। कई मामलों में पुराने बैंक खाते के विवरण, दस्तावेज या जागरूकता के अभाव में, परिवार इस बेकार पड़ी राशि तक नहीं पहुंच पा रहे हैं।

अगर आपका या आपके परिवार के किसी सदस्य का कोई बैंक खाता 10 वर्षों से अधिक समय से निष्क्रिय है, तो उसमें मौजूद धनराशि को अब आप आसानी से वापस पा सकते हैं और इसमें आपकी मदद करेगा खुद आरबीआई।

■ अनक्लेम्ड राशि बढ़ने की क्या है वजह?

अनक्लेम्ड राशि बढ़ने की सबसे बड़ी वजह है भारतीय परिवारों में वित्तीय संवाद न होना। कई बार लोग निवेश तो कर लेते हैं, लेकिन परिवार को इसकी जानकारी नहीं देते। जानकारी के अभाव में मुख्य निवेशकर्ता की अनुपस्थिति में संपत्ति वर्षों तक बिना दावे के पड़ी रहती है।

■ अब RBI चला रहा है विशेष अभियान

आरबीआई 31 दिसंबर तक विशेष सहायता कैंप का आयोजन कर रहा है। इनका उद्देश्य भूले हुए पैसों को सही हाथों में पहुंचाना, क्लेम प्रक्रिया को आसान बनाना और पूरे देश में वित्तीय साक्षरता को मजबूत करना है। कैंप में ग्राहकों को क्लेम फॉर्म भरने में मदद, दस्तावेजों की जांच, नॉमिनी प्रक्रिया, फॉलो-अप सपोर्ट जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिससे भूला हुआ पैसा प्राप्त करना और आसान हो जाएगा।

■ निष्क्रिय खाता क्या होता है?

अगर किसी बचत या करंट अकाउंट में दो साल से कोई लेन-देन (जमा, निकासी, ट्रांसफर या KYC अपडेट) नहीं हुआ है, तो वह निष्क्रिय खाता कहलाता है। ऐसे खातों में पैसे तो सुरक्षित रहते हैं, लेकिन कई सेवाएं बंद हो जाती हैं। ग्राहक के KYC अपडेट करने या ट्रांजेक्शन करने पर यह फिर से सक्रिय हो जाते हैं। अगर खाता 10 साल तक भी इस्तेमाल नहीं होता, तो उस खाते में मौजूद रकम (ब्याज सहित) RBI के जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता (DEA) फंड में ट्रांसफर कर दी जाती है।

■ क्या आप अपने पैसे वापस पा सकते हैं?

हां, बैंक ग्राहक या उनके कानूनी वारिस किसी भी समय अपने पैसे वापस ले सकते हैं। इसके लिए कोई समयसीमा नहीं है।

पैसे वापस पाने के लिए आपको करना होगा:

- अपने बैंक की किसी भी शाखा में जाएं।
- KYC दस्तावेज (आधार, पासपोर्ट, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस आदि) प्रस्तुत करें।
- क्लेम फॉर्म भरें और नॉमिनी या कानूनी उत्तराधिकारी दस्तावेज जमा करें।
- अपना पैसा (ब्याज सहित, यदि लागू हो) वापस पाएं।

इसके अलावा, RBI अक्तूबर से दिसंबर के बीच विशेष कैंप भी आयोजित कर रहा है, जहां आप प्रक्रिया की जानकारी लेकर अपनी रकम का दावा कर सकते हैं।

■ अनक्लेम्ड राशि लौटाने पर RBI दे रहा है बैंकों को इनाम

बैंकों में अनक्लेम्ड रकम को कम करने के लिए RBI ने 01 अक्तूबर, 2025 से एक नई योजना शुरू की है। इस योजना के तहत जो बैंक ग्राहकों को उनके निष्क्रिय खातों का पैसा वापस दिलाएंगे, उन्हें इनाम मिलेगा। अगर खाता 04 साल तक निष्क्रिय है, तो बैंक को 5% या 5,000 रुपये (जो कम हो) मिलेगा। अगर खाता 10 साल तक निष्क्रिय है, तो बैंक को 7.5% या 25,000 रुपये (जो कम हो) मिलेंगे।

बैंक हर तिमाही में इनसेंटिव के लिए क्लेम दाखिल कर सकते हैं। RBI इन दावों की जांच के बाद 30 दिनों के भीतर भुगतान करेगा। यह योजना बैंकों को प्रेरित करने के लिए है, ताकि वे पुराने निष्क्रिय खातों का निपटान करें और भविष्य में नई अनक्लेम्ड रकम बनने से रोक सकें।

जानना जरूरी है

कैसे चेक करें कि आपके पास कोई अनक्लेम्ड पैसा है या नहीं?

आरबीआई ने अनक्लेम्ड जमा खोजने के लिए एक खास पोर्टल UDGAM बनाया है। इसकी मदद से बैंकों में जमा लावारिस राशि के बारे में पता लगाया जा सकता है:

- सबसे पहले udgam.rbi.org.in पर जाएं।
- मोबाइल नंबर या आधार OTP से रजिस्टर करें।
- नाम, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर, अन्य विवरण भरें।
- पोर्टल विभिन्न बैंकों में आपके नाम से जुड़े निष्क्रिय खाते, एफडी, आरडी, सेविंग/करंट अकाउंट या अन्य जमाओं को दिखाता है।
- अगर आपके नाम से कोई अनक्लेम्ड पैसा है, तो बैंक का नाम और UDRN दिखेगा।

फिलहाल 30 बैंक इस पोर्टल से जुड़े हुए हैं, जिनमें SBI, HDFC, ICICI जैसे प्रमुख बैंक शामिल हैं। ये बैंक करीब 90 फीसदी अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स को कवर करते हैं।

आपके बाद परिवार न हो परेशान इसलिए उठाएं ये कदम

- सभी बैंक खातों, PPF, म्यूचुअल फंड और बीमा पॉलिसियों की एक लिखित सूची बनाएं।
- इस सूची के बारे में परिवार के सभी प्रमुख सदस्यों को बताएं।
- नॉमिनी की जानकारी हर खाते में अपडेट रखें।
- बैंक या निवेश में बदलाव होने पर परिवार के प्रमुख सदस्यों को इसकी जानकारी दें।
- दस्तावेज को सुरक्षित और आसानी से उपलब्ध स्थान पर रखें।
- समय-समय पर खातों में गतिविधियां करते रहें, ताकि वे निष्क्रिय न हों।

इंफोग्राफिक्स

डेट फंड्स पर फिर आया निवेशकों का दिल

सितंबर में भारी निकासी के बाद अक्तूबर में डेट म्यूचुअल फंड्स में 1.6 लाख करोड़ रुपये का बड़ा निवेश आया। सितंबर में 1.02 लाख करोड़ रुपये की निकासी हुई थी। एंफी के मुताबिक, सितंबर में डेट म्यूचुअल फंड्स का कुल AUM 17.8 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर अक्तूबर में 19.51 लाख करोड़ रुपये हो गया।

डेट म्यूचुअल फंड में बढ़ा निवेश

फंड	अक्तूबर 2025	सितंबर 2025
ओवरनाइट फंड	24,050.57	4,279.00
लिक्विड फंड	89,375.12	-66,042.32
अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड	15,066.64	-13,605.66
लो ड्यूरेशन फंड	7,516.57	-1,253.22
मनी मार्केट फंड	17,916.44	-17,899.90
शॉर्ट ड्यूरेशन फंड	2,769.57	-2,173.23
मीडियम ड्यूरेशन फंड	389.52	-156.84
कॉरपोरेट बॉन्ड फंड	5,121.91	-1,443.61
बैंकिंग और पीएसयू फंड	212.27	-1,967.31

(राशि रुपये में)

Source: AMFI

कंटेंट : अमर उजाला बोनस टीम

लोकमानस

loksatta@expressindia.com

कथनी आणि करणीत समन्वय हवा

'देशाला बिघडवणारे साहित्य निर्माण करू नका!' या मथळ्याची बातमी (लोकसत्ता-३० नोव्हेंबर) वाचली. नागपूरमध्ये सुरू असलेल्या राष्ट्रीय पुस्तक महोत्सवात डॉ. मोहन भागवत यांनी साहित्यिकांनी देश घडवणारे साहित्य निर्माण करावे असा उपदेश करत असताना, 'आम्ही राष्ट्रवादी नसून राष्ट्रीय आहोत... 'राष्ट्र' आणि 'नेशन' या संकल्पनांमध्ये मूलभूत फरक असून आपले राष्ट्र प्राचीन काळापासून अस्तित्वात आहे', 'विविधता असूनही एकातेचा संस्कार हीच राष्ट्रीयत्वाची खरी ओळख', 'राज्य अस्तित्वात नसतानाही आपण राष्ट्र होतो', अशी प्रचारकी विधाने केली.

शंभरीकडे गेलेल्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने याप्रमाणे जर व्यवहार केला असता तर देशभर पसरलेल्या या संघटनेला गेल्या ७५ वर्षात लोकांनी खांद्यावरून कधीही खाली उतरले नसते. वास्तविक पाहता देशातील डावे गट, फुले- शाहू- पेरियार- आंबेडकर आणि गांधी- नेहरू यांनी ज्या राष्ट्राचे स्वप्न पाहिले होते, त्याच्या अगदी विपरीत राष्ट्राचे उद्दिष्ट घेऊनच संघ सार्वजनिक राजकारणात उतरला. संघाच्या राष्ट्र संकल्पनेत बहुजन कष्टकरी व पददलितांच्या हिताला स्थान कधी होते? जातिअंताच्या चळवळींना आणि डाव्या चळवळींना विरोध करून प्रस्थापित समाज व्यवस्थेच्या (वर्णधर्म-जातीव्यवस्था भेदावर आधारलेल्या) रक्षणासाठी संघाने वेळोवेळी उघड भूमिका घेतल्या. मंडलच्या रूपाने १९९० च्या दशकात दुसरी सामाजिक क्रांती होऊ घातलेली असताना, संघाचे इंग्रजी मुखपत्र असलेल्या 'दि ऑर्गनायझर'ने घेतलेली भूमिका याची साक्ष आहे. संघाच्या त्या मुखपत्राची संपादकीय भूमिका मंडल आयोगाला 'जातीय युद्धाचे पुनर्जीवन' म्हणूनच पाहण्याची होती. ओबीसी आरक्षणाने गुणवत्ता रोडावेल, जातिभेद तीव्र होतील आणि एकूणच सामाजिक वीण उस्कटून जाईल म्हणून संघ त्या वेळी गळे काढत होता. आज ओबीसीमध्ये संचारलेला आत्मविश्वास व झालेला भौतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास ही मंडलची देणगी आहे, हे उघड सत्य आहे. मंडलने देशातील ५२ टक्के ओबीसींमध्ये जे नवजागरण घडून आणले त्याची दिशा आपल्याविरुद्ध वळून वर्णजातवादी, पुरुषसत्ताक चौकटीला छेद बसू नये म्हणून संघाची राजकीय विंग असलेल्या भाजपने, लालकृष्ण अडवाणीच्या नेतृत्वाखाली, रथयात्रेद्वारे, आयोध्या राम मंदिराचा मुद्दा पुढे करून ओबीसींचे लक्ष जातीगत संघर्षाकडून धार्मिक अस्मितेकडे पुन्हा वळविण्यात यश मिळवले. आज नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखालील भारतीय जनता पक्षाने त्यात हिंदुत्वावर आधारलेल्या नॅशनल पॉप्युलिझमची भर टाकून सेक्युलर लोकशाहीला वंशवादी लोकशाहीच्या वळणावर आणून सोडले आहे.

भागवत यांनी म्हटल्याप्रमाणे आपल्या परंपरेत परस्पर मैत्री, सहकार्य आणि एकत्र चालण्याची संस्कृती आहे हे खरे असेल; परंतु संघामध्ये तसे असते तर, संस्कृती रक्षकांचा धुडगूस, झुंडीचा उन्माद, सीएए, एनआरसी, एसआयआर यांद्वारे अल्पसंख्याकांना घाबरवून सोडण्याची संघप्रणीत सत्ताधाऱ्यांची धोरणे, स्वायत्त संस्थांचा राजकीय विरोधकांना संपवण्यासाठी केलेला वापर यावर सरसंघचालकांनी ठोस भूमिका घेऊन जाहीर विरोध केला असता. तसे झाले नाही, होणार नाही, कारण संघाचा राष्ट्रवाद पूर्वीही व्यावर्तक होता व आजही आहे. म्हणून त्यांच्या कथनी आणि करणीमध्ये नेहमीच फरक राहिला आहे.

■ **प्रा. डॉ. विठ्ठल दहिफळे,** नांदेड.

तपोवन रक्षणाची नैतिक जबाबदारी

नाशिकच्या 'तपोवन'मधील शंभर दोनशे वर्षांपेक्षा जास्त वयांची झाडे तोडण्याबाबत घेतलेल्या २४ नोव्हेंबरच्या जनसुनावणीला लोकांनी चांगला प्रतिसाद दिला. चांगले मुद्दे प्रभावीपणे मांडले. एक पूर्ण वाढलेले झाड दररोज २७४ लिटर किंवा वर्षभरात १२० किलो ऑक्सिजन हवेत सोडते. कार्बन उत्सर्जन तुलनेने कमी असते. वैद्यकीय कारणासाठीच्या १० किलो सिलेंडरसाठी आता कर वगळून १६ हजार रुपये किंमत आहे. साधारण एक झाड दोन लाख रुपयांचा ऑक्सिजन देते. पिंपळ, वड, कडुनिंब इ. झाडे ऑक्सिजन रात्रंदिवस हवेत आपणासाठी देत असतात. तपोवनसारखी वृक्षवल्ली समाजासाठी निसर्गाने दिलेला विमा आहे. 'वृक्षवल्ली आम्हा सोयरे वनचरे' संत तुकारामांचा संदेश, 'पात्याचे नुकसान करू नका' हा छत्रपती शिवाजी महाराजांनी सैन्याला दिलेला आदेश, शेती कॉलेजसाठी जोतिबा फुले यांनी स्वतःच्या जमिनीचे केलेले योगदान, छ.शाहू महाराजांनी कोल्हापुरात राखीव ठेवलेली बर्कीचे रान आणि दाजीपूर ही जंगले तर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधानांतच झाडे आणि वन्य पशुपक्षी यांना दिलेले संरक्षण असा मोठा वारसा महाराष्ट्राला आहे. तपोवन रक्षणाची नैतिक जबाबदारी आपल्यावर आहे.

■ **जयप्रकाश नारकर,** वसई पश्चिम

'स्वविवेका'ची निष्पत्ती काय?

'समोरच्या बाकावरून' या पी. चिदम्बरम यांच्या सदरातील 'संविधान गुंडाळलेच; विवेकालाही सोडचिठ्ठी' हा लेख (रविवार विशेष - ३० नोव्हेंबर) वाचला. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम १६३ नुसार राज्यपालांना स्वतःच्या विवेकबुद्धीने काम करण्याचा अधिकार दिला आहे. हा स्वविवेक अधिकार असला तरीही, लोकप्रतिनिधींनी पारित केलेल्या विधेयकाची अडवणूक राज्यपालांनी करणे चुकीचेच ठरते. राज्यपालांच्या हटवादीपणामुळे स्वायत्त असलेल्या विधिमंडळांना बाधा येते. राज्यपालाचा मनमानीपणा नवा नाही. महाराष्ट्रात मविआ सरकारच्या काळात १२ आमदारांच्या नियुक्तीवरून राज्यपाल व राज्य सरकार यांच्यात वितुष्ट आले होते. सरकार विरोधी पक्षाचे असेल, तर राजकीय सोयीसाठी राज्यपालांचा वापर केला जातो. त्यामुळेच राज्यपालांच्या स्वविवेकामधून काय निष्पती होते हेसुद्धा पाहिले गेले पाहिजे.

■ **विनायक फडतरे,** पुणे

राज्यपालांनी १० वर्षांत सरकार पाडले नाही

'समोरच्या बाकावरून' मधील ३० नोव्हेंबरचा लेख वाचून वाटले की, चिदम्बरम यांनी थोडे मागे पाहिले असते तर सगळा अंधारच दिसला असता! चिदम्बरम काँग्रेसचे नेते आहेत, त्या पक्षाइतका राज्यपालपदाचा सवंग वापर विरोधी नेते व सरकारे पाडण्यासाठी अन्य कोणी केला नसेल. एकही सरकार २०१४ ते २०२५ या काळात राज्यपालांकरवी एकही राज्य सरकार पाडले गेलेले नाही. राज्यपालपदाची पात्रता पूर्वी होती तीच आताही आहे. देश चालवणे एका पक्षाची मक्तेदारी नाही हा विवेक ज्यांनी सोडला, त्यांची चिंता वाढणारच.

■ **डॉ. मंगेश नागापूरकर,** शिरड (जि. हिंगोली)

प्रगत देशांपेक्षा सरकारी नोकऱ्या इथे कमी

'आरक्षण हवे? पण नोकऱ्या कुठे आहेत?' हा लेख (२८ नोव्हेंबर) वाचला. सध्या देशातील तसेच राज्यातील रोजगाराची स्थिती भयावह आहे आणि ही परिस्थिती दिवसेंदिवस विदारक होत चाललेली आहे. देशातील कार्यक्षम लोकसंख्येचे (वय १५ ते ६४) प्रमाण ६४ टक्के आहे. या कार्यक्षम लोकसंख्येला रोजगार देण्यासाठी सरकारने सार्वजनिक क्षेत्रात जास्त रोजगार उपलब्ध करून देणे गरजेचे असूनही, या क्षेत्रातील रोजगारांचे प्रमाण घटून आज तीन ते चार टक्क्यांवर आले आहे. आंतरराष्ट्रीय श्रम संघटनेच्या (आयएलओ) आकडेवारीनुसार हे प्रमाण अमेरिकेतही १३ टक्के; जर्मनी व ब्राझीलमध्ये १२ टक्के; तर बहुतेक प्रगत युरोपीय देशांत १४ टक्क्यांच्या पुढेच आहे.

महाराष्ट्रात सरकारने ४ मे २०२२ च्या शासन निर्णयानुसार ७५ हजार पदांची महाभरती जाहीर केली आणि आजवर जवळपास एक लाख पदे भरली गेली (यांत वैद्यकीय शिक्षण संचालनालयातील पाच हजार पदे, तलाठी ४६४४ पदे, विविध जि. प. मधील १६ हजार ४६० तर एकंदर 'ड गट' १० हजार पदे यांचा समावेश आहे). राज्यात तीन लाख पदे रिक्त असून त्यासाठी विविध विभागांमध्ये नवीन आकृतीबंध तयार करण्याचे काम चालू आहे- तो फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत जाहीर करण्याची मुदत विभागांना देण्यात आलेली आहे.

■ **प्रमोद लक्ष्मण सरवदे,** सांगली

आरक्षण हे फक्त नोकऱ्यांसाठीच आहे?

'आरक्षण हवे? पण नोकऱ्या कुठे आहेत?' हा निखिल दगडू रांजणकर यांचा लेख (२८ नोव्हेंबर) वाचला. शासनाच्या सर्वच क्षेत्रांत कंत्राटीकरण, रोजंदारी सुरू केल्याने कायमस्वरूपी नोकऱ्यांतील आरक्षण जवळपास संपुष्टात येत आहे. त्यामुळे आरक्षण असून नसल्यासारखे आहे, असा अनेकांचा समज आहे. परंतु संविधानाच्या अनुच्छेद १५ अन्वये शिक्षणासाठी दिलेले आरक्षण हवेच आहे. सामाजिकदृष्ट्या मागास, इतर मागास मागास वर्गातील विद्यार्थ्यांना या आरक्षणाची नितांत आवश्यकता आहे. नाहीतर फक्त वरच्या वर्गातील विद्यार्थीच शिकत राहतील.

■ **घन:श्याम पांडुरंग मुकणे,** बोरिवली पश्चिम (मुंबई)

महिला आरक्षणातही राजकीय घराणेशाही

नगरपालिका व नगरपंचायत निवडणुकीत 'मागासवर्गीय महिलां'साठी आरक्षित झालेल्या ठिकाणी प्रस्थापितांच्या घरांतील मूळच्या मागासवर्गीय सुनांची वर्णी लागत आहे. याचा परिणाम मागास महिला आरक्षणाच्या मूळ हेतूलाच हरताळ फासणारा आणि लोकशाहीला मागे लोटणारा ठरेल...

डॉ. अनिल जगन हिवाळे
भुसावळ कला, विज्ञान आणि पु. ओ. नाहाटा वाणिज्य महाविद्यालयात सहयोगी प्राध्यापक
hiwaleanil@gmail.com

महाराष्ट्रातील २४७ नगरपालिका आणि १४७ नगरपंचायतींच्या निवडणुकीचे मतदान मंगळवारी- २ डिसेंबर रोजी होत आहे, त्यासाठी सुमारे दोन महिन्यांपूर्वी (६ ऑक्टोबर) नगरअध्यक्षपदांची आरक्षणे सोडत पद्धतीने जाहीर झाली. यात मागासवर्गीय (अनुसूचित जाती, जमाती व इतर मागास वर्ग) प्रवर्गासाठी ५० टक्के जागा राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत. या ५० टक्के राखीव जागांमध्ये नगरपालिका आणि नगरपंचायतीत अनुसूचित जातीच्या महिलांना अनुक्रमे १७ आणि ९ जागा, अनुसूचित जमातीच्या महिलांना अनुक्रमे ६ आणि ७, इतर मागास प्रवर्गातील (ओबीसी) महिलांना ३४ आणि २० तर खुल्या गटातील महिलांना अनुक्रमे ६८ आणि ३८ जागा देण्यात आलेल्या आहेत.

मागास समाज घटकांना मिळालेले एकूणच आरक्षण सामाजिक-सांस्कृतिक व ऐतिहासिक वंचिततेसाठी आहे, वैयक्तिक जातीय ओळखीसाठी नाही. ज्यांना कधीच सत्ता मिळालेली नाही, अशा समाज घटकांना संधी देण्यासाठी राजकीय आरक्षणाची व्यवस्था आहे. महिलांना मिळालेल्या आरक्षणाचा हेतू आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिकदृष्ट्या मागे असलेल्या समूहांना राजकीय प्रतिनिधित्व देणे हा आहे. महिला आरक्षणाचा हेतू वंचित वर्गातील महिलांच्या माध्यमातून त्या समाज घटकाला प्रतिनिधित्व मिळावे हा आहे. पण अशा प्रकारे, या हेतूंसाठी मिळालेल्या राजकीय आरक्षणात महाराष्ट्रात आणि देशातील विविध राज्यांत पुढारलेल्या काही जाती साठमारी करताना दिसतात. राज्यातील काही ठिकाणी मागासवर्गीय महिलांसाठी आरक्षित असलेल्या जागांवर उच्च जात वर्गांत विवाह झालेल्या मागास महिलांना राजकीय आरक्षणाच्या जागांवर सर्वच प्रमुख राजकीय पक्षांकडून संधी दिली जात आहे. विवाहाने मागासवर्गीय महिलांची जात बदलत नसली तरी त्या स्त्रीची वास्तविक सामाजिक सत्ता आणि संधीची समानता यातील स्थिती सुधारते. यावर कायद्याने फार नियंत्रण नसले, तरी याचे सामाजिक परिणाम मोठे आहेत. याने मूळ मागासवर्गीय राजकीय नेतृत्वाचा आवाज कमकुवत होण्याची शक्यता आहे. दलित, आदिवासी आणि इतर मागासवर्गीयांना असलेले राजकीय आरक्षण 'मागासवर्गीय सुनांच्या' माध्यमातून आपल्याच घरात किंबहुना आपल्याच जातीत असावे, हा यामागचा मुख्य उद्देश शेकडो वर्षांपासून सत्ताधारी असणाऱ्या जातींचा असतो. अनेक वर्षं सत्ताधारी असलेल्या जातींची अशा प्रकारची भूमिका मागास महिलांच्या राजकीय आरक्षणाचा खरा उद्देश साध्य करेल काय? की मागास पुरुषांसाठी दिलेल्या राजकीय आरक्षणाप्रमाणेच हे आरक्षणही कालांतराने निष्प्रभ ठरेल?

राजकीय पक्षांचा दृष्टिकोन 'सामाजिक न्याय' पेक्षा राजकीय लाभ घेण्याचा असतो. त्यांना जिंकणारा चेहरा किंवा समीकरण हवे असते. अशा राजकीय पक्षांना आणि त्या पक्षाच्या माध्यमातून स्वजातीय सत्तेला टिकवून ठेवण्यासाठी त्यांना मागासवर्गीय महिलेची जातीय ओळख कायदेशीर पात्रता देते; तर तिच्या सासरच्या जातीची आणि घरातील आर्थिक-सामाजिक ताकद निवडणूक यंत्रणा राबवण्यासाठी बळ मिळवून देते. परिणामी मूळ वंचित गटांतील खऱ्या नेतृत्वाला संधी मिळत नाही. मुळातच सामाजात प्रभावी असलेल्या कुटुंबातील महिला जेव्हा आरक्षित जागेवर उभ्या राहतात, तेव्हा त्यांच्या प्राधान्यक्रमांमध्ये जमिनीचे प्रश्न, आरोग्य, शिक्षणातील मागासलेपणा, अत्याचार, भेदभाव, वनअधिकार यांसारखे तळागाळातील दलित-आदिवासींच्या हक्कांचे विषय प्रामुख्याने राहात नाहीत. याने आरक्षणाला अपेक्षित असणारा तळागाळातील समाजाच्या प्रतिनिधित्वाचा लाभ नाहीसा होतो.

महाराष्ट्रातील प्रदेश आणि जिल्हानिहाय दिसणारे पॅटर्न अगदी स्पष्ट आहेत. खानदेशातील जळगाव, धुळे, नंदुरबार, नाशिक-हा आदिवासीबहुल पट्टा आहे. या भागात बऱ्याच ठिकाणी आरक्षण असूनदेखील आरक्षित जागेवरील सत्ता बिगरआदिवासी राजकीय सत्ताधारी जाती आणि घराण्यांच्या हातात आहे. येथे आदिवासींसाठी आरक्षित काही जागा बिगरआदिवासी व राजकीयदृष्ट्या प्रभावी कुटुंबांतील आदिवासी सुनांच्या हाती गेल्या आहेत. या महिला माहेरकडून अनुसूचित जमातीच्या असतात, पण सासरकडची सामाजिक रचना आणि आर्थिकदृष्ट्या बलाढ्य स्थिती त्यांना सामान्य आदिवासींच्या पुढे नेऊन ठेवते. परिणामतः वनअधिकार, आरोग्य, शिक्षण यांसारख्या आदिवासी विशेष मुद्द्यांचा आवाज कमी होतो. पक्षांना आदिवासी नेतृत्वाऐवजी नियंत्रण ठेवता येईल असा चेहरा अधिक सोयीचा असतो. या भागात गैरआदिवासी कुटुंबांतील अनेक आदिवासी सुना ग्रामपंचायत ते नगराध्यक्षांच्या जागांवर विराजमान झालेल्या आहेत.

मराठवाडा पट्ट्यात दलितांना आरक्षित जागांवर ज्या दलित महिलांचा व्यापारी किंवा उच्चवर्णीय घराण्याशी विवाह झालेला आहे, त्यांच्या माध्यमातून काही ठिकाणी सत्ता नियंत्रित केली जाते. मराठवाड्यात व्यापारी व उच्चवर्णीय कुटुंबांचे स्थानिक प्रभावक्षेत्र मोठे आहे. इथे काही अनुसूचित जातींच्या आरक्षित जागांवर अशा महिला निवडून येतात, ज्यांचे विवाह राजकीय किंवा आर्थिकदृष्ट्या शक्तिशाली घराण्यात झालेले असतात. परिणामी सामाजिक संघर्षाने तयार झालेले खरे स्थानिक दलित नेतृत्व मागे पडते. विकासाच्या नावाखाली उच्चवर्गीय अजेंडा पुढे केला जातो.

विदर्भात मागासवर्गीय महिला या इतर उच्चशिक्षित उच्चवर्णीय घराण्यांशी विवाहबद्ध झालेल्या आहेत. विदर्भात शिक्षण आणि संघटनात्मक राजकारण मजबूत असल्याने इथे काही वेळा आंतरजातीय विवाहातून मागासवर्गीय महिलांना राजकीय व्यासपीठ मिळते. त्यांच्या सासरकडील जातीचे संघटन, निधी आणि नेटवर्कचे प्रचंड सामर्थ्य असते. अशा स्थितीत मूळ मागासवर्गीय सामाजिक चळवळीचे मुद्दे गौण होतात. पक्षाला एक 'सुरक्षित' मागासवर्गीय चेहरा मिळतो, पण समुदायाचा आवाज कमकुवत होतो.

पश्चिम महाराष्ट्र भागात सहकारी संस्थांचा प्रभाव मोठा आहे आणि त्यांना राजकीय नियंत्रणाची गरज असते. इतर मागासवर्गीय सुना त्या सहकार क्षेत्रातील जाती आणि घराण्यांच्या राजकीय समीकरणात बसतात. त्यांना आरक्षित जागेतून उमेदवारी देणे म्हणजे मागासवर्गीय प्रतिनिधित्व नव्हे, तर सहकारी नेटवर्कची राजकीय सुरक्षितता असते. यामुळे मागासवर्गीय समुदायाचा स्वतंत्र राजकीय आवाज जवळपास नाहीसा होतो. सहकारी घराण्यांचे हितसंबंध प्राधान्याने येतात.

गेल्या कित्येक दशकांपासून 'राजकीय आरक्षणाची' व्यवस्था असली तरी त्याच्या जोरावर दलित-आदिवासींमध्ये राजकीय नेतृत्व निर्माण होताना दिसते. आरक्षित जागेवर निवडून येणारे अनेक नेते चार-पाच वेळा एखाद्या मतदारसंघाचे नेतृत्व करत असले तरी आरक्षणाचा कालावधी संपल्यानंतर ते नेतृत्व नाहीसे होते. आरक्षण बदला बरोबरच त्यांचे राजकीय अस्तित्व संपलेले असते. असे नेतृत्व मागासवर्गीयांचे नसून सत्ताधारी पक्ष आणि जाती यांनी उभारलेले बुजगावणे असते. त्यामुळे अनेक दलित, आदिवासी सामाजिक चळवळी अशा राजकीय आरक्षणाला संपवण्यात यावे अशी मागणी वेळोवेळी करताना दिसतात. उच्च आणि बहुसंख्याक जातीच्या 'मेहेरबानी'मुळे झालेले हे राजकीय प्रतिनिधी निव्वळ त्यांना साहाय्य करणाऱ्या समूहांचा अनुनय करताना दिसतात. हे नेतृत्व निवडण्याच्या वेळेपासूनच सत्ताधारी पक्ष व जातसमूह सजग असतात- जी व्यक्ती कुठल्याच सामाजिक/ राजकीय चळवळीचा भाग नसते, अशाच व्यक्तीला नेता म्हणून लोकांवर लादले जाते. दलित-आदिवासींतही ज्या जाती संख्येने अल्प आहेत, अशाच जात समूहांचे नेतृत्व माथी मारले जाते. मागासवर्गीय महिला दुहेरी वंचिततेचा सामना करत असतात. पहिली जातीय वंचितता तर दुसरी लिंगभाव आधारित.

लोकशाही म्हणजे खऱ्या अर्थाने सर्व समाज घटकांचे प्रतिनिधित्व असते. जर काही समूह हजारो वर्षं मागे असतील तर त्यांना पुढे आणणे लोकशाहीचे कर्तव्य आहे. महिलांना दिलेले राजकीय आरक्षण लोकशाहीला समावेशक आणि न्याय्य बनवते. संविधानाच्या प्रस्तावनेत आपण '...सर्व नागरिकांना सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय न्याय,' देण्याचे अभिवचन दिलेले आहे. राजकीय न्यायाचे हे वचन आपण इतर कुणाला दिलेले नसून स्वतःला दिलेले आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्था, विधानसभा आणि लोकसभेच्या पातळीवर आरक्षित जागांच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या आरक्षणाच्या अनुषंगाने आपण आजवर प्रभावी दलित - आदिवासी पुरुषांचे नेतृत्व निर्माण करण्यात अपयशी ठरलो आहोत. जगातील सर्वांत मोठी लोकशाही असणाऱ्या आपल्या देशात हीच अवस्था पुन्हा दलित, आदिवासी आणि इतर मागासवर्गीय जातींच्या महिलांच्या आरक्षणाच्या बाबतीत होऊ नये, ही अपेक्षा.

'तत्त्व-विवेक' हे शरद बाविस्कर यांचे सदर या आठवड्यापुरते बुधवारी प्रकाशित होईल.

कुतूहल

खनिजांचे जैवनिष्कर्षण

सूक्ष्मजीवांचा वापर करून खनिजांच्या स्त्रोतातून खनिज धातू वेगळे करण्याच्या प्रक्रियेला खनिजांचे जैवनिष्कर्षण (बायोलिचिंग) असे म्हणतात. काही जिवाणू आणि बुरशी, खनिजांशी क्रिया करून खनिजांना विरघळवतात आणि त्यातून धातू वेगळे करतात.

प्रथम बुरशीद्वारे आम्लाचा वापर करून जटिल संयुगांचे खंडन (ॲसिडोलिसिस) केले जाते, नंतर ऑक्सिडेशन-क्षपण प्रक्रियेदवारा अघुलनशील धातू विद्राव्य (रेडॉक्सोलिसिस) केले जातात आणि शेवटी त्या धातूचे अणू-रेणू जोडून ठेवले जातात (चेलेशन). या अभिक्रियांमध्ये धातू विरघळवण्याची क्षमता असते.

तांबे या धातूच्या जैवनिष्कर्षणाचे संदर्भ १५व्या शतकपासून मिळतात. केनेथ टेंपल आणि आर्थर कॉलमर हे आधुनिक जैवनिष्कर्षण तंत्राचे उद्गाते मानले जातात. खनिजे विशेषकरून भूभागांमध्ये आणि खडकांच्या थरामध्ये सापडतात. जिवाणूंना योग्य वाढीची परिस्थिती देऊन, जैवनिष्कर्षणाद्वारे कमी दर्जाच्या धातूंवर प्रक्रिया घडवून आणता येते. सोने, चांदी यांसारखे धातू मिळविण्यासाठी नैसर्गिक खनिजांचे ऑक्सिडीकरण करण्यासाठी सूक्ष्मजीवांचा वापर केला जातो. सूक्ष्मजीवांमुळे पायराइट या खनिजामधील सल्फरचे ऑक्सिडीकरण होऊन ते सल्फेटमध्ये रूपांतरित होते. जैवनिष्कर्षण प्रक्रियेत लोह आणि सल्फर ऑक्सिडीकरण करणाऱ्या असंख्य जिवाणूंचा उपयोग करतात. या सूक्ष्मजीवांमध्ये ॲसिडोथायोबॅसिलस थायोऑक्सिडन्स, ॲसिडोथायोबॅसिलस फेरोऑक्सिडन्स, क्रोमोबॅक्टेरिअम वायोलासियम, ईस्चेरेशिया कोलाय व स्यूडोमोनास प्रजाती यांचा समावेश होतो. जैवनिष्कर्षणासाठी बुरशीच्या अनेक प्रजाती जसे की ॲस्पर्जीलस नायजर, पेनीसिलियम सिम्पलिसिसिमम वापरल्या जातात.

जैवनिष्कर्षणाच्या 'डम्प' जैवनिष्कर्षण, 'ढीग' जैवनिष्कर्षण व 'मूळ जागेवर' (इन सीटु) जैवनिष्कर्षण या पद्धती आहेत. तसेच जैवखननासाठी सल्फोलोबस मेटॅलिकस, मेटॅलोस्फेरा सेड्युला या चार टक्के तांबे सहवास सहन करू शकणाऱ्या जिवाणूंचा वापर नियमित केला गेलेला आहे. जैवउत्खनन (बायोमायनिंग) हे 'बायोहायड्रोमेटलर्जी' मधील अनेक अनुप्रयोगांपैकी उत्तम उदाहरण आहे. बायोहायड्रोमेटलर्जीचा पहिला उपयोग तांबे मिळविण्यासाठी सुमारे ३०० वर्षांपूर्वीच केला गेला. जिवाणूंचा वापर करून आजपर्यंत तांबे, सोने, चांदी, युरेनियम, झिंक, कोबाल्ट, निकेल इत्यादी खनिजे मिळवण्यात शास्त्रज्ञांना यश आलेले आहे. खनिजे मिळवण्यासाठी सूक्ष्मजीवांचा वापर खूपच फायदेशीर ठरतो. कारण यासाठी लागणारी प्रक्रिया कमी खर्चाची, पर्यावरणपूरक, स्वच्छ, सुरक्षित व बऱ्याच धातूंच्या स्त्रोतासाठी वापरता येते.

शास्त्रज्ञांनी २०२० मध्ये गुरुत्वाकर्षणविरहित वातावरणात केलेल्या प्रयोगातून हे दाखवून दिले की, अंतराळात जैवनिष्कर्षणाद्वारे बेसाल्टिक खडकांमधून उपयुक्त घटक मिळवता येऊ शकतात.

डॉ. सुहास कुलकर्णी
मराठी विज्ञान परिषद
ईमेल : office@mavipa.org
संकेतस्थळ : www.mavipa.org

व्यक्तिवेध

वयाच्या ३४ व्या वर्षी भरतनाट्यम नृत्यप्रकारातील योगदानासाठी 'संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार (१९६८) आणि पुढे दोनच वर्षांनी 'पद्मभूषण' (१९७०) मिळवणाऱ्या कमला लक्ष्मणन यांना दक्षिण भारताबाहेर मिळालेल्या लोकप्रियतेचे श्रेय नक्कीच हिंदी चित्रपटांचे. पण त्यांनी तमिळ आणि तेलुगु चित्रपटांतही भूमिका केल्या होत्या. दाक्षिणात्त्य अभिनेत्री किंवा हिंदीत नुसतीच एखाद्या गाण्यापुरती नृत्यांगना हा शिक्का स्वतःवर मारून न घेता त्यांनी १९६०पासून चित्रपट कमी केले आणि १९७१च्या 'ज्वाला'मधले 'मेरा ज्वाला नाम, जिया जलाना काम, ओ मतवाले ओ अलबेले रखना दिलको थाम' हे त्यांच्यावर चित्रित झालेले बहुधा अखेरचेच फिल्मी नृत्यगीत ठरले. वयाच्या आठव्या वर्षापासून भरतनाट्यम शिकणाऱ्या आणि त्याही आधीपासून पडद्यावर दिसणाऱ्या कमला यांनी २३ नोव्हेंबर रोजी अमेरिकेत, सान फ्रान्सिस्कोनजीकच्या मिलब्रे या उपनगरात अखेरचा श्वास घेतला.

कमला कुमारी

कमला यांचे बालपण मुंबईचे... 'परिस्थिती बदलली म्हणून कुढायचे नाही- आपण बदलायचे, तेही स्वतःचे गुण नुसते राखून नव्हे तर वाढवून!' - हे बाळकडू जणू या महानगराकडून त्यांना मिळाले. आईवडिलांनी लच्छू महाराजांकडे चिमुरड्या (वय वर्षे साडेतीन!) कमलाला कथ्थक शिकायला पाठवले. त्यांनी थोडे धडे दिले पण कमला नाच शिकली ती मुख्यतः 'प्रोफेसर मोरे' म्हणवणाऱ्या नृत्यदिग्दर्शकांकडे आणि सुंदरप्रसाद यांच्याकडे. कमला यांचा जन्म १६ जून १९३४चा; म्हणजे १९३९मध्ये 'अस्तिक समाज, मुंबई' येथील रामनवमी उत्सवात रंगमंचावर पदार्पण करताना या नृत्यांगनेचे वय होते अवघे पाच वर्षे. पण त्याहीआधीच्या अबोध वयात, 'बालयोगिनी' (१९३६) आणि सोहराब मोदींच्या 'जेलर' (१९३८) मध्ये त्या पडद्यावर दिसल्या होत्या. 'रणजित स्टुडिओ'चे चंदूलाल शहा यांनी या मुलीला १९३९मध्ये - म्हणजे पाचेक रुपयांना चांदीचा पेला मिळायचा अशा काळात- महिना शंभर रुपये पगारावर नोकरीच दिली, त्यामुळे पुढील ३ वर्षे त्यांच्या चित्रपटांत ही मुलगी दिसली, नाचली. पण कुटुंबानेच १९४२ मध्ये तत्कालीन मद्रास प्रांतातल्या मदनपल्ली येथे (आता हे शहर आंध्र प्रदेशात आहे) स्थलांतर केल्याने थेट के. मुथुकुमारप्पा पिल्लै यांच्यासारख्या गुरूकडून भरतनाट्यम शिकण्याची संधी त्यांना मिळाली. भरतनाट्यमची घराणी 'बानी' म्हणून ओळखली जातात. पाण्डनल्लूर, तंजावूर, वेळ्ळुवूर आणि मेलात्तुर या चार 'बानी' पूर्वापार, तर त्यानंतर म्हैसूर आणि कलाक्षेत्र बानीही मोजल्या जातात. यापैकी वेळ्ळुवुर परंपरा पिल्लै कुटुंबाने आजही राखली आहे. मुथुकुमारप्पा वयस्कर झाल्यावर त्यांचे नातेवाईक वेळ्ळुवूर रामय्या पिल्लै यांच्याकडून नृत्यशिक्षण सुरू असतानाच चित्रपटांत भूमिका आणि रंगमंचीय कार्यक्रमही त्या करू लागल्या.

लग्नानंतरही हे सारे सुरू ठेवायचेच, ही ईर्षा त्यांनी जपली खरी, पण त्यापायी पहिला संसार तुटला आणि दुसरे लग्न झाल्यावर शिष्य तयार करण्याचे काम अधिक मोठे आहे, हे त्यांना पटले. नृत्य शिकवणे त्यांनी १९७० पासून सुरूही केले. पण आता अमेरिकी सैन्यात अधिकारी असलेला मुलगा तिथे शिकत असताना, १९७८-७९ मध्ये अमेरिकेस जाऊन आल्यावर, त्या देशात भरतनाट्यम शिकू इच्छिणारे अनेक पण गुरू कमी, हे त्यांना दिसले. अखेर १९८० पासून त्या भारत-अमेरिका ये-जा करू लागल्या. (दुसरे) पती, टी. व्ही. लक्ष्मीनारायणन यांच्या निधनानंतर- १९८३ पासून त्या अमेरिकेतच राहू लागल्या. त्यांचे पहिले पती व्यंगचित्रकार आर. के. लक्ष्मण, हीदेखील त्यांची आणखी एक ओळख.

तर्कतीर्थ विचार

तर्कतीर्थांचा वाचन- व्यासंग

तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी यांनी आपल्या अध्ययन, वाचन व लेखनाबद्दल क्रमवारीने वा कालबद्ध असे वैकासिक लेखन करून ठेवलेले नाही. ते वेदान्ती होते खरे; पण त्यांचे वेदवाचन कसे झाले, याचे तर्कसंगत विवेचन आढळत नाही. त्यामुळे त्यांचे आत्मपर लेख, मुलाखती, भाषणे यांच्या अवगाहनातूनच त्याचा शोध घ्यावा लागतो. आपल्या मुलाने संस्कृत शिकावे, नुसते याज्ञिक वा वैदिक बनू नये, तर त्याने पंडित-शास्त्री व्हावे, अशी वडिलांची आकांक्षा होती. ते टिळक भक्त होते. घरी देवघरात लोकमान्य टिळकांची तसबीर पुजली जायची. आपल्या मुलाने संस्कृत पंडित होऊन गायकवाड वाड्यात (टिळक निवास) कीर्तन करावे, अशी त्यांची महत्त्वाकांक्षा होती.

पिंपळनेर या जन्मगावी असलेल्या मराठी मुलांच्या शाळा क्र. १ मध्ये त्यांचे इयत्ता तिसरीपर्यंतचे शिक्षण सन १९०७ ते १९१० या काळात झाले. मग काही वर्षे वडिलांनी घरी शिकविले. 'अमरकोश' वडिलांनी वाचून घेतला. महिपतीलिखित 'श्रीसंतलीलामृत' वाचल्यानंतर 'पांडव प्रताप', 'हरिविजय' ग्रंथांचे वाचन त्यांनी केले. वयाच्या १३व्या वर्षी सन १९१४मध्ये वडिलांनी तर्कतीर्थांना वाईच्या प्राज्ञपाठशाळेत वेदाध्ययनासाठी दाखल केले. तिथे त्यांनी वेद, वेदांगे यांचा अभ्यास केला. कालिदासाच्या 'रघुवंश'चे वाचन, अध्ययन केले. तर्क, न्याय शिकले. व्युत्पत्ती, पद, व्याकरण शिकले. पंक्ती लावण्यास शिकले. वादविद्या ग्रहण केली. या काळात 'दिनकरी', 'जागदीशी', 'गादाधरी', 'चतुर्दशलक्षणी', 'सिद्धान्तलक्षण'चा अभ्यास झाला. 'वेदांतसार', 'पंचदशी', 'लघुसिद्धान्तकौमुदी', 'अर्थसंग्रह'चे वाचन व अध्ययन झाले.

तर्कतीर्थांचा वाचनक्रम आपण अभ्यासू लागू तर लक्षात येते की, त्यांचे पायाभूत प्राथमिक वाचन संस्कृत होते. नंतर ते इंग्रजी शिकून वाचू लागले. इंग्रजी त्यांना आचार्य विनोबा भावे यांनी, तर संस्कृत स्वामी केवलानंद सरस्वती यांनी शिकवले. विनोबांनी तर्कतीर्थांना 'तर्खडकर भाषांतरमाले'द्वारे इंग्रजी शिकवले. इंग्रजीच्या तीन महिन्यांच्या अध्ययनानंतर त्यांनी टॉलस्टॉयने मुलांसाठी तीनचारशे शब्दांच्या ५२ छोट्या प्रकरणांत लिहिलेले 'टीचिंग ऑफ ख्राइस्ट' वाचले. लॅम्ब भावंडांनी मुलांसाठी लिहिलेले 'टेल्स फ्रॉम शेक्सपीअर' वाचले. मग इंग्रजी वाचन क्रम बनून गेला. तर्कतीर्थ हिंदीतही वाचत. स्वामी सत्यदेव यांचे हिंदी निबंध त्यांना आवडले होते.

वाचनक्रमात संस्कृत, हिंदी, इंग्रजीनंतर मराठीचा क्रम लागावा, याचे आश्चर्य वाटल्यावाचून राहात नाही. इंग्रजी पुस्तकांच्या मराठी भाषांतराद्वारे त्यांनी मराठी वाचनाचा प्रारंभ केला. तत्पूर्वी त्यांनी आगरकरांचे काही लेख (निबंध) वाचले होते. 'इनामदारांचा बाळू', 'हरी आणि त्र्यंबक' ही मराठी भाषांतरे त्यांनी वाचली; पण इंग्रजीचे गंभीर वाचन, अध्ययन तर्कतीर्थांनी कायदेभंगाच्या चळवळीत धुळ्याच्या तुरुंगात शिक्षा भोगत असताना केले. द्वा. भ. कर्णिकांमुळेच त्यांचा मार्क्सशी परिचय झाला. तर्कतीर्थांनी सन १९३० ते १९३५च्या काळात एंगल्सचे 'अँटी डूरिंग' (मार्क्सवादाचे टीकाकार युजीन डूरिंग यांना प्रत्युत्तर), 'डायलेक्टिक्स ऑफ नेचर', 'मॅनिफेस्टो ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी' आदी ग्रंथ वाचले. मानवेंद्रनाथ रॉय यांच्या सहकार्य आणि संपर्कामुळे मार्क्सवादी, कम्युनिस्ट बनले. प्लेखानोव्ह या रशियन कम्युनिस्ट लेखकाचे साहित्य तर्कतीर्थांनी अभ्यासले. नंतर त्यांनी 'हेगेल' वाचला. विशेषतः 'हिगेल्स फिलॉसॉफी ऑफ दि स्टेट अँड ऑफ हिस्ट्री' त्यांना आवडले.

नंतरच्या काळात लोकमान्य टिळकांच्या 'गीतारहस्य'ने तर्कतीर्थांना प्रभावित केले. आपल्या वाचन नि विचाराचे सार अधोरेखित करीत तर्कतीर्थांनी एका मुलाखतीत सांगितले आहे, ''सर्वसंग्राहक असे अंतिम तत्त्वज्ञान जेव्हा तुम्ही मांडू जाता, याला आपण विश्वदर्शन आणि आत्मदर्शन असे म्हणूया- तेव्हा त्याच्यामध्ये अडचणी कायम राहणारच आणि त्या अनुलंघ्य आहेत, अशी माझी समजूत आहे... खरा प्रश्न जग बदलण्याचा आहे आणि ते आपण बदलतो, हेच वास्तव विश्व आहे, आत्म्याच्या स्वतःच्या बाहेर असलेले विश्व याचा पुरावा आहे... मनुष्यजात एक व्हायचा प्रयत्न करते आहे, आपले एक सर्वसमावेशक असे मनोविश्व निर्माण करण्याचा प्रयत्न करते आहे. कारण, तिला या विश्वातून नष्ट व्हायचे नाही. परस्पर विद्रोहामुळे मानवजाती नष्ट होण्याची शक्यता आहे. म्हणून भिन्न संस्कृती एकत्र येणे, भिन्न लोक व वंश एकमेकांत मिसळून जाणे आवश्यक आहे.''

- डॉ. सुनीलकुमार लवटे
drsklawate@gmail.com

सत्ताविसाचा सट्टा!

वाढीव आरक्षणासाठी घटनादुरुस्ती हाच उपाय. तो केंद्र सरकार करत नाही. तरीही स्थानिक निवडणुकांत फसव्या आरक्षणाची लालूच का दाखवली जाते?

सरकार कोणतेही असो. काही निवडक जाती घटक तसेच प्रवर्गांना वेगवेगळ्या माध्यमातून खूश करणे हेच सरकारचे कर्तव्य असे अलीकडे मानले जाऊ लागले आहे. या वास्तवाचे ताजे उदाहरण म्हणजे आरक्षणाचा मुद्दा. हा आरक्षणाचा खेळ किती घातक आहे हे सर्वोच्च न्यायालयाचे ताजे निर्देश दाखवून देतात. सध्या राज्यात जी स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुकांची रणधुमाळी सुरू आहे, त्यात अनेक ठिकाणी आरक्षणाने ओलांडलेली ५० टक्क्यांची मर्यादा घटनाभंग करणारी आहे. तरीही आम्ही निवडणूक प्रक्रिया थांबवणार नाही, पण जे निवडून येतील त्यांचे भवितव्य अंतिम निकालावर अवलंबून असेल असे न्यायालयाने या निकालात स्पष्ट केले. यातून अनेक प्रश्न उभे ठाकतात. त्यातला पहिला व महत्त्वाचा म्हणजे 'ओबीसी' आरक्षणाची मर्यादा नेमकी किती असावी हा. अलीकडच्या काही निवडणुकांमध्ये समाजातील विविध जाती, धर्माची पक्षनिहाय विभागणी ठळकपणे दिसून येते. यातून 'ओबीसी' हाच विद्यमान सरकारच्या विजयाला हातभार लावणारा मोठा प्रवर्ग आहे हे अधोरेखित झाले आहे. मग त्या वर्गाच्या पदरात जास्तीत जास्त दान कसे टाकता येईल यासाठी वेगवेगळ्या पातळीवर प्रयत्न सुरू झाले. त्याचाच एक भाग म्हणजे हे २७ टक्के आरक्षण. राज्यात सर्व ठिकाणी ते लागू करताना आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली जात आहे याचे भान ना निवडणूक आयोगाला राहिले, ना सरकारला. न्यायालयाचा निकाल नेमका यावर बोट ठेवतो. मुळात राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होत आहेत त्या आठ वर्षांनंतर. मधल्या काळात काही ठिकाणी या निवडणुका झाल्या. तेव्हा महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेत होते. तेव्हाही ओबीसींना खूश करण्यासाठी असाच २७ टक्के आरक्षणाचा घाट घातला गेला. नंतर प्रकरण न्यायालयात गेले. तिथे या प्रवर्गातील निवडणुका रद्दबातल ठरवण्यात आल्या. यानंतर तब्बल २८९ ठिकाणी पुन्हा त्या घ्याव्या लागल्या. तरीही तेव्हाच्या सरकारची आरक्षणाची भूमिका कायम राहिली आणि त्यासाठी विधिमंडळात एक विधेयक पारित करून तसा कायदा करण्यात आला. तोही सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला. या घडामोडीची सर्व माहिती असूनसुद्धा विद्यमान महायुतीचे सरकार त्याच पावलावर पाऊल टाकत पुढे निघाले. त्याला आता चाप बसला असला तरी ओबीसींच्या आरक्षणाचे काय? विद्यमान स्थितीत ते लागू करता येणे शक्य आहे का? नसेल तर ते लागू करण्यासाठी विधिवत मार्ग कोणता यावर चर्चाच होताना दिसत नाही. चर्चा होते ती पूर्णपणे राजकीय स्वरूपाची. म्हणजे महाविकास आघाडीला जे जमले नाही ते आम्ही करून दाखवले अशी. निवडणुका जिंकण्यासाठी व त्यातल्या त्यात ओबीसींची मते मिळवण्यासाठी कदाचित ती फायदेशीर ठरणारी असेलही, पण मूळ मुद्द्याचे काय? या प्रश्नातल्या गाभ्याला नेमके कोण हात घालणार?

सध्याच्या परिस्थितीत 'ओबीसीं'ना राजकीय आरक्षण द्यायचे असेल तर घटनेच्या अनुच्छेद २४३ मध्ये दुरुस्ती करण्याशिवाय पर्याय नाही. ही घटनादुरुस्ती झाली, ती न्यायालयात टिकली

आरक्षणाचा तिढा सोडवणे जटिल काम आहे हे मान्यच. पण आधी तो निर्माण करायचा आणि तो सुटेनासा झाला की अशा तात्पुरत्या चाली रचायच्या. हे त्याहून अधिक धोकादायक...

तरच आरक्षणासाठी ५० टक्क्यांची मर्यादा वाढू शकते. पण हे काम केंद्र सरकारचे. सध्या राज्यात व केंद्रात भाजपाची सत्ता. त्यामुळे या मार्गाने जाणे विद्यमान सरकारला केव्हाही सोयीचे. पण त्यासाठी पावले उचलताना कोणी दिसत नाही. ही पार्श्वभूमी लक्षात घेतली तर सरकारचा 'ओबीसी' आरक्षणाचा सध्याचा दावा फसवा ठरतो. मग ही फसवणूक नेमकी कशासाठी? या प्रवर्गाने केवळ निवडणुकाच लढवत राहाव्या असे सरकारला वाटते काय? बरे; हे केवळ याच राज्यात घडते आहे असेही नाही. शेजारच्या तेलंगणात तेथील काँग्रेस सरकारने 'ओबीसीं'ना तब्बल ४२ टक्के आरक्षण जाहीर केले आणि निवडणुका घेण्याची घोषणा केली. त्याला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले गेले. तेथील निवडणुकांवर स्थगिती आली. असे तोंडघशी पडण्याचे प्रयोग वारंवार करण्याची उबळ मुळात सरकारांना येतेच का? याचे उत्तर मंडल आयोगानंतर उदयास आलेल्या 'ओबीसीं'च्या एकगठ्ठा मतांमध्ये सामावलेले आहे. महाराष्ट्रापुरता विचार केला तर ही स्थिती उद्धवण्याला सरकार जेवढे जबाबदार तेवढाच सध्या 'कणाहीन' म्हणून ओळखला जाणारा राज्य निवडणूक आयोगसुद्धा! स्थानिक पातळीवरील निवडणुका घेण्याचे, ही प्रक्रिया राबवताना कायद्याचे पालन होते की नाही हे बघण्याचे काम या आयोगाचे. नगर परिषदा व पंचायतींमध्ये अनेक ठिकाणी आरक्षण मर्यादा ओलांडली जात आहे हे स्पष्टपणे दिसत असतानाही हा आयोग काय करत होता? आरक्षणाच्या सोडती काढताना मर्यादांचे पालन व्हावे असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे नमूद केले आहे. तरीही ते आदेश सर्रास धुडकावले गेले. ते नेमके कोणाच्या निर्देशावरून? आरक्षण सोडतीची सर्व माहिती मिळाल्यानंतरही हा आयोग शांत का बसला? अशा प्रश्नांची उत्तरे शोधायला गेले की हा आयोग नेमका कोणाच्या ताटाखालचे मांजर आहे हे लक्षात येते. राज्य आणि केंद्रातले सरकार हे सर्व निवडणुका एकाच वेळी घ्याव्या या संकल्पनेचे खंदे समर्थक. मग 'ओबीसीं'च्या मुद्द्यावर वारंवार निवडणुका होऊ देणे हे समर्थनीय कसे? 'ओबीसीं'ची मते मिळावीत म्हणून अशा फसव्या आरक्षणाची लालूच दाखवायची आणि सत्ता मिळाली की न्यायालयाकडे बोट दाखवून नामानिराळे व्हायचे हा खेळ किती काळ खेळला जाणार?

राज्यात १७ जिल्हे असे आहेत की जिथे विद्यमान स्थितीत ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण देता येणे केवळ अशक्य. घटनेने संमत केलेले अनुसूचित जाती/जमातीचे आरक्षण कमी करता येत नाही. हे सरकार निश्चितपणे जाणते. त्यावरील उपाय आरक्षणाची मर्यादा ओलांडणे असू शकत नाही. तरीही सरकारकडून हा मर्यादा भंगाचा प्रकार वारंवार केला जातो. याच महाराष्ट्रात २०२२ मध्ये अडीच हजारांवर ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका पार पडल्या. त्यात २७ टक्के आरक्षण नव्हते. तेव्हा कोणीही त्यावर ओरड केली नाही. कारण या निवडणुका अगदीच स्थानिक पातळीवरच्या म्हणून ओळखल्या जातात. त्यातून उडणारा प्रचाराचा धुरळा जनमत तयार करण्यासाठी उपयोगी पडत नाही. यापेक्षा जरा वरच्या पातळीवर अशी ओळख असलेल्या आणि सध्या सुरू असलेल्या निवडणुका मात्र जनमताची हवा तयार करण्यात प्रभावी भूमिका बजावू शकतात. त्यावरच डोळा ठेवून हा आरक्षणाचा घोळ घालण्यात आला. आता न्यायालयाच्या निर्देशानंतर यातून हाती काही लागणार नसले तरीही 'ओबीसीं'ना पुन्हा एकदा फसवणुकीला सामोरे जावे लागणार आहे. त्यातून बाहेर पडण्याचा एक भाग म्हणून महापालिका आणि जिल्हा परिषदेचे आरक्षण नव्याने जाहीर करावे लागेल. त्यात तरी मर्यादाभंगाला थारा नसेल अशी आशा. तरीही तो करण्याचा उद्दामपणा सरकार अथवा आयोगाने दाखवलाच तर न्यायालयाची टांगती तलवार प्रत्येक 'ओबीसीं'च्या विजयावर कायम असेल.

आरक्षणाचा तिढा सोडवणे जटिल काम आहे हे मान्यच. पण आधी तो निर्माण करायचा आणि तो सुटेनासा झाला की अशा तात्पुरत्या चाली रचायच्या. हे त्याहून अधिक धोकादायक. असे पायंडे पाडून सत्ता टिकवता येईलही; पण आरक्षणाचा ज्वर प्रत्येकाच्या मनात तापत जाईल त्याचे काय? त्यात पहिला बळी असेल तो सामाजिक सौहार्दाचा. ते २७ टक्क्यांच्या सट्ट्यात पणास लावावे काय याचा तरी विचार सरकारने करायला हवा.

लाल किल्ला

महेश सरलष्कर
mahesh.sarlashkar
@expressindia.com

हरलेल्यांना संसदेत तरी कोण किंमत देईल?

संसदेचे हिवाळी अधिवेशन आजपासून (सोमवार) सुरू होत आहे. दरवेळी अधिवेशन वादळी होणार असे सांगितले जाते पण, प्रत्यक्षात तसे काही होत नाही. याहीवेळी वादळी होण्याजोगे काही नाही. काही मुद्दे असतात, त्यावर विरोधक आक्रमक होतात. त्यांची घोषणाबाजी आणि गोंधळ खरे तर सत्ताधाऱ्यांना फायद्याचा असतो. गेल्या ११ वर्षांमध्ये सत्ताधारी 'एनडीए'ला अधिवेशन चालवावे असे वाटल्याचे दिसले नाही. विरोधकांच्या गोंधळाचे कारण देऊन चर्चाच न करण्याकडे सत्ताधाऱ्यांचा कल राहिलेला आहे. या हिवाळी अधिवेशनामध्येही हेच चित्र दिसेल. गोंधळ घालून विरोधक सभात्याग वगैरे करतात किंवा न पटणाऱ्या मुद्द्यावरून बहिष्कार टाकतात मग, दुपारच्या सत्रात सत्ताधारी हवी ती विधेयके विनाचर्चा मंजूर करून घेतात. हा मधला मार्ग दोन्ही बाजूंसाठी सोयीचा असतो. केंद्र सरकारला विरोध केल्याचे विरोधकांना दाखवता येते आणि सत्ताधाऱ्यांनाही दोन-चार मिनिटांमध्ये विधेयके मंजूर करून घेता येतात. संसदेत कोणीही स्वत:च्या डोक्याला ताप करून घेत नाही. बाकी टीव्ही मीडियासमोर संसदेच्या आवारात निदर्शने केली की, तेवढीच वातावरण निर्मिती होते. गेल्या काही वर्षांमध्ये संसदेचे कामकाज कसे चालते हे कुणा तिऱ्हाइताला समजून घ्यायचे असेल तर प्रत्यक्ष संसदेत येण्याची गरज नाही. बाहेरूनच सद्य:स्थिती समजू शकेल.

गेल्या काही वर्षांमध्ये संसदेच्या कामकाजाचा दर्जा खालावला असल्याचे सगळेच बोलतात; पण त्याला सत्ताधारी कारणीभूत आहेत तितकेच विरोधकही आहेत. काँग्रेससह विरोधकांच्या 'इंडिया' आघाडीने २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये भाजपला २४० जागांवर अडवले. ऐन राम मंदिराच्या लाटेत, त्यातही 'मोदींच्या गॅरंटी'मध्ये संघाने भाजपला धडा शिकवला आणि 'एनडीए' ३०० जागादेखील गाठू शकली नाही, मोदींनी तर '४०० पार'चा नारा दिला होता. लोकसभेच्या निकालानंतर संघाला शहाणपण सुचले, त्यांना लक्षात आले की, काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस, 'द्रमुक' वगैरे काही विरोधी पक्षांना ताकद दिली तर, डावा विचार बळकट होईल. त्यापेक्षा भाजपच बरा. त्यांना मदत करा, असे संघाने ठरवले. त्यानंतर हरियाणा, महाराष्ट्र आणि आता बिहार या तीनही राज्यांमध्ये भाजपने जबरदस्त विजय मिळवला. या विजयांतून काँग्रेसने दीड वर्षांपूर्वी निर्माण केलेली हवा भाजपने काढून घेतली. बिहारमध्ये काँग्रेसची कामगिरी पाहिल्यावर 'इंडिया' आघाडीतील घटक पक्षच काँग्रेसविरोधात बोलू लागले आहेत. काँग्रेसचे नेते राहुल गांधींची संसदेतील भाषणे दमदार होत असली तरी, बाहेर पक्षाची दुरवस्था रोखण्यात त्यांना अपयश आलेले आहे. बिहार विधानसभा निवडणूक जिंकल्यावर भाजपच्या एका नेत्याने, 'राहुल गांधींमुळे आम्ही बिहार आरामात जिंकू शकलो', अशी टिप्पणी केली. संसदेच्या बाहेर काँग्रेस सातत्याने पराभूत होत असल्यामुळे या पक्षाचे संसदेत आणि 'इंडिया' आघाडीमध्येही फारसे वजन राहिलेले नाही.

समन्वय कुठे आहे?

संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनामध्ये काँग्रेसकडून मतदार याद्यांच्या फेरआढावा मोहिमेवरून (एसआयआर) गोंधळ घातला जाईल. या मुद्द्यावर विरोधकांची एकजूट झालेली आत्ता तरी दिसत असली तरी काँग्रेसपेक्षा तृणमूल काँग्रेस अधिक आक्रमक झालेले पाहायला मिळेल. कारण पश्चिम बंगालमध्ये विधानसभेची निवडणूक होणार आहे. तिथे 'एसआयआर'चा मुद्दा पेटलेला आहे. अशा वेळी काँग्रेसपेक्षा तृणमूल काँग्रेसच्या आक्रमकपणाला जास्त महत्त्व प्राप्त होते. शिवाय, काँग्रेसच्या खासदारांपेक्षा 'तृणमूल'चे सदस्यच मोदी-शहांना न घाबरता संघर्ष करतात. कुठल्याही आघाडीत नसलेले पक्ष 'एसआयआर'च्या मुद्द्यावर 'इंडिया' आघाडीला पाठिंबा देण्याची शक्यता नाही. 'इंडिया' आघाडीतील राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार यांच्यासारखे कुंपणावर बसलेले पक्षदेखील पोटतिकडीने लढण्याची शक्यता नसते. काँग्रेस राज्या-राज्यांत पराभूत होत असल्यामुळे त्यांच्या पक्षनेत्याला तरी संसदेत किती महत्त्व देणार, असे विचारले तर चुकीचे नसेल.

बिहारची निवडणूक संपल्या संपल्या राष्ट्रीय जनता दलाचे नेते तेजस्वी यादव यांनी काँग्रेस आणि राहुल गांधींवर टीका केली. राहुल गांधींनी बिहारमध्ये 'व्होटर अधिकार यात्रा' काढून वातावरण निर्मिती केली; मग हा प्रचाराचा वेग कायम का ठेवला नाही, ऐन प्रचारामध्ये राहुल गांधी परदेशात कसे गेले, मायदेशात परत आल्यावर ते बिहारमधून गायब का झाले, जागावाटपामध्ये घोळ का केला, फक्त 'एसआयआर'च्या मुद्द्यावर निवडणूक लढवता येणार नाही हे माहीत असतानादेखील राहुल गांधींनी इतर मुद्द्यांना हात का घातला नाही, 'महागठबंधन'मध्ये समन्वय साधण्याचा प्रयत्न का झाला नाही, अखेरच्या क्षणी अशोक गेहलोत यांना पाठवून काय साधले, असे अनेक मुद्दे राष्ट्रीय जनता दलाकडून मांडले गेले. पण आता वेळ निघून गेली आहे, बिहारमध्ये भाजपने सत्तेवरील पकड घट्ट करण्यास सुरुवात केली आहे. एखादे राज्य भाजपच्या ताब्यात गेले की, ते हिसकावून घेणे कठीण काम असते. महाराष्ट्रात त्याचा अनुभव महाविकास आघाडीला आलेला आहे. महाविकास आघाडीतील घटक पक्ष आपापसांत भांडत बसले, भाजपने राज्यावर पकड घट्ट केली, आता महाराष्ट्र भाजपकडून परत मिळवणे विरोधकांना नजीकच्या काळात तरी शक्य होईल असे दिसत नाही. दोन्ही शिवसेना, दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्यामध्ये वेगवेगळ्या युत्या-आघाड्या होतील, त्या मोडतील वा पुन्हा नव्याने होतील. पण त्यांचे राजकारण भाजपच्या अवतीभोवती राहील. त्याचा भाजपवर काहीही परिणाम होण्याची शक्यता नाही. हीच बाब केंद्रातही लागू पडते.

बिहारमध्ये काँग्रेससह आघाडी करून राष्ट्रीय जनता दलाला काही मिळाले नाही. उत्तर प्रदेशात २०२२ मध्ये अखिलेश यादव यांच्या समाजवादी पक्षाचेही तेच झाले होते. पश्चिम बंगालमध्ये तर तृणमूल काँग्रेसने काँग्रेसला गृहीतदेखील धरलेले नाही. सत्ता टिकवण्यासाठी आम्हाला काँग्रेसची गरज नाही असे ममता बॅनर्जींनी गेल्या विधानसभा निवडणुकीतही सांगितले होते. त्यामुळे काँग्रेसने डाव्या पक्षांशी युती केली. या पक्षांना पश्चिम बंगालमध्ये कोणी विचारत नाही हेही यातून दिसतेच. नाराज डावे आधी तृणमूल काँग्रेसकडे गेले, ममतांवर नाराज होऊन ते भाजपकडे गेले. पण काँग्रेसकडे कोणी फिरकत नाही हे स्पष्टच दिसते. या वेळी पश्चिम बंगालमध्ये बहुधा पुन्हा तृणमूल काँग्रेसची सत्ता येईल, असे बोलले जाते. भाजपलाही पश्चिम बंगाल काबीज करू असा आत्मविश्वास नाही. भाजपचे नेते तसे खासगी गप्पांमध्ये बोलून दाखवतात. पश्चिम बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेसला काँग्रेसची गरज नाही. उत्तर प्रदेशात समाजवादी पक्षाचा काँग्रेसवर भरवसा राहिलेला नाही. बिहारमध्ये काय झाले हे लालूंच्या पक्षाने पाहिले आहे. महाराष्ट्रात महाविकास आघाडी मोडून पडली आहे आणि काँग्रेसला संघटना मजबूत करण्याची पूर्ण संधी असली तरी तसे अजून तरी होताना दिसत नाही. मग, 'इंडिया' आघाडीमधील घटक पक्षांतच काँग्रेसबद्दल नाराजी असेल तर आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही!

पारा यथातथाच

संसद अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला पुन्हा एकदा 'नॅशनल हेराल्ड' घोटाळा प्रकरण उकरून काढण्यात आलेले आहे. हे प्रकरण गांधी कुटुंबीयांची कोंडी करण्यासाठी हव्या त्या वेळेला वापरले जाते. विरोधकांकडे चर्चेसाठी एखादा मुद्दा असेल तर त्याला प्रत्युत्तर देण्यासाठी अशी 'नॅशनल हेराल्ड'सारखी प्रकरणे भाजपला उपयोगी पडत असतात. संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनामध्ये या कथित घोटाळ्यावरून राहुल गांधींना लक्ष्य केले जाण्याची शक्यता दिसू लागली आहे. 'वंदे मातरम'वर चर्चा झाली तर काँग्रेसला भाजपच्या 'राष्ट्रवादा'त सूर मिसळावे लागतील. काँग्रेसने हे गीत स्वीकारले होते आणि स्वातंत्र्यानंतर काँग्रेसच्या सरकारने 'जन गण मन'ला राष्ट्रगीताचा, तर 'वंदे मातरम'ला राष्ट्रीय गीताचा दर्जा दिला होता. त्यामुळे 'वंदे मातरम'विरोधात काँग्रेसला बोलता येणार नाही. इथे काँग्रेसने 'सेक्युलॅरिझम'चा मुद्दा काढला तरी बिहारच्या निवडणुकीतील पराभवानंतर तो किती बोथट झालेला आहे हे दिसले. लोकसभा निवडणुकीमध्ये मुस्लीम मतदारांचा काँग्रेसवर भरवसा होता, बिहारच्या निवडणुकीतील पराभवानंतर हे मतदार तरी काँग्रेसबरोबर राहतील याची खात्री देता येत नाही. संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाचा पहिला आठवडा गोंधळाने भरलेला असेल. बाकी दोन आठवड्यांमध्ये सत्ताधारी विनाचर्चा विधेयके संमत करून घेईल. तसेही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सभागृहांमध्ये येत नाहीत, त्यांना बोलायचे असेल तेव्हा ते सभागृहांकडे फिरकतात. सभागृहांत एखाद्या महत्त्वाच्या विषयावर चर्चा होणार असेल तरीही मोदींना सभागृहात बसून ऐकण्याची इच्छा नसते. त्याला हिवाळी अधिवेशन अपवाद ठरण्याची शक्यता कमीच. हे पाहता 'एसआयआर'सारखा एखादा मुद्दा वगळता संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या कामकाजाचा पारा फार वर जाईल असे दिसत नाही.

'एसआयआर' मुद्द्यावर विरोधकांची एकजूट झालेली आत्ता तरी दिसत असली तरी काँग्रेसपेक्षा तृणमूल काँग्रेस अधिक आक्रमक झालेले पाहायला मिळेल. पण हा गोंधळ होत असताना सत्ताधारी नेहमीप्रमाणे, अनेक विधेयके चर्चेविना मंजूर करवून घेतील...

अन्वयार्थ

'बंदी केंद्रां'ची संस्कृती!

भाजपची प्रयोगशाळा ठरलेल्या उत्तर प्रदेश आणि आसाम या दोन राज्यांमध्ये लोकशाहीची नवीच संस्कृती उदयाला येत असल्याचे संकेत तेथील उच्चपदस्थांच्या विधानांवरून मिळत आहेत. उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी वरिष्ठ सनदी आणि पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत राज्यातील घुसखोरांचा बंदोबस्त करण्याचा आदेश देताना, गेल्या आठवड्यात या घुसखोरांसाठी राज्याच्या सर्व ७५ जिल्ह्यांत बंदी केंद्रे उभारण्याची सूचना केली. आसाममध्ये तर, विधानसभेत गोंधळ घातल्याच्या कारणास्तव निलंबित होणाऱ्या आमदारांसाठी विधान भवनाच्या आवारात बंदी केंद्र उभारावे, अशी मागणी सत्ताधारी भाजपच्या एका मंत्र्यांनीच केली आणि विधानसभा अध्यक्षांनीही लगेच या प्रस्तावावर विचार करण्याचे जाहीर केले. 'विधिमंडळ सचिवालयाने नियमात तरतूद केल्यावर असे बंदी केंद्र सुरू केले जाईल', असेही विधानसभा अध्यक्षांनी स्पष्ट केले. घुसखोरांसाठी प्रतीक्षा छावण्यांऐवजी 'बंदी केंद्रे' (डिटेन्शन सेंटर) उभारण्याची सुरुवात २०१५ पासून झालेलीच आहे. पण सभागृहात गोंधळ घातला म्हणून आमदाराला बंदिवान करणे हे अधिकच गंभीर. सभागृहात आणि बाहेरही आमदारांनी सरकारच्या विरोधात काहीही बोलू नये, आरोप करू नये, अशीच एकूण व्यवस्था आसाममधील भाजप सरकारकडून निर्माण केली जात आहे. असे निलंबित झालेले आमदार बाहेर जाऊन चुकीची माहिती पसरवतात, म्हणून निलंबित आमदारांना बंदी केंद्रात बसवून ठेवावे व तेथे त्यांच्या चहापाण्याची व्यवस्था करावी, अशी बिनडोक सूचना आसामच्या सांस्कृतिक कार्यमंत्र्यांची. तेथील विधानसभेचे अध्यक्ष त्याहून महान. त्यांनी ही सूचना कसकशी अमलात येईल, हेही विनाविलंब सांगितले.

आसाममध्ये हा पायंडा पडल्यास अन्य भाजपशासित राज्ये विरोधी आमदारांच्या मुसक्या आवळण्यासाठी त्याचे अनुकरण केल्याशिवाय राहणार नाहीत. विरोधी आमदारांचा आवाज बंद करण्याचा भाजप सरकारचा डाव असल्याचा आसाम काँग्रसच्या विधिमंडळ नेत्याने केलेल्या आरोपांत नक्कीच तथ्य आहे. तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी घोषित केलेल्या आणीबाणीबद्दल भाजपचे नेते ऊठसूट गळे काढत असतात. तेव्हा लोकशाहीरवर घाला घालण्यात आला होता, हे ज्या भाजपला समजते त्याच भाजपच्या आसाम सरकारने विरोधी आमदारांनी सभागृहात गोंधळ घातला म्हणून त्यांना काही तासदेखील डांबून ठेवणे हे लोकशाहीशी कितपत सुसंगत ठरेल, यावर भाजपच्या अधिकृत भूमिकेची नक्कीच साऱ्यांना उत्सुकता असेल. काँग्रेसमध्ये २००१ ते २०१५ पर्यंत आमदारकीच नव्हे तर मंत्रीपदेही भोगून आता भाजपची सेवा करणारे मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व सरमा यांच्या वर्तनाबद्दल न बोललेलेच बरे. गुजरातमधील काँग्रेस आमदाराने पंतप्रधान मोदी यांच्या विरोधात ट्वीट केले म्हणून आसाम भाजपच्या कुणा पदाधिकाऱ्याने तक्रार करताच आसाम पोलिसांनी गुजरातमध्ये जाऊन मध्यरात्री आमदाराला घरातून अटक केली होती. ही कारवाई गुजरात पोलिसांनी करणे एकवेळ ठीक. पण अहमदाबादपासून अडीच हजार किमी अंतरावरील आसाम पोलिसांचा याच्याशी संबंध काय? भाजपच्या दिल्लीतील धुरिणांपुढे राजनिष्ठा दाखवण्यासाठी सरमा यांचा हा उद्दामपणा. पक्षपातीपणाचा आरोप होताच घटनात्मक पदावरील व्यक्तीने धर्मनिरपेक्ष असावे, सर्वांना समान न्याय द्यावा, ही घटनेतील अपेक्षा खुंटीला टांगून 'हो, मी एक बाजू घेतो', अशी चिथावणीखोर विधाने या मुख्यमंत्र्यांकडून केली जातात. मतांचे ध्रुवीकरण करून सत्ता कशी ताब्यात ठेवता येईल एवढेच त्यांचे ध्येय. याच सरमा यांच्या एका सहकाऱ्याने विरोधी आमदारांचा आवाज दडपण्यासाठी त्यांना थेट बंदी केंद्रात पाठवण्याचे नवे 'सांस्कृतिक कार्य' हाती घेतले आहे.

उत्तर प्रदेशात घुसखोरांच्या विरोधात कारवाई करताना राज्यातील सर्व जिल्ह्यांत बंदी केंद्रे उघडण्याचा आदेश व पोलीस अधीक्षक व जिल्हाधिकाऱ्यांना अलीकडेच देणारे योगी आदित्यनाथ हे मुख्यमंत्रीपदी गेली आठ वर्षे (२०१७ पासून) आहेत. गोमांसाच्या नुसत्या संशयावरून जिथे लोकच कायदा हातात घेतात, अशा राज्यांतल्या सर्व ७५ जिल्ह्यांमध्ये घुसखोर गेली आठ-आठ वर्षे सुखेनैव नांदत होते की सध्या 'मतदार याद्यांची विशेष फेरतपासणी' (एसआयआर) उत्तर प्रदेशातही सुरू असल्यामुळे घुसखोरांची आठवण योगींना झाली? त्यांनी इतक्या वर्षांत घुसखोरांना शोधून त्यांच्या विरोधात कारवाई का केली नाही, असे अनेक प्रश्न उपस्थित होतात. लोकसभा निवडणुकीत उत्तर प्रदेशात भाजपला मोठा फटका बसला. अगदी मोदींचे वाराणसीत मताधिक्य घटले. २०२७ मध्ये विधानसभा निवडणुकीत सत्ता राखण्यासाठी आतापासून मतांच्या ध्रुवीकरणाचा योगींचा प्रयत्न दिसतो.

भाजपची ही 'बंदी केंद्रा'ची नवी संस्कृती देशभर सर्वत्र उदयाला आल्यास आश्चर्य नाही. महाराष्ट्रात तर देवेंद्र फडणवीस हे अन्य भाजपशासित राज्यांच्या प्रयोगांची लगोलग यशस्वी कॉपी करण्यासाठी प्रसिद्ध. ही बंदी संस्कृती म्हणजे अघोषित आणीबाणीकडे वाटचाल असेच त्याचे वर्णन करता येईल.

विश्लेषण

हर्षद कशाळकर
harshad. kashalkar@
expressindia. com

कोकणातील 'माकड पकड मोहिमे'ने बागायतींमधील उपद्रव थांबेल?

कोकणातील आंबा बागायती, शेतीपिके, फळबागा, फुले आदींची नासधूस करणारे वानर आणि माकडे यांना पकडण्यास अधिकृत मान्यता देणारे धोरण २५ नोव्हेंबरला राज्य शासनाने जाहीर केले आहे. यासाठी अनुदानही दिले जाणार आहे....

राज्य सरकारचा निर्णय काय?

कोकणात आंबा, काजू, केळी, कोकम, चिकू बागायतीचे त्याचबरोबर फळबागा आणि शेतीचे वन्यप्राण्यांकडून प्रामुख्याने माकड आणि वानरांकडून मोठे नुकसान केले जाते. शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान करणाऱ्या या उपद्रवी माकडे आणि वानरांना आवर घालण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. 'माकड पकडा आणि सहाशे रुपये मिळवा' असे या योजनेचे स्वरूप आहे. माकड आणि मानव यांच्यातील संघर्ष रोखणे, माकडांचा उपद्रव कमी करणे आणि नागरिकांना या मोहिमेत सहभागी करून घेणे हा या योजनेमागचा उद्देश आहे.

माकडांचा उपद्रव किती?

पुण्याच्या गोखले इन्स्टिट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स अँण्ड इकॉनॉमिक्स या संस्थेने २०२४-२५ मध्ये केलेल्या सर्वेक्षणात दरवर्षी महाराष्ट्रात वन्यप्राण्यांच्या उपद्रवामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांचे साधारणपणे १० ते ४० हजार कोटींचे नुकसान होत असल्याचे समोर आले होते. यात प्रामुख्याने रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील बागायतींना वानरांच्या उपद्रवाचा सर्वाधिक फटका बसत असल्याचे दिसून आले आहे.

उच्छाद अलीकडेच का वाढला?

जंगलामधील माकडाची वाढती संख्या, आहारस्रोतांचा अभाव, कोकणात जंगलांना वारंवार लागणारे वणवे यामुळे माकडांच्या आणि वानरांच्या स्थलांतराचे प्रमाण वाढले आहे. एकाच वेळी ४० ते ५० वानरांची झुंड बागायतीमध्ये दाखल होऊन पिके, फळे यांची नासधूस करते. अन्नाच्या शोधात ही माकडे आणि वानरे लगतच्या गावांमध्ये प्रवेश करतात. नागरी आणि शहरी भागातील कचऱ्यात अन्नघटक सहज उपलब्ध होतात. शहरांतही माकडांचे स्थलांतर मोठ्या प्रमाणात होते आहे.

माकड पकड योजना कशी?

या योजनेनुसार माकड-वानर पकडण्याचा अनुभव असणाऱ्यांना प्रोत्साहनपर मानधनाच्या आधारावर नियुक्त करण्यात येणार आहे. उपद्रवी माकड जेरबंद करून सुरक्षितपणे नैसर्गिक अधिवासात सोडले जाणार आहे. दहा उपद्रवी माकडे पकडणाऱ्या व्यक्तीला प्रत्येक माकडामागे ६०० रुपये मिळतील; पण दहापेक्षा अधिक माकडे पकडल्यास प्रत्येक माकडमागे ३०० रुपये दिले जातील. माकड पकडणाऱ्या प्रशिक्षित व्यक्तीला एक हजार रुपये प्रवास भत्ता अनुज्ञेय राहील. पण कोणाही व्यक्तीला यातून दहा हजार रु.पेक्षा अधिक रक्कम दिली जाणार नाही.

योजनेतील मर्यादा कोणत्या?

प्रत्येक माकड पकडताना त्याचे व्हिडीओ चित्रीकरण करावे लागेल. पकडलेल्या प्रत्येक माकडाचा- वानराचा फोटो काढावा लागेल. माकड पकडल्यावर त्याच्यावर आवश्यक उपचारानंतर मानवी वस्तीपासून शक्यतो १० किमीपेक्षा अधिक अंतरावरील वनक्षेत्रात सोडावे लागेल. माकड जंगलात सोडल्यावर मुक्तता प्रमाणपत्र तयार करून त्यावर वन अधिकारी आणि माकड पकडणाऱ्याची सही असेल. माकड पकडणारी व्यक्ती जखमी झाल्यास वन विभाग कोणतीही जबाबदारी घेणार नाही. माकड पकडण्यासाठी जाळी आणि पिंजरे यासारखी सुरक्षित साधने वापरावी लागणार आहेत. हा खर्चही माकड पकडणाऱ्यांना करावा लागणार आहे. त्यामुळे माकडे पकडणे आव्हानात्मक ठरू शकेल.

यापूर्वी घेतलेल्या निर्णयांचे काय झाले?

माकडामुळे होणारे नुकसान लक्षात घेऊन या माकडांचा तसेच वानरांचा बंदोबस्त करण्याची मागणी सातत्याने केली गेली आहे. यापूर्वी शासनाने हा उपद्रव लक्षात घेऊन नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत देण्याची घोषणा केली होती. मात्र केवळ एक ते दोन टक्के शेतकऱ्यांपर्यंत ही मदत पोहोचत असल्याचे अभ्यासात उघड झाले. कोकणातील माकडांचा उपद्रव टाळण्यासाठी माकडांच्या नसबंदीचा प्रस्ताव तयार करून तो शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठवण्यात आला; मात्र मागील दोन वर्षांपासून त्यावर अंतिम निर्णय झालेला नाही. मानव-वानर संघर्ष वाढत आहे. यावर तोडगा म्हणून वन विभागाने आता माकडे पकडण्यासाठी आणि नंतर त्यांना नैसर्गिक अधिवासात सोडण्यासाठी कार्यप्रणाली निश्चित केली आहे. पण एकूण परिस्थिती लक्षात घेतली तर माकडे पकडणे हे आव्हानात्मक काम असल्याने या नव्या निर्णयाचाही प्रत्यक्ष लाभ कितपत होईल, याबाबत बागायतदार साशंक आहेत.

रिकॉर्ड वृद्धि दर

सरकार की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक, भारतीय अर्थव्यवस्था ने जुलाई-सितंबर की दूसरी तिमाही में 8.2 प्रतिशत की वृद्धि दर हासिल की, जो पिछली छह तिमाहियों का उच्चतम स्तर है. पिछले वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर 5.6 प्रतिशत, जबकि मौजूदा वित्त वर्ष की पहली तिमाही में वृद्धि दर 7.8 फीसदी थी. इस वृद्धि के साथ भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है. यह आंकड़ा न केवल अर्थशास्त्रियों के पूर्वानुमानों से काफी अधिक है, बल्कि अनिश्चित भू-राजनीतिक स्थिति के बीच भारत की आर्थिक वृद्धि विश्व मंच पर उसकी प्रभावी उपस्थिति बनाये रखने के लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण है. गौरतलब है कि बजट से पहले पेश की गयी आर्थिक समीक्षा में 2025-26 में वास्तविक आर्थिक विकास दर 6.3 प्रतिशत से से 6.8 फीसदी रहने का अनुमान लगाया गया था. लेकिन दूसरी तिमाही के आंकड़ों ने इस अनुमान को पीछे छोड़ दिया है. इस आर्थिक वृद्धि को गांवों की मजबूत अर्थव्यवस्था, सरकारी खर्च में बढ़ोतरी और निर्यात की जल्दी हुई शिपमेंट से सहारा मिला. हालांकि शहरी मांग और निजी निवेश अब भी धीमे बने हुए हैं. उल्लेखनीय है कि वैश्विक व्यापार में अनिश्चितता और अमेरिका द्वारा लगाये गये भारी टैरिफ के बावजूद निर्यात में अच्छी वृद्धि दर्ज हुई है. दूसरी तिमाही में मैन्युफैक्चरिंग या विनिर्माण, वित्तीय, रियल एस्टेट और पेशेवर सेवाओं के क्षेत्र में भारी वृद्धि दर्ज हुई. इस दौरान मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र 9.1 फीसदी की दर से बढ़ा. वृद्धि दर के आंकड़ों से उत्साहित मुख्य आर्थिक सलाहकार ने विश्वास जताया है कि इस वित्त वर्ष में देश की आर्थिक विकास दर सात फीसदी के आंकड़े को पार कर जायेगी और भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार चार ट्रिलियन डॉलर के ऐतिहासिक स्तर को छू लेगा. मौजूदा वित्त वर्ष की पहली छमाही में जीडीपी की वास्तविक वृद्धि दर आठ प्रतिशत रही है. वहीं अप्रैल से अक्तूबर के बीच-यानी इस वित्त वर्ष के शुरुआती सात महीनों में राजकोषीय घाटा वार्षिक अनुमानों का 52.6 फीसदी रहा, जो पिछले वर्ष की समान अवधि के 46.5 प्रतिशत से अधिक है. सरकार ने राजकोषीय घाटे का लक्ष्य जीडीपी का 4.4 फीसदी रखा है. पिछले वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.8 प्रतिशत था. हालांकि जीडीपी में शानदार वृद्धि से रिजर्व बैंक महंगाई को नियंत्रित करने के लिए ब्याज दरों को स्थिर रख सकता है.

मौजूदा वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में जीडीपी की वृद्धि दर 8.2 फीसदी रही, जो पिछली छह तिमाहियों का उच्चतम स्तर है. इस वृद्धि दर को गांवों की मजबूत अर्थव्यवस्था, सरकारी खर्च में वृद्धि और निर्यात से सहारा मिला.

कर्नाटक के कलह में भारी पड़े सिद्धरमैया

रशीद किदवई
वरिष्ठ पत्रकार
rasheedkidwai@gmail.com

कई कारणों से कर्नाटक में सिद्धरमैया कांग्रेस के लिए अपरिहार्य नेता बने हुए हैं. इसलिए यह तो तय है कि उनकी मर्जी के बगैर उन्हें पद से नहीं हटाया जा सकता. ऐसे में, डीके शिवकुमार के पास प्रतीक्षा करने के सिवाय और कोई चारा नहीं है. फिर शिवकुमार की गांधी परिवार के प्रति वफादारी भी मुख्यमंत्री बनने की राह में आड़े आ रही है. इसलिए उनसे कहा जा रहा है कि उन्हें फिलहाल के लिए अपनी महत्वाकांक्षाओं को किनारे करना होगा और 2028 के राज्य विधानसभा चुनाव तक रुकना होगा.

शनिवार की सुबह कर्नाटक की राजनीति शीर्षासन की स्थिति में थी. एक दिन पहले तक कांग्रेस के आसमान में संकट के जो काले-काले बादल नजर आ रहे थे, वहां अब शांति के सफेद कपोत उड़ रहे थे. मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने मुख्यमंत्री आवास में साथ बैठकर नाश्ता किया और फिर पत्रकारों के सवालों के जवाब देकर मानो खुद को ही आश्वस्त करना चाहा कि उनकी पार्टी में चहुंओर 'शांति' है. तो क्या सप्ताह भर पहले तक ढाई-ढाई साल के कथित फॉर्मूले के आधार पर मुख्यमंत्री की कुर्सी की मांग से डीके शिवकुमार पीछे हट गये हैं? फिलहाल लगता तो ऐसा ही है. इस बात को मानने की कई ठोस वजहें भी हैं. इसका एक कारण तो जातिगत समीकरण ही है. सिद्धरमैया दरअसल पिछड़ी जाति से आते हैं, जबकि डीके शिवकुमार अगड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं. कांग्रेस के कुल जमा तीन राज्यों में से दो अन्य में पहले से ही अगड़ी जाति के मुख्यमंत्री विराजमान हैं. ऐसे में कांग्रेस हाईकमान इस स्थिति में बिल्कुल नहीं है कि वह सिद्धरमैया को हटाकर उनकी जगह डीके शिवकुमार को कर्नाटक का मुख्यमंत्री बना दे, क्योंकि इससे पिछड़ों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने की राहुल गांधी की राजनीति कमजोर पड़ती है.

अलबत्ता, यह बात भी स्वीकार करनी होगी कि सिद्धरमैया को मुख्यमंत्री पद से न हटाये जाने की एक बड़ी वजह उनकी स्वयं की शख्सियत और जमीनी सियासत है. इसमें भला क्या संदेह कि धन-जायदाद से संपन्न डीके शिवकुमार के आर्थिक संसाधनों का कांग्रेस पिछले कई चुनावों से भरपूर उपयोग करते आ रही है और इस वजह से पार्टी उनके आर्थिक एहसानों के तले दबी हुई भी है. लेकिन यह भी ध्यान रखना चाहिए कि सिद्धरमैया की गिनती कांग्रेस के दरबारी राजनेताओं में नहीं होती है. वह जनता पार्टी और फिर जनता दल से जमीनी और सधी हुई राजनीति करके कांग्रेस में आये हैं. इसलिए वह न डीके शिवकुमार हैं, न अशोक गहलोत और न ही कमलनाथ. यही कारण है कि सिद्धरमैया को कभी दिल्ली तलब नहीं किया जाता. पिछले ढाई साल में यह देखने में आया है कि जब उन्हें प्रधानमंत्री से मिलना होता है या फिर नीति आयोग की बैठक में शामिल होना होता है, सिर्फ तभी वह दिल्ली आते हैं और केवल औपचारिकतावश कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे से मिलते हैं या कभी नहीं भी मिलते हैं. दूसरे पार्टी क्षत्रपों की तरह राहुल गांधी से मिलने के लिए भी वह कोई बहुत ज्यादा आतुर नहीं रहते. सिद्धरमैया की यही सियासी दबंगई उन्हें कर्नाटक में अपनी पार्टी से इतर अपना स्वयं का कल्ट बनाने में मदद करती है.

इसके अतिरिक्त कांग्रेस के विधायकों के बीच भी सिद्धरमैया की पकड़ बेहद मजबूत है. अगर विधायकों के बीच रायशुमारी करवायी जाये, जो 2023 में भी नहीं करवायी गयी थी, तो सिद्धरमैया अपने प्रतिद्वंद्वी से कहीं आगे नजर आयेंगे. लोकप्रियता के मानकों पर भी वह कांग्रेस के लिए एक अपरिहार्य नेता बने हुए हैं. इसलिए यह तो तय है कि सिद्धरमैया की मर्जी के बगैर उन्हें उनके पद से नहीं हटाया जा सकता और शायद इसीलिए डीके शिवकुमार के पास प्रतीक्षा करने के सिवाय और कोई चारा नहीं है. फिर शिवकुमार की गांधी परिवार के प्रति वफादारी भी मुख्यमंत्री बनने की राह में आड़े आ रही है, जो यह कह चुके हैं कि वह 2029 में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं. इसलिए उनसे कहा जा रहा है कि अगर वह राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के पद पर देखने के आकांक्षी हैं, तो फिर उन्हें फिलहाल के लिए अपनी महत्वाकांक्षाओं को किनारे करना होगा और 2028 के राज्य विधानसभा चुनाव तक रुकना होगा. इस समय यह सवाल भी पूछा जा रहा है, और कांग्रेस के कुछ हलकों में यह स्वाभाविक आशंका भी है कि जो स्थिति बन रही है, उसमें शिवकुमार कांग्रेस के लिए कहीं दूसरे ज्योतिरादित्य सिंधिया या हिमंता विस्वा सरमा तो नहीं बन जायेंगे? यह तथ्य है कि शिवकुमार से विपक्ष के अनेक नेता संपर्क में हैं. लेकिन उनके बारे में यह कहा जाता है कि उनका गांधी परिवार से एक पर्सनल रैपो रहा है. प्रियंका तो उन्हें मुख्यमंत्री बनाने के पक्ष में ही हैं. ऐसे में वह कांग्रेस से तुरंत कोई बगावत करेंगे, इस बात की आशंका कम ही है. एक फॉर्मूला यह सामने आ रहा है कि कांग्रेस हाईकमान, और उसमें भी खुद सोनिया गांधी सिद्धरमैया से यह कहें कि वह राज्य का बजट प्रस्तुत करने तक मुख्यमंत्री के पद पर रहें और इसके बाद स्वेच्छा से कुर्सी छोड़ दें. फिर उनकी जगह शिवकुमार को मुख्यमंत्री बनाया जाये. लेकिन कर्नाटक में कांग्रेस के साथ एक समस्या यह भी है कि जहां अन्य कई राज्यों में पार्टी के पास क्षेत्रीय क्षत्रपों का अकाल है, वहीं कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद के दावेदारों की कतार लगी है. सिद्धरमैया के मुख्यमंत्री पद से हटने की स्थिति में राज्य के गृह मंत्री जी परमेश्वर सहित कई लोग मुख्यमंत्री पद पर दावा करने के लिए तैयार बैठे हैं. कहा तो यह भी जा रहा है कि मौका मिलने पर स्वयं मल्लिकार्जुन खरगे भी मुख्यमंत्री पद लेना चाहेंगे. कर्नाटक का मुख्यमंत्री न बन पाने की कसक वह जब-तब व्यक्त कर चुके हैं.

देखा जाये, तो इस पूरी समस्या की जड़ में है गांधी परिवार का अपने रणनीतिकारों पर हद से ज्यादा आश्रित रहना. सोनिया गांधी की कामयाबी में बड़ी भूमिका अहमद पटेल ने निभायी थी. लेकिन अगर आज राहुल गांधी विफल हो रहे हैं, तो यह उनके रणनीतिकारों केसी वेणुगोपाल और रणदीप सुरजेवाला की भी विफलता है. राहुल गांधी के साथ दिक्कत यह है कि वह वेणुगोपाल या रणदीप सुरजेवाला की लगातार नाकामयाबियों के बाद भी उन्हें ढोये जा रहे हैं. इंदिरा और राहुल गांधी में दरअसल यही बुनियादी अंतर है. इंदिरा गांधी न केवल अपने रणनीतिकारों में समय-समय पर फेरबदल किया करती थीं, बल्कि वह उनकी जवाबदेही भी तय किया करती थीं. किंतु राहुल गांधी के किसी भी मैनेजर की कोई जवाबदेही नहीं है और बार-बार की चुनावी विफलताओं के बाद भी वे अपने पदों पर जमे हुए हैं. इसका परिणाम यह है कि पार्टी नेताओं में आत्मसमीक्षा और पुनर्गठन की संस्कृति लगभग लुप्त हो चुकी है. ऐसा संभवतः पहली बार ही हुआ है कि बिहार की इतनी बड़ी चुनावी हार के बाद भी नतीजों की समीक्षा के लिए कोई कमेटी तक गठित नहीं की गयी है और पराजय का पूरा जिम्मा चुनाव आयोग के मत्थे डाल दिया गया है.

(ये लेखक के निजी विचार हैं.)

महिला क्रिकेट में नये युग की शुरुआत

अभिषेक दुबे
वरिष्ठ पत्रकार
abhishekdubey1975@gmail.com

विमेंस प्रीमियर लीग के लिए हुई नीलामी में भारतीय महिला क्रिकेटरों की प्रतिभा की छाप स्पष्ट दिखी. देश में महिला क्रिकेट का परिदृश्य पूरी तरह से बदल चुका है. अब महिलाएं भारतीय क्रिकेट की चीयर लीडर नहीं, असली लीडर हैं.

अपने देश की जो महिलाएं घरों की रीढ़ थीं, अब वे पूरे देश में हो रहे बदलाव की धुरी बनकर सामने आ रही है. एक तरफ वे राज्य दर राज्य चुनावी नतीजों में निर्णायक भूमिका निभा रही हैं, फाइटर जेट चलाने से लेकर इसरो में बड़ी भूमिका को अंजाम दे रही हैं, वहीं खेल के मैदान में भारतीय विकास की कहानी का इंजन बनकर सामने आ रही हैं. ओलिंपिक खेलों में तो भारतीय महिलाएं पहले से ही बदलाव का नेतृत्व कर रही थीं, लेकिन राष्ट्रीय क्रिकेट में उनकी भूमिका अब तक बहुत महत्वपूर्ण नहीं थी. यह सच है कि क्रिकेट को भारत के खेलों में लगभग धर्म का दर्जा मिला है, लेकिन बीते पांच साल तक भी इस खेल में महिलाएं लगभग हाशिये पर थीं. अलबत्ता वर्ष 2025 ने यह तस्वीर पूरी तरह बदल कर रख दी.

खेलों के इतिहास पर अगर नजर दौड़ायें, तो हर क्रांतिकारी बदलाव के पीछे एक सूत्रधार होता है. आने वाले समय में जब भारत में महिला क्रिकेट में आये बदलाव पर चर्चा होगी, तो जय शाह को इसके सूत्रधार के तौर पर याद किया जायेगा. जय शाह जब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के महासचिव थे, तब उन्होंने दो बड़े कदम उठाये थे, जिसने भारतीय महिला क्रिकेट में आमूलचूल बदलाव ला दिया. पहला, उन्होंने महिला क्रिकेट में पुरुष क्रिकेट के बराबर वेतन लाने का काम किया. और दूसरा, उन्होंने इंडियन प्रीमियर लीग की तर्ज पर विमेंस प्रीमियर लीग को अमली जामा पहनाने का काम किया. इन दोनों का नतीजा हाल ही में दिखा, जब भारतीय महिला टीम ने विश्व कप का खिताब जीता. भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के लिए 1983 विश्व कप और 2007 में टी-20 वर्ल्ड कप की जीत जितनी विराट उपलब्धि थी, भारतीय महिला क्रिकेट टीम के लिए इस साल विश्व कप में विजय उतनी ही बड़ी उपलब्धि रही है. इसका साफ असर इसके ठीक बाद विमेंस प्रीमियर लीग के लिए हुई नीलामी में दिखायी पड़ा. यह कहना तो खैर बेमानी होगा कि विमेंस प्रीमियर लीग की नीलामी का स्तर आंकड़ों और रणनीति के आधार पर इंडियन प्रीमियर लीग के बराबर हो चुका है, लेकिन इस साल की नीलामी से यह स्पष्ट है कि विमेंस प्रीमियर लीग बड़ी तेजी से उस ओर अग्रसर है. इस नीलामी में 73 रिक्त स्थानों के लिए 277 खिलाड़ियों का पूल था, जिनमें 194 भारतीय और 83 विदेशी महिला क्रिकेटर शामिल थीं. जाहिरा तौर पर अब भारतीय खिलाड़ियों का टैलेंट पूल बड़ा होता जा रहा है और फ्रेंचाइजी उन पर अधिक भरोसा भी दिखा रहे हैं.

विश्व कप में भारत की और से दमदार प्रदर्शन करने वाली ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा 3.2 करोड़ रुपये की रिकॉर्ड राशि में बिकीं. दूसरी ओर, ऑस्ट्रेलिया की सुपरस्टार एलिसा हेली का कोई खरीदार नहीं मिला. मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स ने इस नीलामी में सबसे कम बजट के साथ एंट्री की, लेकिन ये दोनों सबसे मजबूत टीम के साथ ऑक्शन रूम से बाहर निकले. मुंबई इंडियंस ने अपनी पहचान के हिसाब से पूरा जोर अपने अहम खिलाड़ियों को दोबारा अपने कुनबे में शामिल करने पर लगाया. मुंबई इंडियंस ने जब एमिलिया केर को टीम में नहीं बनाये रखा था, तब उसकी काफी चर्चा हुई थी. लेकिन जैसे ही वह ऑक्शन टेबल पर आयीं, मुंबई इंडियंस ने उन्हें तीन करोड़ की बड़ी राशि देकर खरीदा. मुंबई इंडियंस ने इसी तरह सजीवन साजना, शाबनीम इस्माइल और साइका इशाक को अपनी टीम में दोबारा शामिल किया. इन तीनों की ही मुंबई इंडियंस की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका रही थी. इसके अलावा मुंबई इंडियंस ने निकोला कैरी को शामिल कर अपनी टीम को और मजबूती दी. दिल्ली कैपिटल्स ने अपना पूरा दांव वुल्वार्ट, श्री चरनी और चिनले हेनरी पर लगाया. ये तीनों विश्व कप की महत्वपूर्ण खिलाड़ी थीं. दिल्ली कैपिटल्स के दांव को देखकर लगता है कि वुल्वार्ट या फिर जेमिमा रोड्रिग्स में से किसी एक पर कप्तानी का जिम्मा होगा.

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने नीलामी में जोर अपनी बल्लेबाजी दमखम को बढ़ाने में लगाया. टीम ने ग्रेस हैरिस, जॉर्जिया वॉल और नदीन डी क्लर्क को खरीदकर अपनी रणनीति जाहिर कर दी. टीम के पास वस्त्राकर, लॉरेन बेल और अरुंधती रेड्डी के रूप में जबरदस्त पेस बैटरी है. इस टीम की स्पिन गेंदबाजी की कमान राधा यादव और लिंसी स्मिथ के हाथों में होगी. अगर हम यूपी वारियर्स की बात करें, तो भले ही ऑक्शन रूम में वह सबसे अधिक सक्रिय दिखे, लेकिन टीम के संतुलन को देखकर उन्हें निराशा ही होगी. मेग लैनिंग और दीप्ति शर्मा में से कोई एक इस टीम की अगुवाई करेंगी, लेकिन टीम को विजेता बनाने के लिए जाहिर है, उन्हें खासी मशक्कत करनी होगी. इसी तरह गुजरात टाइटन्स को भी वह टीम नहीं मिली, जिसे वह जिताऊ कह सके. विमेंस प्रीमियर लीग का अगला विजेता चाहे जो भी टीम हो, लेकिन इतना तो स्पष्ट है कि भारत में महिला क्रिकेट का परिदृश्य पूरी तरह से बदल चुका है. अब महिलाएं भारतीय क्रिकेट की चीयर लीडर नहीं, बल्कि असली लीडर हैं. ये महिलाएं भारतीय क्रिकेट को पुरुषों के साथ मिलकर मैदान पर महाशक्ति बनाने में न सिर्फ सक्रिय भूमिका निभायेंगी, बल्कि क्रिकेट को नयी ऊंचाइयों पर पहुंचायेंगी भी.

(ये लेखक के निजी विचार हैं.)

देश दुनिया

गाजा में स्थिरता के लिए दुनिया को इस्राइल की हिंसा की निंदा करनी होगी

दो वर्ष तक दुनिया गाजा में हो रही तबाही को देखती रही, पर इसे रोकने का कोई निर्णय नहीं कर पायी. इस दौरान सत्तर हजार से अधिक फिलिस्तीनी मारे गये और गाजा पट्टी का अधिकतर हिस्सा मलबे में बदल गया. पर वैश्विक शक्तियां खोखली चेतावनियों, दिखावटी युद्धविराम और राहत की बजाय मौत देने वाली सहायता व्यवस्थाओं के अलावा कुछ नहीं कर पायीं. एक बार फिर से अमेरिका के नेतृत्व वाली वैश्विक शक्तियां दावा कर रही हैं कि वे हमारे ध्वस्त हो चुके क्षेत्र में सुरक्षा प्रदान करने के लिए काम कर रही हैं. यह हास्यास्पद है कि यह सब कुछ उसी संस्था के सहयोग से हो रहा है जिसने इस क्षेत्र में नरसंहार को अंजाम दिया है. इस नये युद्धविराम के बाद गाजा को नियंत्रण के एक नये और कपटी रूप का सामना करना पड़ रहा है. गाजा पट्टी के उत्तर-पश्चिम में इराक अल-मन्शेया नामक फिलिस्तीनी गांव में दर्जनों देश और संगठन अब अमेरिका के नेतृत्व वाले नागरिक सैन्य समन्वय केंद्र में मौजूद हैं. यह एक विदेशी संचालित कमान केंद्र है, जहां से विदेशी अधिकारी दूर से पट्टी की निगरानी करेंगे और उस मॉडल को आकार देना शुरू करेंगे जो इसके भविष्य को नियंत्रित करेगा. यहां प्रश्न उठता है कि यदि वैश्विक शक्तियां गाजा के भविष्य के लिए इतनी समर्पित हैं, तो वे यहां के लोगों के बीच क्यों नहीं जाती हैं? क्या वे उन तबाह हुए लोगों से डरती हैं जिनकी मदद करने का वे दावा करती हैं? या फिर क्या वे जानती हैं कि एक बार गाजा में प्रवेश करने के बाद, इस्राइल के बमों से उनकी सुरक्षा की भी गारंटी नहीं दी जा सकती? जब तक अवैध कब्जे को जवाबदेही से बचाया जाता रहेगा और उसे भयरहित होकर काम करने की अनुमति दी जाती रहेगी, तब तक गाजा, फिलिस्तीन और इस क्षेत्र में स्थिरता नहीं आ सकती. यहां स्थिरता तभी संभव है, जब दुनिया इस्राइल की हिंसा की निंदा करे.

-अहद अल-नज्जार

बोधि वृक्ष

लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए

आज हम ऐसे युग में जी रहे हैं, जहां एक तरफ भौतिक समृद्धि अपनी ऊंचाई पर है, तो दूसरी तरफ चारित्रिक पतन की गहराई है. आधुनिकीकरण में उलझा मानव सफलता की नित नयी परिभाषा खोजता रहता है और स्वयं की ही अंतहीन इच्छाओं के रेगिस्तान में भटकता रहता है. ऐसे में सच्ची सफलता और सच्ची सुख-शांति की प्यास से आकुल-व्याकुल मनुष्य मानसिक रोगों का शिकार होता जा रहा है. परंतु हममें से कितनों को ज्ञान है कि जीवन में सफलता प्राप्त करना और सफल जीवन जीना, दो अलग-अलग बातें हैं. यह जरूरी नहीं कि जिसने साधारण कामनाओं को हासिल कर लिया हो, वह पूर्णतः संतुष्ट और प्रसन्न हो. अतः हमें समझना चाहिए कि इच्छित फल को प्राप्त कर लेना ही सफलता नहीं है. जब तक हम अपने जीवन को नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों से सिंचित नहीं करेंगे, तब तक वास्तविक सफलता पाना असंभव हो जायेगा, क्योंकि बिना मूल्यों के प्राप्त सफलता क्षणभंगुर सुख के समान है. बदलते परिवेश में मनुष्य ने स्थान की दूरी तय करने के लिए ऐसे साधन बनाने में सफलता पायी है जिससे हम सप्ताह की दूरी घंटों में और घंटों की दूरी मिनटों में तय कर सकते हैं, परंतु यही साधन दिलों की दूरियों को कम करने में असफल रहे हैं. हमने सागर की गहराई में जाकर मोती खोजना तो सीख लिया, किंतु अपने मन की गहराई में जाकर सुख-शांति खोजना अब तक नहीं सीख पाये हैं.

कुछ लोगों का कहना है कि हम सफल नहीं हो सकते, क्योंकि हमारे भाग्य या परिस्थितियां ही ऐसी हैं. परंतु यदि हम अपना ध्येय निश्चित कर लें, तो सफलता स्वयं हमारी और खिंची चली आयेगी. पर यदि हम असफलताओं के बारे में सोचते रहेंगे, तो कभी सफल नहीं हो पायेंगे. अतः, असफलताओं की चिंता न करें, क्योंकि वह हमारे जीवन का सौंदर्य हैं और संघर्ष जीवन का काव्य है. कई बार प्रथम आघात में पत्थर नहीं टूट पाता, उसे तोड़ने के लिए कई बार आघात करना पड़ता है. इसलिए सदैव अपने लक्ष्य को सामने रखकर आगे बढ़ते रहने की जरूरत है.

-ब्रह्माकुमार निकुंज जी

प्रबंध सूत्र

तकनीक से दोस्ती जरूरी

आज का युग तकनीकी युग है. पेटीएम से लेकर बैंकिंग एप्स, यूपीआई से लेकर ऑनलाइन बिल भुगतान तक-हमारी दिनचर्या में डिजिटल तकनीक इस कदर घुस चुकी है कि बिना इसके एक कदम चलना भी कठिन है. किंतु इस परिवर्तन की रफ्तार में जो पीछे छूटते दिखायी दे रहे हैं, वे हैं हमारे 70-80 वर्ष से अधिक आयु के माता-पिता, दादा-दादी तथा बुजुर्ग. जिन हाथों ने जीवनभर कलम पकड़ी, चिट्ठियां लिखीं, बैंक की पर्ची भरी, दुकानदार से नकद लेन-देन किया, आज वे हाथ स्मार्टफोन की स्क्रीन पर उलझे हैं. उनके लिए यह परिवर्तन सुविधा नहीं, संकट बन गया है. प्राचीन संस्कृत साहित्य में एक सुंदर उक्ति है, 'नवं नवं प्रजायते' अर्थात नित नया-नया उत्पन्न होता रहता है. यह नवीनता ही सृष्टि का नियम है, किंतु जब यह नवीनता तीव्र गति से आये, तो पुरानी पीढ़ी के लिए उसे आत्मसात करना कठिन हो जाता है.

आलोक पुराणिक
स्तंभकार
puranika@gmail.com

हमारे बुजुर्गों के सामने मुख्य समस्याएं हैं : जटिल इंटरफेस- बैंकिंग ऐप्स में अंग्रेजी, छोटे-छोटे आइकन, पासवर्ड, ओटीपी, बायोमेट्रिक. धोखाधड़ी का भय- रोज समाचार आते हैं कि बुजुर्ग के साथ ऑनलाइन ठगी हो गयी. इससे वे डरे रहते हैं. सहायता की कमी-बैंक शाखाएं कम हो रही हैं, काउंटर पर लंबी कतारें हैं और घर के युवा भी व्यस्त हैं. मानसिक दबाव- 'मैं पिछड़ गया', यह भावना उन्हें हीनता का शिकार बना देती है.

संस्कृत में एक और गंभीर उक्ति है-'विद्या विनयं ददाति'-विद्या विनम्रता देती है. किंतु जब कोई जीवन के छठे-सातवें दशक में यह महसूस करने लगे कि वह कुछ नया समझ नहीं पा रहा, तो उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है. कई बुजुर्ग मोबाइल फोन तो खरीद लेते हैं, पर उसे केवल इनकमिंग कॉल के लिए इस्तेमाल करते हैं. व्हाट्सएप पर 'गुड मॉर्निंग' के मैसेज आते हैं, पर वे उसे देख भी नहीं पाते, क्योंकि फोन साइलेंट मोड पर रहता है या बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है. यह उनकी गलती नहीं है, साठ साल की आयु के बाद नयी चीजें सीखने की क्षमता कम हो जाती है.

कुछ व्यावहारिक उपाय : सरल हिंदी/क्षेत्रीय भाषा एप्स-सरकार और बैंक क्षेत्रीय भाषाओं में सरल इंटरफेस वाले ऐप्स लायें. वॉयस कमांड का अधिक प्रयोग हो. बुजुर्ग-विशेष हेल्पलाइन-साठ से अधिक उम्र वालों के लिए हर बैंक का अलग से नंबर हो, जहां धैर्यपूर्वक हिंदी में सहायता मिले. परिवार की जिम्मेदारी-सप्ताह में एक घंटा निश्चित करें, जब बच्चे या पोते-पोतियां धीरे-धीरे सिखायें. दबाव न डालें, प्रशंसा करें. सामुदायिक कक्षाएं- अपार्टमेंट्स, वरिष्ठ नागरिक संघों में 'निःशुल्क डिजिटल साक्षरता' शिविर आयोजित हों. ऑफलाइन विकल्प बनाये रखें- नकद लेन-देन, चेक, पासबुक सुविधाएं बंद न हों.

आपके पत्र

भाषा की मर्यादा बनाये रखें

कोई भी जब सार्वजनिक मंच पर बोलता है, तो उसके शब्द व्यक्तिगत नहीं रह जाते, वे सभ्य समाज की गरिमा का प्रतिबिंब बन जाते हैं. हाल ही में आइएएस संतोष वर्मा द्वारा आरक्षण चर्चा के दौरान ब्राह्मण बेटियों के संदर्भ में किया गया कथित बयान अत्यंत आपत्तिजनक और अस्वीकार्य है. बेटियां किसी समुदाय की संपत्ति नहीं, राष्ट्र की आत्मा हैं. उनके सम्मान पर आघात पूरे समाज के सम्मान पर आघात है. हमें चाहे किसी से कितनी भी शिकायत क्यों न हो, बोलते समय भाषा की मर्यादा बनाये रखनी चाहिए.

प्रो आरके जैन, बड़वानी

ध्वनि प्रदूषण चिंता की बात

बढ़ता ध्वनि प्रदूषण चिंता का कारण बन रहा है. भीड़भाड़ वाली जगह पर लोगों द्वारा लगातार हॉर्न बजाते रहना, शादी, पार्टी या किसी छोटे समारोह में तेज आवाज में लाउडस्पीकर बजाना सही नहीं है. तेज ध्वनि का दुष्प्रभाव छोटे बच्चे एवं नवजात शिशुओं पर अत्यधिक पड़ता है. बच्चों के नाजुक श्रवण अंगों पर अत्यधिक ध्वनि को झेलने की क्षमता नहीं होती है. तेज आवाज के दुष्प्रभाव से बच्चों में श्रवण शक्ति क्षीण होने के साथ अन्य बीमारियां भी उत्पन्न हो सकती हैं. इसलिए हमें ध्वनि प्रदूषण से बचना चाहिए.

पी वासुदेव राव, जमशेदपुर

पोस्ट करें : प्रभात खबर, 15 पी, इंडस्ट्रियल एरिया, कोकर, रांची 834001 ■ **फैक्स करें :** 0651-2544006 ■ **मेल करें :** eletter@prabhatkhabar.in पर ■ ई-मेल संक्षिप्त व हिंदी में हो. लिपि रोमन भी हो सकती है.

न्यूज बाइट्स

शॉर्टकट ले रहा था, चल पड़ी ट्रेन, बाल-बाल बचा

फतेहपुर (गया). गया-कोडरमा रेलखंड के पहाड़पुर स्टेशन पर रविवार दोपहर एक युवक के ऊपर से पूरी मालगाड़ी गुजर गयी, लेकिन उसकी खरोंच तक नहीं आयी. सूत्रों के अनुसार, रविवार दोपहर डाउन लूप लाइन में बॉक्स एमटी मालगाड़ी खड़ी थी. इसी दौरान एक युवक जल्दबाजी में खड़ी मालगाड़ी के नीचे से होकर रेलवे ट्रैक पार करने लगा. तभी मालगाड़ी अचानक चल पड़ी. ट्रेन खुलते ही युवक घबरा गया, लेकिन उसने संयम नहीं खोया. सूझबूझ दिखाते हुए वह पटरी पर लेट गया. उसके ऊपर से पूरी मालगाड़ी गुजर गयी.

तीन दिसंबर को राज्यव्यापी आंदोलन : माले

पटना. भाकपा–माले की तीन दिवसीय केंद्रीय कमेटी की बैठक के बाद माले राज्य सचिव कुणाल ने रविवार को कहा कि चुनाव के बाद पूरे राज्य में दलित और गरीब समुदायों पर बुलडोजर चलाये जा रहे हैं. उन्होंने इसे दलितों और गरीब जनता के खिलाफ सीधे हमला करार दिया. कुणाल ने घोषणा की कि इस कार्रवाई के खिलाफ तीन दिसंबर को बिहार विधानसभा के समक्ष धरना आयोजित किया जायेगा.

अत्याचार के खिलाफ कांग्रेस नेताओं का प्रदर्शन

पटना. नालंदा के रहुई प्रखंड के शिवनन्दन नगर में एक समुदाय के घरों पर बुल्डोज़र चलाने सहित दलित, महादलित और अतिपिछड़ा समाज अत्याचारों के विरोध में इन्कम टैक्स गोलंबर पर रविवार को कांग्रेस नेताओं ने एक दिवसीय धरना-प्रदर्शन किया. इसमें बुल्डोज़र कार्रवाई की उच्च स्तरीय न्यायिक जांच की मांग की गयी. साथ ही दोषी अधिकारियों एवं जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की गयी.

एनआइए का सुबह तीन बजे पूर्व पोस्टमास्टर के घर छापा

दिल्ली बम ब्लास्ट के तार खगड़िया से जुड़े

प्रतिनिधि, मानसी (खगड़िया)

दिल्ली बम ब्लास्ट के तार खगड़िया से जुड़ गये हैं. एनआइए की 15 सदस्यीय टीम ने मानसी के सैदपुर गांव में रविवार की सुबह तीन बजे छापेमारी की. छापेमारी के बाद सेवानिवृत्त पोस्टमास्टर अब्दुल हादी का मोबाइल एनआइए की टीम लेकर चली गयी. थाना क्षेत्र के सैदपुर गांव वार्ड संख्या-8 निवासी सेवानिवृत्त ब्रांच पोस्टमास्टर अब्दुल हादी उर्फ नन्हू ने बताया कि एनआइए की टीम सुबह तीन बजे 10 फीट ऊंची दीवार फांदकर घर में घुस गयी. घर की तलाशी ली गयी. उन्होंने बताया कि घर में सभी जगह की तलाशी लेने के बाद टीम मेरे छोटे भाई दिवंगत अब्दुल अहद उर्फ साहेब के घर में घुसकर बक्सा, आलमारी की तलाशी ली. उन्होंने बताया कि किसी प्रकार का कोई सामान या आपत्तिजनक सामग्री नहीं मिली. अब्दुल हादी ने बताया एनआइए की टीम एक मोबाइल साथ ले गयी है.

छापेमारी के बाद पोस्टमास्टर के साथ ग्रामीण.

परिवार के सभी सदस्यों को गिरफ्त में ले लिया

अब्दुल हादी ने बताया कि सुबह तीन बजे घर के सभी सदस्य सोये हुए थे. इसी दौरान चहारदीवारी फांदकर एनआइए की 15 सदस्यीय टीम घर में घुस गयी. टीम में दो महिलाएं भी शामिल थीं. जब तक वह कुछ समझ पाते उन्हें एनआइए की टीम ने गिरफ्त में लिया. हादी ने बताया इस तरह घर में घुस कर तलाशी लेने से पूरे परिवार के लोग भयभीत हैं.

चार घंटे तक एनआइए की टीम ने की छापेमारी

सैदपुर गांव में अब्दुल हादी व स्व अब्दुल अहद के घर एनआइए की टीम सुबह तीन बजे से सात बजे तक छापेमारी की. रविवार की सुबह आसपास की सभी सड़कों व गलियों की नाकेबंदी कर दी गयी थी. किसी को बाहर निकलने की अनुमति नहीं दी गयी. स्थानीय लोगों में चर्चा का बाजार गरम हो गया. हालांकि प्रशासनिक पुष्टि नहीं हो पायी है.

नयी विस का सत्र आज से, कल स्पीकर चुने जायेंगे प्रेम कुमार

पटना. राज्य में 18वीं विधानसभा के पहले शीतकालीन सत्र की शुरुआत सोमवार से होगी. यह सत्र पांच दिसंबर तक चलेगा. इसको लेकर सुरक्षा बंदोबस्त सहित सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं. शीतकालीन सत्र के दौरान कुल पांच बैठकें निर्धारित की गयी हैं. सत्र के पहले दिन एक दिसंबर को नवनिर्वाचित विधानसभा सदस्यों का शपथ ग्रहण होगा. इनको प्रोटेम स्पीकर नरेंद्र नारायण यादव सदन की सदस्यता ग्रहण करने की शपथ दिलायेंगे. वर्ष 2010 के बाद पहली बार सदन में सत्ता पक्ष की ओर 200 से अधिक सदस्य होंगे. विपक्ष के सदस्यों की संख्या 38 होगी. इसी दिन दोपहर में नये विधानसभा के अध्यक्ष पद के लिए नामांकन होगा. भाजपा के डॉ प्रेम कुमार विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए अपना नामांकन दाखिल करेंगे. दो दिसंबर को एक से अधिक नामांकन होने की स्थिति में अध्यक्ष पद का चुनाव होगा. एक ही नामांकन की स्थिति में डा प्रेम कुमार के निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित होने की घोषणा की जायेगी. साथ ही तीन दिसंबर को बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होगी.

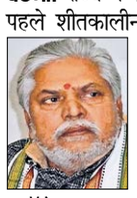

डॉ प्रेम कुमार

रोजगार का बड़ा केंद्र बनकर उभर रहा है सोनपुर मेला : नीतीश कुमार

प्रतिनिधि, सोनपुर

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोनपुर मेला परिसर पहुंच कर अलग-अलग विभागों की प्रदर्शनियों का अवलोकन किया. उन्होंने कहा कि सोनपुर मेला काफी ऐतिहासिक है. सरकार इसे सजाने व संवारने के लिए हर स्तर पर प्रयास कर रही है. कहा कि मेला में आने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ी है और युवा वर्ग यहां आकर मेला की ऐतिहासिकता से अवगत हो रहे हैं. मुख्यमंत्री ने इस मेले को रोजगार का एक बड़ा केंद्र बताया. कहा कि खासकर महिलाएं भी अब यहां रोजगार का अवसर प्राप्त कर रही हैं.

सोनपुर मेले में लगे स्टॉल का निरीक्षण करते मुख्यमंत्री नीतीश कुमार.

जीविका समूह को 98 करोड़ से अधिक की राशि हस्तांतरित : मुख्यमंत्री ने इस दौरान ग्रामीण विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को राशि हस्तांतरित किया. जीविका सारण के अंतर्गत 2184 स्वयं सहायता समूहों को परियोजना एवं विभिन्न बैंकों के माध्यम से कुल 98 करोड़ 12 लाख की राशि प्रदान की गयी.

मजदूरों को कैंप लगाकर बिहार में दिया जायेगा रोजगार

संवाददाता, पटना

बिहार से दूसरे देश और राज्य में काम करने जाने वाले मजदूरों को कैंप लगाकर बिहार में रोजगार मिलेगा. इस दिशा में श्रम संसाधन विभाग के अधिकारियों ने तैयारी शुरू कर दी है. विभाग सबसे पहले मजदूरों के स्किल के मुताबिक बिहार में रोजगार सृजन करेगा. उसके बाद उन सभी मजदूरों को उनके घर के पास रोजगार मिलेगा. अधिकारियों ने रोजगार सृजन के लिए संबंधित सभी विभागों से पत्राचार शुरू कर दिया है, ताकि सरकारी व निजी विभागों में काम में इन्हें प्राथमिकता मिल सके.

बिहार में पांच आइएएस का तबादला, मिहिर बने विकास आयुक्त

पटना. राज्य में पांच आइएएस का तबादला रविवार को किया गया है. मिहिर कुमार सिंह को विकास आयुक्त की जिम्मेदारी दी गयी है. वे उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव थे. प्रमण्डलीय आयुक्त, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर राज कुमार को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक सचिव, परिवहन विभाग की जिम्मेदारी दी गयी है. इसके साथ ही सीके अनिल को बिहार राज्य योजना पर्षद के परामर्शी पद से स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रधान सचिव की जिम्मेदारी दी गयी है. ग्रामीण कार्य विभाग के अपर मुख्य सचिव और राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव के अतिरिक्त प्रभार में कार्यरत दीपक कुमार सिंह को अब स्थानांतरित करते हुए महानिदेशक-सह-मुख्य जांच आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग की जिम्मेदारी दी गयी है. बिहार भवन, नयी दिल्ली के स्थानिक आयुक्त कुंदन कुमार को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक उद्योग विभाग के सचिव की जिम्मेदारी दी गयी है. लघु जल संसाधन विभाग के सचिव बी कार्तिकेय धनजी (अतिरिक्त प्रभार-सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को अतिरिक्त प्रभार से मुक्त कर दिया गया है.

बंगला खाली हुआ, तो महुआबाग में शिफ्ट हो जायेंगे लालू-राबड़ी!

संवाददाता, पटना

पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी आवास को खाली करने का नोटिस भेजा गया है. राबड़ी देवी को 39 हार्डिंग रोड में नया सरकारी बंगला आवंटित किया गया है. हालांकि राजद के प्रदेश अध्यक्ष सहित कई नेताओं के बयान आये हैं कि यह बंगला खाली नहीं किया जायेगा. जरूरत पड़ी तो पार्टी कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा सकती है. सूत्रों के अनुसार यदि बंगला खाली करने की नौबत आती है तो लालू व राबड़ी के नये आवंटित बंगले में शिफ्ट होने की संभावना बेहद कम है, ऐसी परिस्थिति में लालू-राबड़ी परिवार सरकारी बंगले के बजाय दानापुर के महुआबाग में बन रहे आवास में शिफ्ट हो सकता है.

महुआबाग में बन रहा लालू प्रसाद का मेंशन.

पिछले पांच साल से बन रहा मेंशन : दानापुर के महुआबाग में लालू परिवार का निजी आवास पिछले करीब पांच वर्षों से निर्माणाधीन है. अब इसके इंटीरियर पर काम जारी है, जो जल्द पूरा होने की संभावना है.

बेलसंड विधायक को मिली जान से मारने की धमकी

मुजफ्फरपुर. सीतामढ़ी जिले के बेलसंड विधानसभा क्षेत्र से लोजपा रामविलास के टिकट पर नवनिर्वाचित विधायक अमित कुमार रानू को जान से मारने की धमकी मिली है. उनके निजी सचिव सौरभ कुमार ने मुजफ्फरपुर जिले के अहियापुर थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी है. दारोगा प्रमोद प्रसाद केस के आइओ हैं. वह दिये गये मोबाइल नंबर के आधार पर छानबीन में जुटे हैं. प्रारंभिक छानबीन में पुलिस को पता चला है कि जिस नंबर से नवनिर्वाचित विधायक को धमकी मिली है, वह नंबर राहुल सिंह के नाम से टू कॉलर में दिख रहा है.

बाइक सवार, इ-रिक्शा, पैदल यात्री... जो मिला उसे रौंदता गया ट्रक, पांच की मौत

प्रतिनिधि, मोतिहारी

कोटवा थाने के दीपउ मोड़ के पास रविवार को तेज रफ्तार ट्रक ने एक साथ आठ से अधिक बाइक व इ-रिक्शा में जोरदार टक्कर मार दी. इससे पांच लोगों की मौत हो गयी. वहीं, आधा दर्जन से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गये. घटना रविवार को दोपहर करीब 12.30 बजे के आसपास की है.घटना से आक्रोशित लोगों ने जमकर बवाल किया. एनएचएआइ की गाड़ी को फूंक दिया. वहीं डुमरियाघाट थाने की गाड़ी व डायल 112 की गाड़ी को क्षतिग्रस्त कर दिया. थानाध्यक्ष से लेकर डीएसपी तक से आक्रोशित लोगों की तीखी नोकझोंक हुई.

तीन बाइक को दस मीटर तक घसीटा : दोपहर साढे बाहर बजे कोटवा दीपउ मोड़ क्रॉस करने के लिए दर्जनों बाइक सवार, इ-रिक्शे व पैदल यात्री खड़े थे. इस बीच तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक ने डिवाइडर को तोड़ते हुए सड़क पार करने के इंतजार में खड़े लोगों को रौंद दिया. इस दौरान ट्रक के नीचे तीन बाइक फंसी रह गयी, लेकिन चालक ने ट्रक नहीं रोका और करीब दस मीटर तक तीनों बाइक को घसीटते ले गये.

झारखंड

न्यूज बाइट्स

चौका में कुएं से शव बरामद तीन दिन से लापता था

चौका. ईचागढ़ के चितरी गांव में कुएं से पुलिस ने रविवार को एक व्यक्ति का शव बरामद किया है. शव की पहचान रांची के सोनाहातू के बारेंदा गांव निवासी दलगोबिंद सिंह (56) के रूप में हुई है. कुआं में शव मिलने पर लोगों ने इसकी सूचना ईचागढ़ थाना को दी. पुलिस शव को जब्त कर पोस्टमार्टम के लिए सरायकेला भेज दिया है. वह कई वर्षों से ईचागढ़ के चितरी गांव में परिवार के साथ रहता था. दलगोबिंद सिंह बीते शुक्रवार से घर से लापता था.

गोला : युवक ने फांसी लगा कर दे दी जान

गोला. गोला थाना क्षेत्र की हेंसापोड़ा पंचायत अंतर्गत परसाडीह गांव में पेड़ से लटका युवक का शव मिला. पुलिस ने बताया कि मृतक की पहचान लालधन मांझी के पुत्र सुनील हेंब्रम के रूप में हुई है. परिजनों ने बताया कि सुनील शनिवार रात से लापता था. उसकी खोजबीन की गयी, लेकिन उसका पता नहीं चला. रविवार सुबह 11 बजे ग्रामीणों को शव पेड़ पर लटका हुआ दिखाई पड़ा. इसके बाद परिजनों को सूचना दी गयी. बताया जाता है कि सुनील रामधन मांझी का छोटा पुत्र था. वह अविवाहित था. वह ट्रैक्टर चालक था. गांव में इस घटना को लेकर प्रेम-प्रसंग सहित अन्य मामले से भी जोड़ कर चर्चा की जा रही है.

प्रभात खबर संवाद. देश के कोकिंग कोल का 20 फीसदी स्टॉक बीसीसीएल में

बीसीसीएल का भविष्य उज्जवल, आनेवाले समय में कोकिंग कोल की मांग बढ़ेगी : सीएमडी

वरीय संवाददाता, धनबाद

- क्वालिटी से समझौता नहीं, लापरवाह अधिकारी नपेंगे
- नक्सलवाद की तरह खत्म होगी कोयला चोरी
- कारपोरेट अस्पताल की तर्ज पर विकसित होगा केंद्रीय अस्पताल

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल) के सीएमडी मनोज कुमार अग्रवाल रविवार को प्रभात खबर के धनबाद कार्यालय पहुंचे. उन्होंने प्रभात खबर संवाद में कोयला उद्योग के भविष्य से लेकर नये श्रम कानून एवं झरिया मास्टर प्लान के क्रियान्वयन से संबंधित सवालों का खुलकर जवाब दिया.

सीएमडी ने कहा कि बीसीसीएल का भविष्य उज्जवल है. देश में कोकिंग कोल की मांग आने वाले दिनों में घटने की बजाय बढ़ने वाली है. भारत में सबसे ज्यादा कोकिंग कोल का स्टॉक बीसीसीएल के पास है. इस्पात उद्योग के लिए कोकिंग कोल की सबसे ज्यादा जरूरत है. वहीं कंपनी कोयले के इतर भी सीबीएम व सोलर प्लांट जैसे डायवर्सिफिकेशन प्रोजेक्ट पर भी तेजी काम कर रही है. जल्द ही सीबीएम का उत्पादन शुरू होने की संभावना है. नये श्रम कानून से मजदूरों को लाभ होगा. यह कहीं से भी मजदूर विरोधी नहीं है. इससे जेंडर भेद समाप्त हुआ है. सबको काम का बराबर मौका मिलेगा. आने वाले समय में कोयला चोरी समाप्त होगी. नक्सलवाद की तरह इसका भी अंत होगा. झरिया के अग्नि एवं भू-धंसान प्रभावितों के लिए मंजूर रिवाइज्ड मास्टर प्लान का हर हाल में क्रियान्वनय होगा. जून 2028 तक तय समय-सीमा में सभी कार्य होंगे.

चार नये श्रम कानूनों से होगा लाभ

मनोज कुमार अग्रवाल.

नये श्रम कानून को लेकर कोयला उद्योग में विभिन्न श्रम संगठनों के विरोध के सवाल पर कहा कि नया श्रम कानून को लेकर किसी को चिंतित होने की जरूरत नहीं है. यह मजदूरों के हित में है. सरल भाषा में कहें कि पहले जहां मजदूरों के लिए 29 कनून थे. वहीं अब सिर्फ चार रह गया है. अब महिलाएं भी कोयला उद्योग में 24 घंटे काम कर सकती हैं. पहले महिलाओं को पात्रि ड्यूटी नहीं मिलती थी. काम का घंटा भी तय हो गया है. ठेका मजदूरों को भी न्यूनतम मजदूरी मिलेगी. साथ ही मेडिकल सुविधाएं एवं बीमा का लाभ मिलेगा.

कोढ़ है कोयला चोरी चंद लोगों को ही लाभ

कोयला चोरी की चुनौती पर कहा कि कोयला चोरी जल्द ही समाप्त होगी. नक्सलवाद की तरह इसका भी अंत होगा. कोयला चोरी कोढ़ है. इससे चंद लोगों को ही लाभ होता है. जबकि इस काम में लगे लोग बहुत कठिन श्रम करते हैं. उन्हें कई तरह की समस्याएं झेलनी पड़ती है.

prabhatkhabar.com पर संबंधित वीडियो देखने के लिए स्कैन करें

रायडीह : सड़क दुर्घटना में पांच माह की मासूम की मौत, छह लोग घायल

रांची से चैनपुर मेहमानी में आये थे, लौटने के क्रम में हुआ हादसा

प्रतिनिधि, रायडीह

रायडीह थाना क्षेत्र अंतर्गत मरियमटोली में रविवार की शाम सड़क दुर्घटना हुई. इसमें रांची के दलादली निवासी एक ही परिवार के सात लोग गंभीर रूप से घायल हो गये, जिसमें मासूम अमायरा कुजूर (पांच माह) की मौत हो गयी. हादसा इतना भयावह था कि मौके पर अफरा-तफरी मच गयी.

स्थानीय लोगों, पुलिस और समाजसेवी अशरफ राय लालो की मदद से घायलों को रायडीह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद सभी घायलों को बेहतर इलाज के लिए गुमला सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया. गुमला सदर अस्पताल पहुंचते डॉक्टरों ने पांच माह की मासूम अमायरा कुजूर को मृत घोषित कर दिया. घायलों में पात्रिक बेक (40 वर्ष), हरलीना एक्का (37 वर्ष), निलोफर एक्का (32 वर्ष), अमित कुजूर (37 वर्ष), अमायरा कुजूर (पांच माह), इवान डायलोन बेक व संगीता गोगोराई (16 वर्ष) शामिल हैं. सभी घायलों की हालत चिंताजनक बतायी जा रही है. जानकारी के अनुसार सभी लोग एक कार से चैनपुर एक पारिवारिक समारोह में शामिल होने आये थे. कार्यक्रम समाप्त होने के बाद वे रांची लौट रहे थे. इस दौरान मरियमटोली के पास कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से टकरा गयी. इधर, सदर अस्पताल में अमायरा की मौत की खबर सुनते परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

चास : वाहन के धक्के से बाइक सवार युवक की मौत

तलगड़िया. चास मुफस्सिल थाना क्षेत्र के चास–तलगड़िया मुख्य पथ पर धनडाबर के पास अज्ञात वाहन की चपेट में आने से बाइक सवार युवक घलटु रजवार (48 वर्ष) की मौत हो गयी. घटना रविवार शाम करीब साढ़े चार बजे की है. बताया जाता है कि घलटू रजवार अपनी बाइक (जेएच 09 कियु 2311) से अमलाबाद ओपी क्षेत्र भंडारीबांध गांव में रिश्तेदार के यहां पार्टी से अपने घर भवानीपुर साइड चास लौट रहा था. इसी क्रम में उसकी बाइक वाहन की चपेट में आ गयी. घटना के बाद थोड़ी देर के लिए सड़क जाम हो गया था. मृतक जोधाडीह मोड़ की दुकान में मजदूरी पर काम करता था. उसके दो पुत्र हैं. वह परिवार का एकमात्र कमाऊ सदस्य था. इधर, घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को उठा कर पोस्टमार्टम के लिए भेजने का प्रयास किया, लेकिन परिजन व ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग को लेकर शव उठाने नहीं दिया. कहा कि जब तक मुआवजा नहीं मिल जाता है, तब तक शव उठाने नहीं देंगे. समाचार लिखे जाने तक शव सड़क पर ही पड़ा था.

एसआइआर का झारखंड में कोई असर नहीं, बिहार की ज्यादा जानकारी नहीं

मुख्य संवाददाता, जमशेदपुर

- विधानसभा अच्छे से चले, तैयारी पूरी, आगामी पांच दिसंबर से 11 दिसंबर 2025 तक चलेगा शीतकालीन सत्र.
- भारत सरकार के उपक्रम यूसीआइएल में स्थानीय युवाओं को रोजगार मिले, इसे लेकर सरकार से बात करेंगे.

झारखंड में मतदाता एसआइआर (विशेष गहन पुनरीक्षण) का कोई असर नहीं है. झारखंड में हुए हाल में हुए घाटशिला उपचुनाव इसका ताजा उदाहरण है. यह बातें झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रवींद्रनाथ महतो ने रविवार को स्थानीय परिसदन में 'प्रभात खबर' से बातचीत में कही.

झारखंड विधानसभा अध्यक्ष श्री महतो ने बिहार चुनाव में एसआइआर को लेकर सवाल पर कहा कि उन्हें बिहार की ज्यादा जानकारी नहीं है. उन्होंने कहा कि विधानसभा अच्छे से चले, इसकी तैयारी की जा रही है. आगामी पांच दिसंबर से 11 दिसंबर 2025 तक शीतकालीन सत्र चलेगा. विधानसभा अध्यक्ष ने आगे कहा कि भारत सरकार के उपक्रम यूसीआइएल में स्थानीय युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले, इसे लेकर सरकार से बात करेंगे. यूसीआइएल में तृतीय व चतुर्थवर्गीय स्तर की राष्ट्रीय बहाली का विरोध कर रहे हैं. इसे लेकर स्थानीय युवाओं का एक प्रतिनिधिमंडल झामुमो जिला संयोजक बाघराय मार्डी के नेतृत्व में रविवार को उन्हें ज्ञापन सौंपकर ध्यान आकृष्ट कराया है. राज्य के विकास व माहौल के एक सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि राज्य में रोजगार का अच्छा माहौल है. सरकार ने युवाओं को डिप्टी कलेक्टर से लेकर अन्य पदों का नियुक्ति पत्र बांटा है.

सेक्स समस्याओं का प्रभावशाली समाधान

शुगर एवं बीपी में लाभदायक
मात्र 400/- 600/-
12 घंटे असर
आधुनिक आविष्कार
शीघ्रपतन, स्वप्नदोष, नपुंसकता, इन्द्री की कमजोरी व इन्द्री का छोटापन के लिए विशेष लाभदायक
100% आयुर्वेदिक
18 वर्ष से 80 वर्ष तक लाभदायक
0852169839 9
0822890141 9

बंदर के हमले से जवाहर नवोदय विद्यालय के चार छात्र घायल

गांडेय. बंदर के हमले में जवाहर नवोदय विद्यालय की एक छात्रा समेत चार विद्यार्थी रविवार को घायल हो गये. शिक्षक और कर्मचारी घायल बच्चों को लेकर सीएचसी पहुंचे. वहां उनका प्राथमिक उपचार किया गया. बच्चों को टीकाकरण के लिए सोमवार की सुबह बुलाया गया है. जानकारी के अनुसार, रविवार की दोपहर विद्यालय परिसर में अचानक एक बंदर पहुंच गया. वह सीधे मेस में घुस गया. उसे देख कर छात्र हड़बड़ा गये. इसी क्रम में बंदर ने हमला कर चार विद्यार्थियों को घायल कर दिया. सूत्रों की मानें, तो शनिवार की शाम गांधीनगर के जंगल में कुछ युवकों ने उक्त बंदर को शराब पिला दी थी. शराब पीने के बाद बंदर नशे में हरकत करने लगा था.

घोड़थंभा में असामाजिक तत्वों ने आदिवासियों का घर जमींदोज किया

प्रतिनिधि, खोरीमहुआ

- रोहनियाटांड़ गांव की घटना, शादी समारोह में गये थे पीड़ित लोग

घोड़थंभा ओपी क्षेत्र अंतर्गत रोहनियाटांड़ गांव में शनिवार की देर रात असामाजिक तत्वों ने शादी समारोह में गये कई आदिवासी परिवारों के घर को निशाना बनाया. इस दौरान उनके कच्चे और टिनशेड घरों को जमींदोज कर दिया. रविवार की सुबह जब परिवार के सदस्य लौटे, तो अपना टूटा-फूटा आशियाना देखकर स्तब्ध रह गये. पीड़ित लोगों ने पारंपरिक तरीके से डुगडुगी बजाकर ग्रामीणों को एकत्रित किया तथा बैठक कर इस घटना पर आक्रोश व्यक्त किया. सुकेश हेंब्रम, ब्रह्मदेव टुडू आदि आदिवासी नेताओं ने इसे एक सोची-समझी शरारत बताते हुए दोषियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की. भुक्तभोगी महान मालिक जगदीश बास्के, संझलु बास्के, नरेश हेंब्रम, सुरेश बास्के, मदन बास्के, नरेश बास्के, चरकू बास्के, बबुआ मुर्मू आदि ने बताया कि घर के अंदर राशन, कपड़े, बर्तन आदि सब दब गये हैं. कहा कि रात के अंधेरे में घर तोड़े जाने की यह पहली घटना है. सूचना पर घोड़थंभा पुलिस मौके पर पहुंची और जांच की. ओपी प्रभारी धर्मेंद्र अग्रवाल ने आदिवासी परिवारों को आश्वस्त किया कि घटना गंभीर है और इसमें शामिल व्यक्तियों की पहचान कर कड़ी कार्रवाई की जायेगी.

कोयला लदा ट्रक जब्त

बोकारो थर्मल. बोकारो थर्मल थाना क्षेत्र अंतर्गत कथारा स्थित ऑटो लाइफ पेट्रोल पंप परिसर से पुलिस ने 35 टन कोयला लदा एक ट्रक (यूपी 67 एटी 2025) जब्त किया. मामले में ट्रक के चालक व मालिक पर केस दर्ज किया गया है. थाना प्रभारी पिंकू कुमार यादव ने गुप्त सूचना पर कार्रवाई की. इसके बाद पुलिस जवान ट्रक को जब्त कर थाना ले आये.

सेक्स समस्याओं का प्रभावशाली समाधान

शुगर एवं बीपी में लाभदायक
मात्र 400/- 600/-
12 घंटे असर
आधुनिक आविष्कार
शीघ्रपतन, स्वप्नदोष, नपुंसकता, इन्द्री की कमजोरी व इन्द्री का छोटापन के लिए विशेष लाभदायक
100% आयुर्वेदिक
18 से 80 वर्ष तक के लिए लाभदायक
9709991888
9709992888

वर्ष : 42, अंक : 325, रजिस्ट्रेशन : आर एन 44208/1984, पोस्टल रजिस्ट्रेशन : आरएन /022/2018-20, प्रभात खबर हवाई शुल्क : पटना, कोलकाता : 10 पैसे, लखनऊ, नयी दिल्ली : 15 पैसे, अखबार के स्वामी न्यूट्रल पब्लिशिंग हाउस लि. के लिए मुद्रक, प्रकाशक : आशुतोष चौबे द्वारा प्रकाशित तथा न्यूट्रल पब्लिशिंग हाउस लि., एम.एच.आई. बिल्डिंग, ओल्ड हजारीबाग रोड, कोकर, रांची-834001, (झारखंड) से मुद्रित और न्यूट्रल पब्लिशिंग हाउस लि., 15-पी, कोकर इंडस्ट्रियल एरिया, रांची (झारखंड) से प्रकाशित. संपादक (रांची संस्करण) : विजय पाठक*, प्रबंध संपादक : अंकित शुक्ला, प्रधान संपादक : आशुतोष चतुर्वेदी, फोन : संपादकीय 6613100, 6613140, विज्ञापन : 6613106, प्रसार विभाग : 6613114, ई मेल : ranchi@prabhatkhabar.in (* पीआरपी अधिनियम के तहत खबरों के चयन के लिए जिम्मेवार.)

तैयारी • लावारिस कुत्तों की बढ़ती संख्या को नियंत्रित करने की कवायद, हर माह 50 के करीब कुत्तों का बधियाकरण

नवादा में 10 एकड़ भूमि पर बनेगा लावारिस कुत्तों का आश्रय स्थल

भास्कर न्यूज | फरीदाबाद

शहर में लावारिस कुत्तों के लिए नवादा गांव मे करीब 10 एकड़ भूमि पर आश्रय स्थल बनाया जाएगा। वहां एक साथ करीब 5000 कुत्तों को रखा जा सकेगा। वहां डाक्टर की भी तैनाती की जाएगी। पूरा स्थल सीसीटीवी कैमरे की जद में रहेगा। शहर में आवारा कुत्तों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन निगम की ओर से एक भी शेल्टर नहीं है।

निगम के आंकड़ों की माने तो शहर के 46 वार्डों में आवारा कुत्तों की संख्या 18 हजार के करीब है। निगम ने स्ट्रीट डॉग के बधियाकरण के लिए एजेंसी गठित की है। यह एजेंसी हर माह 50 के करीब कुत्तों का बधियाकरण करती है। जिससे उनकी संख्या को नियंत्रित किया जा सके।

एजेंसी के पदाधिकारियों के अनुसार एक साल में 3400 कुत्तों का बधियाकरण किया गया है। इसके बावजूद शहर में कुत्तों की संख्या बढ़ रही है। लिहाजा कुछ समय पहले सीएम नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों को लावारिस कुत्तों की बढ़ती संख्या को नियंत्रित करने का आदेश दिया था। इसके बाद नगर निगम की ओर से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं।

सुप्रीम कोर्ट भी लगा चुका है फटकार

सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों अपने एक फैसले में कहा था कि कुत्तों को खाना खिलाने के स्थान सुरक्षित और नियंत्रित तरीके से तय किए जाएं, ताकि लोगों की सुरक्षा प्रभावित न हो। शहर में यह व्यवस्था अभी तक नहीं है। नतीजतन सड़कें, गली-मोहल्ले भोजन स्थलों में बदल गए हैं। जहां रोज लोग कुत्तों को खाना खिलाते हैं। इससे वहां कुत्तों का जमावड़ा बना रहता है।

निगम के पास कार्रवाई का विकल्प

नगर निगम के अधिकारियों का कहना है कि नियम कुत्तों को सड़क से उठाकर स्थायी रूप से कहीं रखने की अनुमति नहीं देते। एबीसी (एनीमल बर्थ कंट्रोल) प्रोग्राम के तहत कुत्तों को पकड़कर नसबंदी व टीकाकरण कर उसी इलाके में छोड़ा जाता है। लेकिन जब कोई कुत्ता बार-बार काट रहा हो या आक्रामक हो जाए तो निगम के पास उसे रखने का स्थान ही नहीं है।

शहर में आवारा कुत्तों और लावारिस पशुओं के लिए नवादा गांव में जगह देखी जा रही है। पांच से 10 एकड़ जमीन हमें मिलने की उम्मीद है। जहां पांच हजार से अधिक कुत्तों और पशुओं को रखने की व्यवस्था होगी।
-अशवीर सिंह, विशेष स्वास्थ्य अधिकारी, नगर निगम

हेल्प लाइन नंबर जारी किया

स्वास्थ्य विभाग ने तीन हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। इन पर लोग कुत्तों से संबंधी किसी भी समस्या की शिकायत दर्ज करा सकते हैं। ये नंबर हैं 0129-2411649, 0129-2411664, 0129-2415449 हैं। इसके साथ ही नगर निगम के अधिकृत वेंडर द्वारा भी एक अलग शिकायत नंबर जारी किया गया है। लोग 76890 44463 इस नंबर पर कुत्तों को पकड़ने, नसबंदी, आक्रामक कुत्तों की सूचना या किसी भी अन्य समस्या से जुड़ी शिकायतें दर्ज करा सकेंगे।

ग्रेटर फरीदाबाद सेक्टर-77 में नया ब्लॉक का होगा विकास

कोर्ट केस हुआ खत्म, जनवरी से शुरू होगा काम

भास्कर न्यूज | फरीदाबाद

हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) सेक्टर-77 में जल्द ही एक नया ब्लॉक विकसित करेगा। इसकी योजना तैयार की जा रही है। प्राधिकरण ने सेक्टर 77 में पहले से ही काफी विकास कार्य हुए हैं। इस सेक्टर में पांच से छह एकड़ जमीन ऐसी थी, जिस पर कोर्ट केस चल रहा है। एचएसवीपी ने इस जमीन को पहले अधिग्रहण कर लिया था, लेकिन पहले यह जमीन जिस व्यक्ति की थी, उसने से रिलीज करने का केस डाला हुआ था। कोर्ट ने अब एचएसवीपी के पक्ष में फैसला दिया है। इसके बाद एचएसवीपी ने इस पॉकेट को विकसित करने की तैयारी शुरू कर दी हैं। जमीन के इस हिस्से में एचएसवीपी साल 2022 में ही प्लॉट अलॉट कर चुका था, लेकिन कोर्ट केस के साथ यहां विकास कार्य नहीं हो पा रहे थे। इससे जिन्हें यहां प्लॉट अलॉट किए गए हैं वे लोग यहां घर नहीं बना पा रहे थे। एचएसवीपी ने करीब 63 करोड़ के टेंडर लगाए गए हैं। जनवरी में काम शुरू कर दिया जाए। एचएसवीपी के अधीक्षण अभियंता संदीप दहिया ने कहा, प्राधिकरण ने दो महीने में काम पूरा करने का लक्ष्य रखा है।

बैंक अधिकारी से एक करोड़ की ठगी, केस दर्ज

भास्कर न्यूज | फरीदाबाद

साइबर ठगों ने शेयर बाजार में पैसा निवेश का झांसा देकर एक बैंक अधिकारी से करीब एक करोड़ रुपए ठग लिए। आरोपियों ने पीड़ित को पैसा निवेश करने पर कई गुना मुनाफे की बात कही थी। उन्होंने अपने को बड़ी कंपनियों का फाइनेंस एडवाइजर बताया था। साइबर थाना एनआईटी की पुलिस मामला दर्ज कर जांच कर रही है। पुलिस के अनुसार पीड़ित सेक्टर-21 में परिवार के साथ रहते हैं। वह एक बैंक में अधिकारी हैं।

ट्रैक्टर-ट्राली से ऑटो टकराया, चालक की मौत

भास्कर न्यूज | पलवल

नेशनल हाईवे पर मुंडकटी थाने के निकट सड़क किनारे खड़े ट्रैक्टर ट्राली से टकराने से ऑटो चालक की मौत हो गई। पुलिस ने अज्ञात ट्रैक्टर चालक के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। थाना प्रभारी तेजपाल के अनुसार यूपी के कन्नौज जिले के रहने वाले अमित ने बताया कि उनका भाई सतेंद्र गुरुग्राम में ऑटो चलाता था। शनिवार शाम वह कन्नौज से गुरुग्राम ऑटो से जा रहा था। रविवार देर रात ऑटो की टक्कर मुंडकटी थाने के समीप हाईवे किनारे खड़े ट्रैक्टर-ट्राली से हो गई।

कवायद • लगेंगी बड़ी स्क्रीन, 400 करोड़ की लागत से विकास

फरीदाबाद रेलवे स्टेशन पर लगेंगी डिजिटल मशीन, मिलेगी जानकारी

भास्कर न्यूज | फरीदाबाद

शहर में प्रथम श्रेणी स्टेशन के रूप में विकसित हो रहे फरीदाबाद रेलवे स्टेशन पर बड़ी-बड़ी डिजिटल मशीनें लगाई जाएंगी। इससे यात्रियों ट्रेन के आगमन -प्रस्थान, प्लेटफॉर्म आदि की सही जानकारी समय रहते मिल सकेगी। यात्री मिनट-टू-मिनट ट्रेनों की लाइव अपडेट देख सकेंगे। इससे यात्रियों को काफी लाभ होगा। फरीदाबाद को औद्योगिक नगरी के रूप में जाना जाता है। यहां करीब 30 हजार छोटी-बड़ी औद्योगिक इकाइयों में करीब आठ लाख कामगार हैं। इनकी और जिले के लोगों की सुविधा के लिए फरीदाबाद में तीन रेलवे स्टेशन हैं। इनमें से ओल्ड फरीदाबाद सबसे बड़ा स्टेशन है। इसे अमृत भारत योजना के तहत करीब 400 करोड़ की लागत से विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन के रूप में विकसित किया जा रहा है। स्टेशन के दोनों तरफ पांच-पांच मंजिला पार्किंग तैयार की जा रही है। इसमें एयरपोर्ट की तर्ज पर आगमन और प्रस्थान अलग-अलग होगा। स्टेशन के दोनों तरफ मल्टीलेवल कार पार्किंग भी होगी।

पूछताछ केंद्र से मिल जाएगा छुटकारा

यात्रियों को सबसे ज्यादा परेशानी ट्रेनों की लाइव अपडेट की होती है। फरीदाबाद से आगरा, मथुरा, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई सहित देश के विभिन्न राज्यों में ट्रेनें चलती हैं। ऐसे में अनेक यात्रियों को ट्रेनों की लाइव स्थिति जानने के लिए बार-बार पूछताछ केंद्र के चक्कर काटने पड़ते हैं। लाइव स्क्रीन लगने से यात्रियों को ट्रेन के आगमन, प्रस्थान, प्लेटफॉर्म नंबर, विलंब की स्थिति और कोच पोजीशन जैसी जानकारी के लिए मोबाइल एप या पूछताछ केंद्र पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।

चरणबद्ध तरीके से लागू होगी योजना

ऑटोमेटेड पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम (एपीआईएस) को चरणबद्ध तरीके से लागू होने के बाद किसी भी ट्रेन का लाइव स्टेटस उसके निर्धारित आगमन समय से चार घंटे पहले स्क्रीन पर दिखाई देने लगेगा। ट्रेन कहां है, कितनी देर में पहुंचेगी, कितना विलंब है और किस प्लेटफॉर्म पर आएगी ये सभी जानकारियां वास्तविक समय के अनुसार अपडेट होती रहेंगी।

इस तरह काम करेगा यह नया सिस्टम

एपीआईएस को सीधे सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम के सर्वर से जोड़ा जाएगा। सिस्टम में सिम आधारित इंटरनेट तकनीक होगी। जिसके जरिए ट्रेन का वास्तविक समय पर आधारित अपडेट प्लेटफॉर्म स्क्रीन तक पहुंचेगा। इससे खराब नेटवर्क या एप लोडिंग की समस्या से राहत मिलेगी। फिलहाल यह सिस्टम दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर स्टेशन पर है।

नौकरी दिलाने का झांसा देकर ठगे 12 लाख रुपए

भास्कर न्यूज | फरीदाबाद

जालसाजों ने एक व्यक्ति को हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए सेल्स टैक्स आफिसर की नौकरी दिलाने का झांसा देकर करीब 12 लाख रुपए ठग लिया। एनआईटी थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार पीड़ित सुरजीत सिंह कालोनी में रहते हैं। शुभम ने हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में नौकरी के लिए साल 2023 में आवेदन किया था। इसी दौरान ग्रेटर फरीदाबाद निवासी जानकार मनोज दुबे से उनकी मुलाकात हुई। उसने किसी और से मिलवाया।

सूबेदार हितेश की ड्यूटी के दौरान मौत, शहीद को विदाई दी

पलवल | हथीन क्षेत्र के गहलब गांव निवासी सूबेदार हितेश सहरावत की लेह लद्दाख में ड्यूटी के दौरान हृदय गति रुकने से मौत हो गई। शहीद का पार्थिव शरीर रविवार को पैतृक गांव पहुंचा। इसके बाद राजकीय सम्मान के साथ शहीद अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान शहीद सूबेदार हितेश सहरावत अमर रहें और भारत मां के जयघोष से आकाश गूंज उठा। हितेश 15 फरवरी 2001 को सेना में बतौर ड्राइवर भर्ती हुए थे। इस समय वह सूबेदार थे।

हसनपुर में नौ करोड़ की लागत से बनेगा अत्याधुनिक एसटीपी

तीन एमएलडी वाला एसटीपी फिलहाल छोटा पड़ रहा

भास्कर न्यूज | पलवल

हसनपुर में नौ करोड़ की लागत से अत्याधुनिक सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) बनाया जाएगा। इसके अलावा पहले से संचालित तीन एमएलडी क्षमता वाले पुराने एसटीपी को भी अपग्रेड किया जा रहा है। इसकी तैयारी जनस्वास्थ्य विभाग ने शुरू कर दी है। जलभराव की समस्या से निजात दिलाने के लिए करीब दस वर्ष पहले यमुना किनारे सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किया गया था। इसमें शहर का गंदा सीवर का पानी आता है। जिसे साफ करने के बाद यमुना नदी में छोड़ दिया जाता है। कुछ वर्षों में हसनपुर की आबादी में काफी वृद्धि हुई। साथ ही सहनौली गांव भी इस सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट से जोड़ दिया गया। ऐसे में तीन एमएलडी वाला एसटीपी छोटा पड़ रहा है। इससे सीवर का पानी ओवरफ्लो होकर सड़कों पर बहता रहता है।

गीता जयंती : द्रौपदी चीरहरण से श्रीकृष्ण लीला की शुरुआत

भास्कर न्यूज | फरीदाबाद

गीता जयंती महोत्सव रविवार को ऊर्जा, उल्लास और सांस्कृतिक विविधता के रंगों से सराबोर रहा। विभिन्न शिक्षण संस्थानों के कलाकारों ने अपनी प्रतिभा का ऐसा प्रदर्शन किया कि सभागार तालियों से गूंजता रहा। कार्यक्रम की शुरुआत राजकीय कन्या सीनियर सेकेंडरी स्कूल, एनआईटी-5 की छात्राओं द्वारा प्रस्तुत महाभारत के द्रोपदी चीरहरण प्रसंग से हुई। इसके बाद संध्या चौधरी ने रागनी के सुरों की ऐसी मिठास घोली कि दर्शक मंत्रमुग्ध हो उठे। उनकी गायकी की सुरीली लय, अभिव्यक्ति की स्पष्टता और प्रस्तुति की गरिमा ने लोगों का मन मोह लिया। दर्शकों ने पूरा उत्साह दिखाते हुए तालियों के माध्यम से उनका उत्साह बढ़ाया।

दर्जनभर मामलों में लाखों की ठगी करने वाले दो अपराधी गिरफ्तार

नूंह | साइबर क्राइम यूनिट दो शातिर साइबर ठगों को गिरफ्तार कर इनके कब्जे से फर्जी आईडी पर एक्टिव मोबाइल सिम, मोबाइल फोन, एटीएम कार्ड व संदिग्ध लेनदेन का रिकार्ड बरामद किया है। आरोपियों पर लाखों रुपये की ऑनलाइन ठगी के कई मामले दर्ज हैं। पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है। पुलिस की एक टीम ने सिकरावा-पुन्हाना रोड पर दबिश देकर चांदडाका निवासी राशिद उर्फ बिल्ला को गिरफ्तार किया। उसके पास से दो मोबाइल फोन बरामद हुए। इनमें फर्जी आईडी पर एक्टिव सिम कार्ड डले हुए थे। आरोपियों ने मोबाइल पर व्हाट्सएप आईडी पंकज सिंह के नाम से बना रखी थी। जांच में पता चला कि आरोपी के खिलाफ 12 से ज्यादा साइबर ठगी के केस दर्ज हैं और इसने करीब 6 लाख रुपये की ठगी कर रखी है।

डिजिटल अरेस्ट कर बुजुर्ग महिला से 78.89 लाख रुपए वसूले

गुरुग्राम | साइबर क्राइम साउथ एरिया में जालसाजों ने मनी लॉन्ड्रिंग में अरेस्ट वारंट का दे दिखा कर बुजुर्ग महिला से 78,89,981 रुपए ठग लिए। बुजुर्ग महिला को डिजिटल अरेस्ट करके वारदात को अंजाम दिया गया। पीड़ित महिला की शिकायत और पुलिस ने किस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। सेक्टर-67 निवासी तमिता सेठी (70) ने पुलिस को शिकायत दी कि 21 नवंबर को उनके घर पर लगे एयरटेल लैंडलाइन नंबर पर एक कॉल आई। कॉलर ने बताया कि आपके आधार कार्ड का मनी लॉन्ड्रिंग में गलत इस्तेमाल करने पर आपके खिलाफ अरेस्ट वारंट है। थोड़ी ही देर में तमिता सेठी के व्हाट्सएप पर कॉल आई और बताया कि आपके अकाउंट का मनी लॉन्ड्रिंग में गलत इस्तेमाल किया गया है।

शिकंजा • सीबीआई अफसर बनकर डिजिटल अरेस्ट किया, 2.92 करोड़ ठगे

आरोपी वीजा कंसल्टेंट को गुजरात से किया गिरफ्तार, कई ठगी का खुलासा

भास्कर न्यूज | गुरुग्राम

साइबर क्राइम ईस्ट थाना पुलिस ने डिजिटल अरेस्ट कर 2.92 करोड़ रुपए की ठगी के मामले में गुजरात से वीजा कंसल्टेंट को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने अपने भाई के माध्यम से साइबर ठगों को बैंक अकाउंट मुहैया कराए थे। उस अकाउंट का प्रयोग कर 39 लाख रुपए ठगने की वारदात को अंजाम दिया गया था। पुलिस इस मामले में अब तक वीजा कंसल्टेंट व उसके भाई समेत 18 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है।

दरअसल, साइबर क्राइम ईस्ट थाना पुलिस में बीती चार दिसंबर को एक महिला ने शिकायत दर्ज कराई थी। जिसमें कहा गया कि उसके बेटे के पास एक व्हाट्सएप पर ऑडियो कॉल आया। जिसमें बताया गया कि इसके बेटे के आधार कार्ड का हवाला के काम में प्रयोग हुआ है। जब उसने मना किया तो उन्होंने केस दर्ज कराने की बात कही और एक सीबीआई अफसर से वीडियो कॉल करके डिजिटल अरेस्ट करने की बात कही। हवाला केस में शामिल होने का डर दिखाकर उन्होंने अलग-अलग बैंक खातों में कुल 02.92 करोड़ रुपए ट्रांसफर करवा लिए। पुलिस ने केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। मामले में एसीपी साइबर क्राइम प्रियांशु दीवान की अगुवाई में साइबर क्राइम ईस्ट थाना पुलिस ने 17 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद पुलिस ने गुजरात से वीजा कंसल्टेंट को गिरफ्तार कर लिया। जिसकी पहचान गुजरात के तापी निवासी आशीष भाई रमनलाल राणा (36) के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश कर दो दिन के रिमांड पर लिया है और उससे अन्य वारदातों व अन्य साथी आरोपियों के बारे में पूछताछ की जा रही है।

ठगी के बाद राशि को अलग-अलग खाते में किया ट्रांसफर

गुरुग्राम। पुलिस गिरफ्त में आरोपी।

दुबई में वीजा कंसल्टेंट के रूप में काम करता था आरोपी

पूछताछ में पता चला कि वह वर्ष 2021 से दुबई में वीजा कंसल्टेंट के रूप में काम करता है। मई में वह दुबई से भारत आया था। आरोपी ने ठगी गई राशि 2.92 करोड़ रुपए उसके व अन्य साथी आरोपियों द्वारा अलग-अलग बैंक खातों में ट्रांसफर कराए गए थे। इनमें से 39 लाख रुपए अशीष भाई रमनलाल राणा द्वारा उपलब्ध कराए गए बैंक खाते में ट्रांसफर हुए थे। यह बैंक खाता उसके भाई मितेश ने ही उसे उपलब्ध कराया था। इसके बाद आशीष भाई रमनलाल राणा ने वह बैंक खाता साइबर ठगों को उपलब्ध कराया था।

पुलिस ने इस केस में अब तक आरोपी आशीष भाई रमनलाल राणा व इसके भाई मितेश सहित 18 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी आशीष भाई रमनलाल राणा को दो दिन के रिमांड पर अन्य वारदातों व अन्य साथी आरोपियों के बारे में पूछताछ की जा रही है। मामले में संलिप्त अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया जाएगा।
-प्रियांशु दीवान, एसीपी साइबर क्राइम

कांकरौला के नाले में मिली युवक की डेड बॉडी; चोट के निशान मिले, हत्या की आशंका

कपड़ों से नहीं मिला कोई भी पहचान पत्र, सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस

भास्कर न्यूज | गुरुग्राम

खेड़कीदौला थाना क्षेत्र में तेजधार हथियार से गला रेतकर युवक की हत्या करने का मामला सामने आया है। युवक का शव गांव कांकरौला के गंदे नाले में मिला है। जिसकी शिनाख्त नहीं हो सकी है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर हत्या का केस दर्ज कर लिया और जांच शुरू कर दी।

शनिवार की सांय को राहगीरों ने गांव कांकरौला के गंदे नाले में एक शव देखा। जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और एफएसएल व फिंगरप्रिंट विशेषज्ञों की टीम को बुलाकर घटनास्थल का निरीक्षण कराया। मृतक की अभी पहचान नहीं हुई है और उसकी उम्र करीब 35 साल बताई गई है। उसका शव फूलकर पानी के ऊपर आया हुआ था। पुलिस को कोई दस्तावेज या पहचान पत्र नहीं मिला, ताकि शव की पहचान हो सके। पुलिस मृतक युवक की पहचान करने के प्रयास कर रही है। आशंका है कि युवक की हत्या करने के बाद बाद शव को सबूत मिटाने और पहचान छिपाने के इरादे से नाले में फेंका गया था। पुलिस का मानना है कि युवक का शव ज्यादा पुराना नहीं है। शुक्रवार की रात को युवक की हत्या करने के बाद शव को नाले में फेंका गया होगा, जोकि दोपहर बाद फूलकर नाले में पानी के ऊपर आ गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम में रखवाया है। पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर लिया और कार्रवाई शुरू कर दी। इस मामले में जांच अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर लिया है। मृतक युवक की पहचान के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। आसपास के थानों में लोगों की गुमशुदगी की रिपोर्ट खंगाली जा रही हैं। गांव व घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है।

सीआईए ने स्मैक के साथ दो नशा तस्कर किए गिरफ्तार

नूंह। नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ अभियान के तहत नूंह सीआईए टीम को एक बड़ी कामयाबी मिली है। टीम ने 10.37 ग्राम स्मैक के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों की पहचान गांव घासेड़ा निवासी राहुल और मुबारिक उर्फ मुब्बा के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपियों के पास से स्मैक के अलावा एक डिजिटल कांटा भी बरामद किया है, जिसका इस्तेमाल नशीले पदार्थों को तौलने में किया जाता था। पुलिस के अनुसार नूंह सीआईए की एक टीम 29 नवंबर की शाम करीब 6 बजे नूंह–सोहना रोड पर गांव घासेड़ा के पास गश्त पर थे। इसी दौरान सूचना मिली कि दो नशा तस्कर गांव हिरमथला के पास इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप से आगे स्थित एक सुनसान कोठड़ी में स्मैक बेचने की तैयारी में बैठे हैं। सूचना मिलते ही टीम मौके पर दबिश देकर कोठड़ी में छिपे दो युवकों को काबू कर लिया। नियम अनुसार दोनों आरोपियों की तलाशी ली गई। इस दौरान आरोपी राहुल की लोअर की जेब से एक डिजिटल कांटा बरामद हुआ, जबकि आरोपी मुबारिक उर्फ मुब्बा की जेब से पारदर्शी पॉलिथीन में रखी 10.37 ग्राम स्मैक (चिट्टा) मिली।

रोल बॉल एसोसिएशन ने किया खिलाड़ियों को सम्मानित

भास्कर न्यूज | गुरुग्राम

रोल बॉल एसोसिएशन गुरुग्राम ने विभिन्न आयु वर्गों के विजेता खिलाड़ियों का भव्य सम्मान समारोह आयोजित किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में वार्ड–33 की पार्षद सरिका भारद्वाज एवं प्रशांत भारद्वाज उपस्थित रहे। उनके साथ रोल बॉल एसोसिएशन के प्रधान गजराज नाहरवाल ने भी खिलाड़ियों को सम्मानित किया।

सम्मान समारोह में गुरुग्राम के अंडर–9, अंडर–11, अंडर–14 और अंडर–17 आयु वर्ग के खिलाड़ियों को फूल मालाएं पहनाकर सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथियों ने सभी राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। इस मौके पर वार्ड–33 के पार्षद प्रशांत भारद्वाज ने खिलाड़ियों को आश्वासन दिया कि गुरुग्राम के सेक्टर–4 में रोल बॉल का एक समर्पित ग्राउंड शीघ्र ही विकसित कराया जाएगा, जिससे खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण मिल सकेगा। कार्यक्रम में गुरुग्राम के सभी प्रमुख कोच राजेंद्र, हरीशंकर, इरफ़ान, नज़ाकत आदि थे।

बोर्ड परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने वाले को सम्मान

गुरुग्राम | सेक्टर-22 स्थित रोटरी पब्लिक स्कूल में 38वें वार्षिक समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि पूर्व रोटरी इंटरनेशनल डायरेक्टर टीएन सुब्रमण्यन, विशिष्ट अतिथि, डीएलजेएम ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन श्रीपाल जैन, स्कूल प्रबंध समिति के चेयरमैन अनिल जैन समेत अनेक रोटेरियन ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम की शुरुआत वंदे मातरम की धुनों पर बांसुरी वादन और स्कूल बैंड ''बीट ब्रिगेड'' के ढोल और गूंजते बैगपाइप की गड़गड़ाहट के साथ हुई। इस दौरान स्कूल के वार्षिक रिपोर्ट प्रधानाचार्या डायरेक्टर संदीपा राय ने प्रस्तुत की। इस समारोह में बोर्ड कक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन करने वाले स्टूडेंट्स को सम्मानित किया गया। वर्ष 2024-25 स्कूल के टॉपर विशेष शर्मा (नॉन-मेडिकल), राज मिश्रा (मेडिकल), नूपुर बिष्ट (कॉमर्स) और हर्षिता यादव (मानविकी) को सम्मानित किया गया।

आधी रात को पुलिस ने चोरी के 15 मोबाइल किए बरामद

नूंह| पुलिस ने चोरीशुदा मोबाइल फोन की खरीद-फरोख्त करने वाले गिरोह पर कार्रवाई करते हुए चोरी के 15 मोबाइल बरामद किए हैं। इन मोबाइलों की बाजार कीमत डेढ़ लाख रुपये से अधिक आंकी जा रही है। आरोपियों की गिरफ्तारी सुनहेड़ा बॉर्डर से की गई है।

शनिवार-रविवार की रात बिछौर थाना पुलिस की एक टीम एसआई प्रीतम सिंह के नेतृत्व में गश्त पर थी। इसी दौरान सुनहेड़ा बॉर्डर के पास नेहदा गांव जाने वाली सड़क किनारे खेतों में कुछ लोग मोबाइल फोन की डील कर रहे थे। इसकी सूचना जब पुलिस को मिली तो पुलिस ने मौके पर रेड की। पुलिस की गाड़ी देखकर आरोपी भागने लगे। दो युवक एक मोटरसाइकिल पर बैठकर फरार हो गए, जबकि दो उबड़-खाबड़ रास्ते का फायदा उठाकर भाग निकले। पुलिस टीम ने आरोपियों का पीछा करने का प्रयास भी किया लेकिन ये काबू नहीं आ सके। आरोपित मौके पर अपना एक पिट्ठू बैग छोड़ गए। बैग की तलाशी लेने पर उसमें 15 मोबाइल फोन बरामद हुए। फोन अलग-अलग ब्रांड के हैं। पुलिस ने सभी मोबाइल फोन जब्त कर सील कर दिए। पुलिस ने मौके से फरार हुए दो आरोपियों की शिनाख्त कर ली है। पुलिस प्रवक्ता के अनुसार दो नामजद आरोपियों के साथ कुल चार लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।

ट्रक की टक्कर से ऑटो चालक गंभीर, पैर कटा

भास्कर न्यूज | गुरुग्राम

बादशाहपुर थाना एरिया में तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से ऑटो चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे में ऑटो चालक का पैर कट गया और सिर में गंभीर चोट आई हैं। उसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

राजस्थान के झुंझनू निवासी दिलीप सैनी गुरुग्राम में टैक्सी चलाता है। वह स्विफ्ट डिजायर लेकर 28 नवम्बर को एरिया मॉल की तरफ जा रहा था। उसके आगे एक वैगनार कार व पीछे एक सीएनजी ऑटो चल रहा था। इसी दौरान एक तेज रफ्तार कार ने सीएनजी ऑटो में टक्कर मारी। टक्कर इतनी जबरदस्त की ऑटो स्विफ्ट डिजायर से जा टकराया वहीं दिलीप का कार आगे चल रही वैगनार से टकरा गई। हादसे में ऑटो चालक यूपी के एटा निवासी संदीप का पैर कट गया और सिर पर गंभीर चोट आई। जिसे पुलिस को बुलाकर अस्पताल पहुंचाया गया। मामले में पुलिस ने चालक नेपाल मूल के राजन केसी को काबू कर ट्रक को कब्जे में ले लिया। पुलिस ने दिलीप सैनी की शिकायत पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

कॉर्पोरेट्स अधिकारियों ने दिए स्टूडेंट्स को टिप्स, बातचीत की

गुरुग्राम | भोंडसी-दमदमा रोड स्थित जेके बिजनेस स्कूल में इंडस्ट्री–अकादमिक मीट समागम 2025 में कॉर्पोरेट्स अधिकारियों ने स्टूडेंट्स को करियर संबंधित टिप्स दिए। इसमें बैंकिंग, कंसल्टिंग, टेक्नोलॉजी, वित्तीय संस्थान, रेटिंग एजेंसियां, ई-कॉमर्स, मानव संसाधन एवं शिक्षा क्षेत्र से 32 कॉर्पोरेट अधिकारियों ने भाग लिया। इस दौरान संस्थान का प्रतिनिधित्व एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, जेके टेक्नोसॉफ्ट एवं सदस्य सतीश चंद्र गुप्ता, डॉ. प्रो. बीके मोहंती व वरुण तोमर द्वारा किया गया। साथ ही निदेशक डॉ. चारु बंसल ने शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए उद्योग से मिलने वाले इनपुट्स के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने फैकल्टी की भूमिका और परिसर के वातावरण को भी महत्वपूर्ण बताया, जिसका छात्रों के शैक्षणिक विकास पर गहरा असर पड़ता है। इस दौरान कई तरह की क्विज प्रतियोगिता भी आयोजित की गई। इसके अलावा अतिथियों ने छात्रों और फैकल्टी सदस्यों के साथ उत्साहपूर्ण बातचीत का आनंद लिया। विद्यार्थियों को करियर संभावनाओं, डेटा एनालिटिक्स, डिजिटल मार्केटिंग, ब्रांडिंग और उद्योग की स्किल आवश्यकताओं पर महत्वपूर्ण जानकारी मिली।

गुरुग्राम। मीट समागम में उपस्थित कॉर्पोरेट्स प्रतिनिधि।